हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 26 मार्च, 2015 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई ।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

26.03.2015/1100/negi/jt/1

प्रश्न संख्याः 1764.

श्री कुलदीप कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने काफी डिटेल में रिप्लाई दिया है। लेकिन इसमें ऊना जिला का बड़े लाल अक्षरों में लिखा है । ऊना जिला में सैक्स रेशो की कमी जो कि बड़ी सुर्खियों में आई है और ह्युमन राइट्स कमीशन ने भी इसका संज्ञान लिया है।

क्या मंत्री जी बताएंगे कि ऊना जिला में 1000 लड़कों के पीछे 500 या 500 से कम लड़कियों की कितनी पंचायतें हैं? यह जो सैक्स रेशो कम हो रही है इसको रोकने के लिए इन्होंने काफी डिटेल में पग उठाए हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई सरप्राइज़ रेड किये गये ?क्या वहां पर कोई इल्लिगल काम करता हुआ पकड़ा गया? अगर कोई पकड़ा गया है तो उसके खिलाफ आपने कौन सी कार्रवाई की है ?

दूसरा, मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि यहां लाहौल-स्पिति का सैक्स रेशो 1033 है । बॉडर एरियाज़ में सैक्स रेशो कम होने के क्या कारण हैं? क्या उन कारणों के रोकथाम के लिए कोई पग उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह जो चाइल्ड सैक्स रेशो हिमाचल में कम होना हम सब के लिए चिन्ता का विषय है। वर्ष 2001 से पहले हमारा सैक्स रेशो ऑल इण्डिया के सैक्स रेशो से बराबरी पर था या उससे बैटर था। लेकिन 2001 में हमारा सैक्स रेशो काफी कम हुआ है । अब भी 2011 की सैंसिज़ की जो फिगर आई है उसके मुताबिक ऑल इण्डिया सैक्स रेशो 1000 लड़कों के पीछे 919 लड़कियां हैं जबकि हिमाचल प्रदेश का सैक्स रेशो 1000लड़कों के पीछे 909 लड़कियां है। जो 24 पंचायतें आपने कहा, जो कम सैक्स रेशो है चाइल्ड सैक्स रेशो में, उसमें कंट्री के जो 10 स्टेट्स हैं उसमें हमारा हिमाचल प्रदेश भी आ रहा है और जो कंट्री के 100 जिले कम सैक्स रेशो में है उसमें ऊना जिला को भी शामिल किया

26.03.2015/1100/negi/jt/2

गया है। ऊना जिला की जो 24पंचायतें हैं उनमें सैक्स रेशो कम है और उनमें 500 से भी कम हैं। उसके लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं,वो सारा हमने विस्तृत तौर पर इसमें जवाब में दे दिया है। लेकिन...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

26/1105/03.2015.यूके1/

प्रश्न संख्या--1764-जारी---

-

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ---जारी----

इसमें उत्तर में दे दिया है । लेकिन उसमें, जैसे आपने कहा कि इंस्पैक्शन वगैरहा कितने किए हैं? इस वक्त हिमाचल प्रदेश में 260 अल्ट्रासाउंड की मशीनें स्थापित हुई हैं, जिसमें सरकारी मशीनें 86 हैं और प्राईवेट सैक्टर में 174 मशीनें अल्ट्रासाऊंड की चल रही हैं । उसमें जो रिन्यूअल हुई हैं, 1-4- 2014से 31-12- 20114तक की 15 रिन्यूअल हुई हैं । इसी इंस्पैक्शन के दौरान 1-4- 2014से 31-12-2014 तक 721 इंस्पैक्शन किए गए जिसमें 303 प्राईवेट मशीनों की कैंसिलेशन पायी गयी है । इसमें मैं यह भी बताना चाहूंगा कि अल्ट्रासाऊंड की मशीनें PC& PNDT के तहत जो हैं वह सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट रेडियालॉजिस्ट ही ऑपरेट कर सकता है । इन 86 में से हमारी भी 30 या 35 मशीनें ऐसी हैं जो बन्द हैं, उनको नहीं चला सकते क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट की हमारे पास कमी है । अभी वे ट्रेनिंग कर रहे हैं । इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं । अभी हमने कोशिश की है कि वूमेन एंम्पॉवरमैंट के अन्तर्गत , और यह सोशियल ज्यादा है, लोगों को लगता है कि लड़का हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, खुशियां मनाते हैं, लड़की हो जाए तो उदास होते हैं । इसके लिए हमने पिछली बार "बेटी बचाओ" कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर चलाया था । उसके तहत हमने कहा था कि एक बेटी के बाद जो परमानेंट फैमिली प्लानिंग कर लेता है उसको हम 25 हजार रुपए देंगे । यदि दो बेटी पर करते हैं तो उसको 20 हजार रुपए देंगे । अभी मुख्य मंत्री महोदय ने बजट भाषण में 20रुपए को 25 रुपए तथा 25 रुपए को 35 रूपए किया है । लेकिन सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि दोनों, चाहे एक बेटी के बाद फैमिली प्लानिंग करे चाहे दो बेटी के बाद फैमिली प्लानिंग

करे, हम 40 हजार रूपए बेटी के नाम पर फिक्स करा देंगे ताकि जब 22 या 24साल के बाद उसकी शादी हो तो उस राशि से 12से 15 लाख रूपए उसके खाते में जमा हो जाएं । उसके लिए सरकार प्रयत्न कर रही है । मैं सभी माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि कई बार हमे CMO कहते हैं कि जब हम इंस्पैक्शन करने जाते हैं तो चुने हुए प्रतिनिधियों का टेलीफोन आ जाता है कि यह मेरा आदमी है

26/1105/03.2015.यूके2/

इसकी मशीन को कैंसिल न करें । इस बारे में मैं सभी माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह सामाजिक समस्या है । इस समस्या का निपटारा करने के लिए हम सभी लोग जब अपने-अपने क्षेत्रों मे जाते हैं, तो इसका जरूर प्रसार और प्रचार करें ।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने वैसे यहां पर बड़ा विस्तृत जवाब दिया है । लेकिन क्योंकि यह प्रश्न भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है । यहां जो जानकारी उपलब्ध करवाई है उसके अनुसार ऊना जिला नम्बर वन पर 1000 के पीछे 875 और कांगड़ा जिला 1000 के पीछे 876, हमीरपुर जिला 1000 के पीछे 887, सोलन में 899 चौथे नम्बर पर है, बिलासपुर में 900, मंडी जिला में 916 , शिमला जिला 7वें पर, सिरमौर 8वें पर और चम्बा 9वें पर है । तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एक कार्यक्रम पीछे हमारी सरकार के समय में शुरू किया गया था । मदर ट्रैकिंग कार्यक्रम उसमें जैसे आपने यहां पर बताया भी है । क्या वह कार्यक्रम अभी भी चला हुआ है? उसमें मोबाइल के ऊपर ही वहां उन गांव में, जिस पंचायत में मदर ट्रैकिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचना मिलती है ,जैसे ही प्रेगनैंसी का पता लगता है ,उसी समय उसकी रजिस्ट्रेशन BMO कार्यालय के अन्दर हो जाएगी या जो नज़दीक PHC होगी, उसको वहां पर दर्ज किया जायेगा । वह कार्यक्रम जब आप चलाएंगे तो यह जो भिन्नता आपके सामने यहां पर आयी है, सैक्स रेशो में कमी एक तो वह नहीं रहेगी । दूसरे माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यहां पर कहा है कि जांच के लिए आपने जिला स्वास्थ्य अधिकारी और खंड चिकित्सा अधिकारियों को इंस्पैक्शन के लिजए भेजा है और आपने बताया भी है कि इसमें 721 इंस्पैक्शन की गयी जिसमें 303 मशीनों की कैंसिलेशन भी की है ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी ---

26.03.2015/1110/sls-ag-1

प्रश्न संख्या : 1764...जारी

श्री रविन्द्र सिंह... जारी

लेकिन अभी भी जो बड़े इंटीरियर के गांव हैं, वहां जो कलस्टर पड़ते हैं, वहां पर अभी भी ऐसे केसिज हैं। आपके अधिकारी वहां नहीं पहुंच पाते। आपकी ही तरह मैं भी निवेदन करूंगा कि इसके लिए कोई सिफ़ारिश न करे ताकी आने वाले समय में स्थिति सुधरे। मैंने यहां पर जो मदर ट्रैकिंग बारे और जांच कहां-कहां की , कितनी की और उसमें आपने क्या कार्रवाई की है, उसके बारे में पूछा है, मंत्री महोदय यह सारी जानकारी यहां पर उपलब्ध करवाएंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने कहा, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम अभी तक भी चालू है। टेलिफोन के माध्यम से ही उसकी सूचना दे दी जाती है और रजिस्टर किया जाता है। मैंने कहा कि विशेषकर हिमाचल प्रदेश के लिए यह बड़ा गंभीर मसला है। हिमाचल प्रदेश के जो हैल्थ इंडिकेटर्ज़ हैं , जो ऑल इंडिया हैल्थ इंडिकेटर्ज़ हैं, उनमें our State is the best in the country , चाहे डैथ रेट है या इनफैंट मोरटालिटी रेट है, चाहे वर्थ् रेट है, चाहे मदर मोरटालिटी रेट है, चाहे फर्टिलिटी रेट है। लेकिन इस मामले में हम पिछड़ गए हैं। इसलिए मैंने सबसे अनुरोध किया है कि हम इसको मिलकर कर सकते हैं। ऊना जिला को लेकर कल इन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि क्या कारण हैं? इसके कारण यह हैं कि एक तो ऊना जिला के बॉर्डर पर नंगल ,होशियारपुर हैं, वहां अल्टरासाऊंड मशीनें चली हैं। पंजाब में अपने काऊंटरपार्ट और सैक्रेटरी हैल्थ को भी लिखा जा रहा है कि इस ओर विशेष ध्यान देकर उन अल्टरासाऊंड मशीनों की इंस्पैक्शन करें ताकि ऐसा काम न हो। ऊना का एक केस ट्रिब्यून में भी छपा और नेशनल ह्यूमन राईट्स कमीशन ने उसका संज्ञान लिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी और नेशनल ह्यूमन राईट्स कमीशन में भी हमने अंडरटेकिंग दी है। हम चाइल्ड सैक्स रेशो को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे।

उसके लिए पंचायतों में सैंसटाईजेशन कार्यक्रम चलाया गया है। अब हमने 7750 आशा वर्कर भी नियुक्त किए हैं और उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और कई जगह ट्रेनिंग हो चुकी है। हमारे स्वास्थ्य उप-केंद्रों में मेल हैल्थ वर्कर तथा फिमेल हैल्थ वर्करज़ हैं और हर 4-5 पंचायतों के ऊपर प्राइमरी हैल्थ सैंटर है। इसी तरह जितने भी मैडिकल ऑफिसर्ज़ हैं, ब्लॉक मैडिकल ऑफिसर्ज़ हैं, यह सारे अपने तौर पर कार्यरत हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी एन.जी.ओज. हैं ,वह भी यह काम करें। यहां तक कि जो नेशनल इंस्पैक्शन एंड मोनिटरिंग कमेटी है ,उन्होंने भी हमारे दो जिलों का दौरा किया था। जहां तक केस की बात है, ऊना जिला में ही एक केस इस एक्ट के तहत दर्ज़ किया गया और उस केस में जिनका अल्टरासाऊंड था उनको ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रट फर्स्ट क्लास के कोर्ट ने एक साल की सजा और 10000 रुपये जुर्माना भी किया है। हमने प्राईवेट अल्टासाऊंड की रजिस्ट्रेशन की कुछ कैंसलेशन भी की हैं। हमने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को ,जो जिले के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं और रिनियु भी करते हैं, उनको कैंसलेशन के लिए अथोराईज किया गया है। उनको हिदायतें दी गई हैं कि कृपया इंस्पैक्शन करें। सीफ मैडिकल ऑफिसर्ज़ के अलावा जो मैडिकल ऑफिसर हैल्थ हैं ,उनको भी इंस्पैक्शन के लिए एम्पावर्ड किया गया है और जो ब्लॉक मैडिकल ऑफिसर हर ब्लॉक में हैं ,उनको भी इंस्पैक्शन के लिए पावर्ज़ दी गई हैं। अगर कहीं वॉयलेशन होती है तो चीफ मैडिकल आफिसर्ज़ को इन्फौर्म करते हैं और चीफ मैडिकल ऑफिसर्ज़ रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं ,अल्टरासाऊंड को सील कर सकते हैं और कन्फिसकेट भी कर सकते हैं।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो एक बच्ची के बाद या दो बच्चियों के बाद ऑप्रेशन करवाने के लिए कुछ प्रोत्साहन दिए जाते हैं ,उनका ज़िक्र किया है। उन्हें पढ़ाने की बात भी कही है। यह तो एनकरेज करने के लिए पॉजिटिव स्टैप्स हैं।

जारी ..गर्ग जी

प्रश्न सं. ---1764 क्रमागत

प्रो. प्रेम कुमार धूमल-----क्रमागत

यह उन्हें उत्साहित करने के लिए एक पॉजिटिव स्टैप है। लेकिन जिन पंचायतों में लगातार कन्या भ्रूण हत्या हो रही है या उनकी सैक्स रेश्यो कम होती जा रही है क्या सरकार उनको दण्डित करने के लिए कोई कानून बनाने का विचार रखती है और विकास कार्यों के लिए जो धन दिया जाता है उसको इसके साथ जोड़ा जाए? दूसरा, इतना स्टाफ लगा है, मदर ट्रैकिंग सिस्टम में भी ऐसा हो रहा है, आपने कानून का भी जिक्र किया कि आप इसको फौलो कर रहे हैं ,लेकिन सिर्फ एक ही मामला पकड़ा गया। क्या लगता नहीं कि जिनको यह दायित्व दिया गया है और मदर ट्रैकिंग सिस्टम में जो लोग शामिल हैं अगर उनके क्षेत्र में ऐसा मामला पकड़ा जाए, तो उनको भी पनिशमैंट हो? वे अपनी डियुटी करें। तीसरा, आपने सबसे एक अपील की है कि जन-प्रतिनिधि फोन कर देते हैं सी.एम.ओ. को कि इनका कैंन्सल मत करों। तो क्या सरकार ऐसे कदम उठाएगी कि जो ऐसे जन-प्रतिनिधि हैं उनको भी ऐक्सपोज़ करेगी ताकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो? जो ऐसे गैर-कानूनी काम के लिए फोन करते हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। इन्होंने कहा है कि हम पी.सी. एण्ड.पी.एन.डी.टी. ऐक्ट के तहत जो कार्रवाई कर रहे हैं ,उसमें कई स्थानों पर हमने अल्ट्रासॉउन्ड की मशीनें कॉनफिसकेट भी की हैं ,कई जगह सील भी की हैं और उनके पंजीकरण भी कैंसल किए हैं। लेकिन आपने ठीक कहा कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि बुधवार को एक वर्क शॉप पीटर हॉफ में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगाई जा रही है। आप सभी लोग उसमें शाम को आमंत्रित हैं। उसमें हम इस बारे में पूरी प्रिजैन्टेशन देंगे कि पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. ऐक्ट के तहत क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सभी चुने हुए प्रतिनिधि क्या-क्या कदम उठा सकते हैं। इसके बारे में मैं आज ही सबसे अपील करूंगा। वैसे व्यक्तिगत तौर पर भी हमने यह फैसला किया है। अभी 8 तारीख को अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस था जो ऊना

जिले में ही मनाया गया और जो स्टेट ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई जिसका मैं चेयरमैन हूं। उसमें हमने एक फैसला किया कि जिन पंचायतों में चाइल्ड सैक्स रेश्यो सबसे अच्छा है और ऐसी हमने 50 पंचायतें चुनीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि

26/03/2015/1115/RG/AG/2

लाहौल-स्पिति में सैक्स रेश्यो सबसे अच्छा है क्योंकि वहां 1000लड़कों के पीछे 1033लड़कियां हैं। सबसे टॉप पर लाहौल-स्पिति रहा है और सारे देश में भी वह टॉपर है। इसलिए मैं लाहौल-स्पिति के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। जैसा मैं पहले कह रहा था कि अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस पर 50 पंचायतों को ईनाम देंगे और इस बारे में ऊना में राज्य स्तर पर काफी बड़ा कार्यक्रम हुआ। जो पहले नंबर पर पंचायत थी उसको 50,000/-रुपये नकद ईनाम दिया गया ,दूसरे नंबर पर आने वाली पंचायत को 40,000/-रुपये, तीसरे नंबर पर आने वाली पंचायत को 30,000/-रुपये ,चौथे नंबर पर आने वाली पंचायत को 25,000/-रुपये और पांचवे स्थान पर आने वाली पंचायतों को 20,000/-रुपये दिए गए। बाकी सभी पंचायतों को दस-दस हजार रुपये के चैक हमने बांटे।

अध्यक्ष महोदय, यह बात माननीय विपक्ष के नेता ने ठीक कही कि इनको डिसइन्सैन्टिव क्या दिया जाए। तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कांगड़ा की एक जनसभा में कहा था और इस बात को ध्यान में रखते हुए जिन पंचायतों में सैक्स रेश्यो कम होगा उनको डिसइन्सैन्टिव किया जाएगा और उनके विकास कार्यों के काम के लिए कम धन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिन पंचायतों में सबसे अच्छा सैक्स रेश्यो है उनको ज्यादा विकास के लिए फण्ड्ज दिए जाएंगे। यह एक अच्छा सुझाव है। Noted for action.

श्री कुलदीप कूमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तृत उत्तर दिया है और अच्छे सैक्स रेश्यो वाली पंचायतों को इन्सैन्टिव्स और अवाड्र्ज भी दिए हैं , लेकिन जो ऊना जिले की 24 पंचायतों की डिटेल इसमें दी गई है जिनका सैक्स रेशो 500 या उससे नीचे है इनमें कई पंचायतों की बहुत अलार्मिंग पोजीशन है। जैसे एक पंचायत की 111 है और एक पंचायत की 167 है। जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि कई सालों से इनकी सैक्स रेश्यो कम होती जा रही है। क्या इस बात के

लिए वहां कभी अध्ययन किया गया जिन कारणों से वहां सैक्सा रेश्यो इतना अलार्मिंग है और इसको रोकने के लिए वहां क्या पग उठा गए हैं?----जारी

एम.एस. द्वारा प्रश्न जारी

26/03/2015/1120/MS/JT/1

प्रश्न संख्याः 1764 क्रमागत----श्री कुलदीप कुमार जारी-------

इन पंचायतों में इसको रोकने के लिए क्या वहां कोई स्टडी की गई है कि किन कारणों से ये सैक्स रेशो अलार्मिंग है? इस हेतु क्या पग उठाए गए हैं? दूसरे, मुझे यह भी जानकारी मिली है कि बॉर्डर एरिया में कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, इन्होंने तो कहा कि जो रजिस्टर्ड क्लीनिक हैं, PC&PNDT Act के तहत उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई है और इतने सालों में केवल एक की रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए कोर्ट में गए थे तो उसको सजा हुई है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि कितने सरप्राइज रेड किए गए और मेरी जानकारी के मुताबिक बॉर्डर एरिया में कई संस्थाएं ऐसी हैं जो इस तरह के कैम्प लगाती हैं और बाहर से नर्सिज मंगवाकर ऐसे इल्लीगल काम करवाती हैं। इस तरह के काम रोकने के लिए सरकार क्या पग उठा रही है?

Health & Family Welfare Minister: Speaker, Sir, I have already mentioned that child sex ratio at the panchayat level is not a reliable indicator. इसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो यह है कि बच्चे के जन्म के समय ही रजिस्ट्रेशन हो जाए। जैसे मैंने ऊना का जो स्टडी किया। मैंने वहां डी0सी0, सी0एम0ओ0 और दूसरे अधिकारियों से बात की। ऊना एक छोटा सा जिला है। 8-10 किलोमीटर दूर के पंचायतों के लोग जिनकी डिलीवरी होनी होती है, वे ऊना रिजनल अस्पताल में डिलीवरी करवाने आते हैं। वहां उनकी रजिस्ट्रेशन की जाती है। एक तो एट बर्थ सैक्स रेशो है और एक 0-6(0 TO 6) है। जो कंट्री में देखते हैं, वह 0-6 है। तो इस जीरो साल से छः साल तक में ऊना जिला की 24 पंचायतों में भी सैक्स रेशो बैटर है। ऐसा नहीं है कि 500 से कम है, जैसे आपने कहा कि 133है। वह तो एक साल का देखते हैं। जैसे एक साल में एक पंचायत में 12 बच्चे पैदा हुए और उनमें 4 लड़कियां और 8 लड़के हुए, उसकी सैक्स रेशो निकाल देते हैं। That is not a reliable and

dependable method to find out the indicators. इसलिए जो 0-6 है वह कंट्री के अंदर देखा जाता है और उसके मुताबिक ही ये इंडीकेटर निर्धारित किए जाते हैं। बाकी मैंने बता दिया है कि हमने कितनी इन्सपैक्शन्ज कीं ,कितनी कैंसलेशन की है। यहां तक कि जो नेशनल इन्सपैक्शन मॉनिटरिंग कमेटी है, वह भी हिमाचल के दो-तीन जिलों में गई। उन्होंने भी कैंसलेशन को रिकॉमैण्ड किया और सी0एम0ओ0

26/03/2015/1120/MS/JT/2

उसी समय कदम उठा रहे हैं। इस तरह से प्रदेश सरकार इस दिशा में पूरी तरह से गंभीर है और इसीलिए मैंने आप सभी लोगों से अनुरोध किया है कि यह एक सामाजिक इश्यू है और इस इश्यू को हम सब मिलकर टैकल करे और हमारी कोशिश होगी कि हिमाचल का चाइल्ड सैक्स रेशो कंट्री से ऊपर जाए।

डॉ0 राजीव बिंदलः अध्यक्ष जी, यह सही है कि यह सामाजिक समस्या है और विभाग इसके लिए प्रयास कर रहा है। परन्तु जो मदर ट्रैकिंग की बात है, मैं जानना चाहता हूं कि कितनी प्रतिशत प्रैग्नैंसी हमारी रजिस्टर्ड हो रही हैं? अध्यक्ष जी, वह जो 100 परसेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रैग्नैंसी हैं, ये ही और उसकी ट्रैकिंग, यही इसका एकमात्र सोल्यूशन है।15 दिन के अंदर जो प्रैग्नैंसी हुई, 15 दिन के अंदर हमारी फीमेल हैल्थ वर्कर ने मोबाइल द्वारा क्या उसकी रजिस्ट्रेशन करवा दी। डायरैक्टोरेट ने उसको Up till बर्थ, फोलो किया है। कितने परसेंट रजिस्टर्ड हुई और उसमें से कितने परसेंट डिलीवरी के समय तक फोलो हुई, एक तो हम यह जानकारी चाहते हैं। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो उसको क्या मंत्री जी इम्प्लीमैंट करवाएंगे, इसको और बेहतर करवाएंगे? दूसरे, यह बात सही है कि यह इंटर स्टेट प्रॉब्लम है। तो कितनी कॉन्फ्रेंस हमने पिछले सवा दो सालों के अंदर इंटर स्टेट कॉन्फ्रेंसिज हिमाचल, पंजाब, हरियाणा या चण्डीगढ़ में की? कितनी मीटिंग्स हुई, कितनी मॉनिटरिंग हुई और उसका क्या परिणाम हुआ? क्योंकि जब प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार थी, हमने पड़ोसी पांचों राज्यों को बुलाकर कॉन्फ्रेंसिज शुरू की थी और हर राज्य के अंदर कॉन्फ्रेंसिज हुई। तीसरे ,'बेटी है अनमोल योजना' सामाजिक जागरूकता के लिए एक बहुत बड़ी योजना शुरू की थी और वह बेटी है अनमोल योजना, वह आपने लिखा है कि 11वें प्वांइट के ऊपर चल रहे हैं। परन्तु क्या वजह है कि वह अब स्कूलों तक ,

जारी श्री जे0के0 द्वारा----------

26.3.2015/1125/जेटी/जेके/1

प्रश्न संख्याः 1764---जारी-----

डॉ0 राजीव बिन्दलः----जारी----
परन्तु क्या वज़ह है अब स्कूलों तक नीचे तक इतने प्रभावी तरीके से वह योजना क्यों नहीं चल रही है जिस तरीके के साथ उसको चलाया गया था? यह तीन प्रश्न मैं, माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। इसके पीछे एक ही भाव है कि यदि हम इसको सक्रिय करेंगे तो इसका हमें लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मोबाईल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने के बारे में कहा। हिमाचल प्रदेश में जो हमने सर्वे करवाया है 98प्रतिशत रजिस्ट्रेशन इसके माध्यम से हो रही है। इसके अलावा अब हर तीन गांवों में एक आशा वर्कर भी लगा दी है। हर पंचायत में एक स्वास्थ्य संस्था भी है। उनमें मेल हैल्थ वर्कर भी है और फीमेल हैल्थ वर्कर भी है, लेकिन कई जगह फीमेल हैल्थ वर्कर ही है। इसके अलावा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता है वे भी इस काम में पूरी तरह से शामिल है। वे भी गांवों में जा करके पता करती हैं कि कहां पर प्रैगनेंसी वाली महिला है। इन्स्टिच्युशनल डिलिवरी और रजिस्ट्रेशन को रिलाएबल बनाने के लिए उसमें भी हमारी काफी अच्छी प्रगति हुई है और काफी अच्छी मात्रा में इन्स्टिच्युशनल डिलिवरी हुई है। जहां तक आप कह रहे हैं कि स्टेटों के साथ भी कांफ्रेंसिज करने की जरूरत है। इस बारे में हम निश्चित तौर पर जागरूक है। मैंने पंजाब सरकार के हैल्थ मिनिस्टर से व्यक्तिगत तौर पर भी बात की है। हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) ने भी उनको लिखा है। हिमाचल बॉर्डर के जो शहर है उन शहरों में जो अल्ट्रासाऊंड चल रहे हैं उनकी फ्रीक्वैंट और रैगुलर इन्सपैक्शन की जा रही है। मैंने कहा है कि यह एक सामाजिक समस्या है। अब कोई किसी और काम के लिए जाता है और प्राईवेट हैल्थ क्लिनिक में अल्ट्रासाऊंड कर लेता है। वैसे तो इसके लिए परफॉर्मा है और उसको भरना पड़ता है। लेकिन जो प्राईवेट अल्ट्रासाऊंड चल रहे हैं वे परफॉर्मा नहीं भरते हैं और सीधे ही बता देते हैं कि आपके पेट में लड़का है या

26.3.2015/1125/जेटी/जेके/2

लड़की। इस समस्या से निपटने के लिए एक जागृति अभियान के तौर पर हमें इसे समाज के अन्दर चलाना होगा और लोगों में एक भावना पैदा करनी है कि लड़की और लड़के में कोई भेद नहीं है। लड़कियां ज्यादा सेवा माता-पिता की बुढ़ापे के वक्त करती है।

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष महोदय, गर्भपात की गोलियां हर काऊंटर के ऊपर खुलेआम बिक रही है उनको रोकने के लिए माननीय मंत्री जी क्या उपाय कर रहे हैं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अभी 14 अक्तूबर को चण्डीगढ़ में इन्टर स्टेट कांफ्रेंस हुई है। यह मैं आपको सूचना देना चाहता हूं । जहां तक आपने गर्भपात की गोलियों की बात की है। हमारी जो ड्रग एजैंसिज़ हैं उनको हिदायतें दी है कि फ्रीक्वैंट चैक दवाइयों की दुकानों में करें। यदि कोई इनको खुलेआम बेचते हुए पाया गया तो उनके खिलाफ चालान भी कोर्ट में पेश किया जाए।

प्रश्न समाप्त।

26.3.2015/1125/जेटी/जेके/3

प्रश्न संख्या 1765

श्री गोविन्द राम शर्माः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सूचना सभा पटल पर रखी है उसमें टैण्डर 13.5.2013 को कॉल किया था और 14.6.2013 को खोला गया। दो साल का समय बीत चुका है और अभी तक एक भी कार्य नहीं हुआ है। यह कार्य कब तक शुरू होगा? भाग-ख में लिखा है कि बजट की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा। टैण्डर 2013 में लग गया और टैण्डर खोल दिया।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

26.03.2015/1130/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 1765 क्रमागत

श्री गोविन्द राम शर्मा क्रमागतः
दो सालों में उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और इससे पहले भी एक दफ़ा जो चार-पांच पंचायतें हैं पलानिया, जलाना, दधोगी, कोटली और कुछ एरिया दानूघाट का, इसमें शालाघाट में काफी बड़ा आंदोलन भी हुआ था। बहुत सारे केसिज़ भी बने थे। ट्रैफिक को रोका गया था। मैंने बार-बार मंत्री जी से निवेदन किया और विभाग के अधिकारियों से भी निवेदन किया लेकिन आज तक यह काम पूरा नहीं हुआ। फिर बोलते हैं कि बजट की उपलब्धता अगर होगी तो काम होगा। यह छोटा-सा काम है जिसके लिए 29-30 लाख का टैंडर लगा। मैं माननीय मंत्री जी यह जानना चाहता हूं कि कब तक यह कार्य शुरू और पूरा होगा?

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं शालाघाट-कोटली वाटर सप्लाई स्कीम की एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल और एक्सपेंडीचर सैंक्शन के बारे में बात करना चाहती हूं। The AA&ES has been accorded by the Chief Engineer, Shimla Zone vide his office number dated 31st March, 2008 for Rs. 37.84 lacs. The technical approval has also been accorded and most of the work is completed. For balance work tender was called for by the Executive Engineer, IPH Division, Arki on 13th May, 2013 and opened on 14th June, 2013. Due to some technical observations this tender could not be processed. Now the validity period of this tender has expired. Therefore, fresh tenders are being called for by the Executive Engineer, IPH Division, Arki. Work will be completed by December, 2015. I can assure you this much. You understand now. It is very simple. I have told you whatever is right thing. I think this will be the best way. We are doing the best for you. Thank you.

अध्यक्षः मंत्री जी ने कहा है कि टैंडर दोबारा लगेंगे।

प्रश्न समाप्त

26.03.2015/1130/SS-AG/2

प्रश्न संख्याः 1766

श्री बिक्रम सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, तहसील जसवां में कुल पद 36 हैं और उन 36 में से 17 पद खाली हैं। तहसील रक्कड़ में कुल 34 पद हैं और उसमें से 15 पद खाली हैं। रक्कड़ तहसील में न तहसीलदार है और न ही नायब-तहसीलदार है। उसके बाद रक्कड़ में वरिष्ठ सहायक की पोस्ट 18.8.2007से खाली है। लिपिक 2003 से खाली है। आपने चार पद बताए। एक 2003 से खाली है। एक 2005 से खाली है और एक 2007 से खाली है। एक को तो चलो एक-दो साल हुए हैं। तामील कुनिन्दा, ये आपने एक जगह तीन सैंक्शन्ड पोस्ट बताई हैं। रक्कड़ मे इसकी दो पोस्टें सैंक्शन बताई हैं। जो आपने रिक्त पदों की संख्या बताई है वहां तीन-तीन कर दी हैं। सैंक्शन पोस्टें दो हैं और आप खाली पोस्टें तीन बता रहे हैं। ज़रा यह भी बताएं कि यह गड़बड़ कहां पर है? और यह भी पोस्ट 2002 व 2004 से खाली हैं। इतने लम्बे समय से ये पोस्टें खाली हैं और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि जनता को घरद्वार पर सुविधा देने के लिए तहसीलें व सब-तहसीलें खोल रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि ये जो 2002, 2004, 2007 से पोस्टें खाली हैं क्या इन्हें एक महीने के अंदर भर दिया जायेगा? जो पटवारियों की पोस्टें हैं एक जगह 8 खाली हैं और एक जगह 6 खाली हैं क्या इन्हें भी जल्दी भरने का प्रावधान किया जायेगा?

जारी श्रीमती के0एस0

/1135/26.03.2015केएस/एजी/1

प्रश्न संख्याः 1766 जारी—

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, तहसील जसवां में तो तहसीलदार भी है और नायब तहसीलदार भी है। जहां तक तहसील रक्कड़ की बात हैं, उसके बारे में बता देना चाहता हूं कि ये पोस्टें अभी खाली हुई है। वहां तहसीलदार का पद 26.02.2015 को सरकार द्वारा सेवा विस्तार वापिस लेने के कारण रिक्त हुआ है क्योंकि उस तहसीलदार को चार्जशीट कर दिया गया था और गलती से उसको एक साल की एक्सटैंशन दे दी गई थी। जब यह नोटिस में आया कि वह तो ऑलरेडी चार्जशीट है और चार्जशीट में एक्सटैंशन नहीं देनी है तो उसको 26.02.2015 को रिटायर कर दिया। इसी तरह से जो आपका नायब तहसीलदार था

वह 31.01. 2015को रिटायर हुआ और इस वजह से वह पोस्ट वहां पर खाली है। अभी हम डी.पी.सी. कर रहे हैं और कुछ हम डायरैक्ट पब्लिक सर्विस कमिशन को भी तहसीलदार और नायब तहसीलदार के केसिज़ दे रहे हैं और मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र हम इन पोस्टों को भरने का प्रयास करेंगें।

अध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिगत रूप में जानता हूं कि रेवन्यू मैटर्ज़ में तहसीलदार और नायब तहसीलदार में से कम से कम एक होना तो बहुत ही जरूरी है। जहां तक क्लर्कों के पद खाली है, माननीय सदस्य ने वर्ष 2003 से ले कर 20 07 की बात की लेकिन उसके बाद भी पांच साल तक ये पद खाली ही रहे। 2008 से ले कर 2012 तक भी ये पद खाली ही रहे। हम उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं और जो फंक्शनल पोस्टें हैं, जो बहुत

/1135/26.03.2015केएस/एजी/2

जरूरी है, जिनके बिना तहसील में काम नहीं चल सकता, उनको भरने का प्रयास करेंगें।

प्रश्न समाप्त

/1135/26.03.2015केएस/एजी/ 3

प्रश्न संख्या 1767

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो सूचना सभा पटल पर रखी है, उसमें कहा है कि वन रक्षकों का कैडर वृत स्तर का होता है। सर्कलवाईज़ पोजीशन माननीय मंत्री जी ने दी है और 4 33पद पूरे प्रदेश में खाली है और इन्होंने कहा कि इनको इसी वर्ष भरने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि अभी इनको भरने का प्रोसैस चला भी है, एप्लीकेशन्ज़ मांगी हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सभी 433पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है या कम है ? अगर कम है तो उसके बारे में सर्कल वाईज़ बताएं। दूसरा, मंत्री जी ने कहा है कि

बिलासपुर सर्कल में 18 पोस्टें खाली हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी एक वाईल्ड लाइफ रेंज़ श्री नैनादेवी जी थी। वह डीनोटिफाई हुई और वह रेंज टैरिटोरियल में कन्वर्ट हो गई और सर्कल बिलासपुर के अंतर्गत आ गई। उस वाईल्ड लाइफ रेंज में 11 पद वन रक्षकों के थे। वे सारे पद वहां से हटा दिए गए जबकि वाईल्ड लाइफ सेंक्चुअरी एरिया टैरिटोरियल सर्कल बिलासपुर में मर्ज हो गया । जब एरिया मर्ज हो गया तो गार्ड की पोस्टें भी उसी टैरिटोरियल सर्कल में आनी चाहिए थी, परन्तु ये वहां से बदलकर कहां मंत्री जी ले गए, ये तो मंत्री जी बताएं परन्तु इसके कारण नुकसान हुआ है। इन्होंने कहा कि सर्कल कैडर है। अब बिलासपुर सर्कल को जो 29 पोस्टें मिल सकती थी उसकी बजाय 18 पोस्टें हैं इसलिए क्या मंत्री जी जो ये 11 पोस्टें कहीं आगे-पीछे ले गए हैं, उनको बिलासपुर सर्कल को देने का आश्वासन देंगें ?

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया संक्षेप में सप्लीमेंटरी करें।

/1135/26.03.2015केएस/एजी/4

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने खुद कहा कि यह वृत स्तर का कैडर है और इनको भरने की जो प्रक्रिया चली है उसमें इन्होंने आवेदन मांगें हैं और कहा है कि कोई भी आवेदक कहीं भी आवेदन कर सकता है। बिलासपुर सर्कल का चम्बा में कर सकता है और चम्बा वाला बिलासपुर में, शिमला में, कहीं भी कर सकता है। यह तो वही बात आ गई जो कंडक्टरों की भर्तियों वाली है फिर स्टेट कैडर ही बना देते, सर्कल कैडर क्यों बनाया गया? जब सर्कल कैडर है तो क्या मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करेंगें कि उसी सर्कल के जो परमानैंट रैज़िडैंट्स हैं, वे ही उस सर्कल में अप्लाई करें ताकि उनको बैनिफिट मिले। दूसरे सर्कलों से जो एप्लीकेशन्ज़ मांगी गई है, क्या उसको रोका जाएगा?

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि विधायक महोदय ने फरमाया कि क्या ये जो 433 पोस्टें सर्कल वाईज़ सारे प्रदेश में खाली पड़ी हैं, ये इसी साल भरी जाएंगी?

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

26.3.2015/1140/jt/av/1

प्रश्न संख्या : 1767 -------जारी

वन मंत्री जारी----------
ये इसी साल भरी जायेंगी। सारी 433 खाली पोस्टें माह अगस्त-सितम्बर तक भर दी जायेगी। जहां तक सर्कल की बात की गई है कि एक सर्कल से दूसरे सर्कल में अप्लाई कर रहे हैं तो यह रूल में प्रावधान है और वे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई रोक नहीं सकता। उनकी सलैक्शन उसी के मुताबिक होगी। उनके तीन इन्टरव्यू होंगे। उसमें हाई जम्प, लाँग जम्प, दौड़, उसके बाद लिखित परीक्षा और फिर वायवा होगा।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो 11 पोस्टें ले जाने के बारे में पूछा उसके संदर्भ में तो मंत्री जी ने उत्तर ही नहीं दिया। अगर रूल ऐसा है तो मैंने रूल में अमैंडमैंट की बात की है। जब यह सर्कल काडर है तो क्या रूल को अमैंड करके यह सुनिश्चित किया जायेगा कि हर ऐपलिकांट अपने सर्कल में ही अप्लाई करें। जब इसको सर्कल काडर किया गया है तो इसका सर्कल काडर को ही लाभ मिले। इसके अतिरिक्त जो नैनादेवी वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी एरिया डीनोटिफाई हुआ उसकी 11 पोस्टें कहां गई? जब एरिया टैरिटोरियल सर्कल बिलासपुर में मर्ज हो गया है तो वे 11 पोस्टें वहां मर्ज क्यों नहीं हुई?

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वाइल्ड लाइफ और टैरिटोरियल की पोस्ट्स का युक्तिकरण कर रहे हैं। जब वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी एरिया टैरिटोरियल रेंज से बाहर निकाले तो उसका फिर युक्तिकरण होना था ,उस वजह से कर रहे हैं। जितनी पोस्टें वहां की थीं वे पूरी मिलेंगी। There is no problem. वे कम नहीं की जायेगी। ऐपलिकेशन सर्कल लैवल पर दी जा सकती है परंतु कनसिडर एक ही स्थान पर होगी। एक ऐपलिकांट दो जगह अप्लाई नहीं कर सकता। एक केंडिडेट एक ही जगह अप्लाई करेगा और वह प्रदेश में कहीं भी अप्लाई कर सकता है।

26.3.2015/1140/jt/av/2

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने स्वयं कहा कि वन रक्षक के बहुत पद रिक्त पड़े हैं। इस बात के लिए तो मैं आपका धन्यवाद करुंगा कि आप इनको इसी वर्ष भरने जा रहे हैं। वन रक्षक वन में न हो तो स्वाभाविक है कि वहां अवैध लकड़ी कटेगी। एक प्रश्न लगा है, वह आज आयेगा नहीं। उसमें आपने कहा है कि इन ढाई वर्षों में 18 करोड़ रुपये की मार्किट वैल्यू की लकड़ी कटी है। ये तो वे केसिज हैं जो आपके ध्यान में आए हैं। इसके अतिरिक्त न जाने कितनी कटी। इसके अलावा प्राइवेट लैण्ड की संख्या भी आपने दी नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से जो संख्या आपने दी है और जो वैल्यू आपने बताई है उससे ज्यादा पेड़ कटे हैं। आपके बी.ओज. के पद भी खाली पड़े हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या फॉरैस्ट गार्ड के इन्टरव्यू से पहले जितने पद आपके बी.ओज .के खाली हैं क्योंकि अभी पदोन्नति भी होनी है। अगर आपने ये पद भर भी दिए तो रिक्तियां फिर भी रहने वाली है। आपने जिनको ऐक्सटैंशन दी है वह भी अब 31 मार्च को समाप्त होने वाली है तथा दूसरी रिटायरमैंट्स भी होंगी। क्या आप इन सभी पोस्टों को एक मुश्त भरेंगे ताकि हर बीट में गार्ड हो सके। दूसरा, जैसे अभी माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि यह सर्कल काडर पोस्ट है और व्यक्ति कहीं भी अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने से कोई नहीं रोक सकता। मगर राजस्व में भी, मंत्री महोदय यहां बैठे हैं। पटवारी की पोस्ट डिस्ट्रिक्ट काडर की है इसलिए वहां बाहर के लोगों को कनसिडर नहीं किया जा सकता। अप्लाई करने से आप नहीं रोक सकते। मगर वह वहां का निवासी होना चाहिए, उसी को ही सर्कल काडर पोस्ट कहते हैं। इस बात को रोकने के लिए क्या आप एक बात सुनिश्चित करेंगे कि सारे प्रदेश में सभी सर्कलों में एक ही दिन में इंटरव्यू हो ताकि कोई लोग ऐसा न करें कि एक दिन एक जगह इंटरव्यू दिया और चौथे दिन दूसरी जगह पहुंच गये।

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो फरमाया, वह इनकी चिन्ता है। ये इंटरव्यू एक ही दिन में सारे प्रदेश में होंगे और सारी-की-सारी 433 खाली पड़ी पोस्टें एक साथ भरी जायेंगी। खाली कोई भी नहीं रहेंगी। इसके अतिरिक्त आपने पूछा है कि बी.ओज. प्रमोट होने हैं तो उनसे जो रिक्तियां होंगी वह कंटिन्यू प्रोसैस है -----

श्री बी.जे.नेगी द्वारा जारी

26.03.2015/1145/negi/jt/1

प्रश्न संख्या ..1767जारी..

माननीय वन मंत्री .. जारी..

कि बी.ओ. प्रोमोट होने हैं और उससे वैकेन्सी होगी, मैं बताना चाहूंगा कि भर्तियों का एक कॉन्टीन्युअस प्रोसैस है। यह नहीं कि उसको बन्द कर दिया जाएगा। । जैसे वर्ष 2012 में 154 पोस्टें खाली थी और वे भरी नहीं गई। फिर वर्ष 2013 में 154 पोस्टें जो खाली थीं और रिटायरमैन्ट के बाद वैकेन्सी पोजिशन 309 हो गई । हमने आते ही 205 पोस्टें भर दी। उसके बाद फिर 175 पोस्टें खाली हुई। अभी इस समय प्रदेश में फोरेस्ट गार्डो की टोटल 433 पोस्टें खाली है और ये भर दी जाएगी।

जहां तक भाई रणधीर शर्मा जी वाईल्ड लाइफ सैन्चुरी की बात कर रहे हैं, वाईल्ड लाइफ में हम 46 पोस्टें दे रहे हैं। यह हमने इसमें लिखा है कि हम 46 पोस्टें देंगे । उसके मुताबिक जो आपके रेंज में पोस्टें खाली होंगी वे दे दी जाएगी। टेरिटोरियल में पोस्टें खाली होंगी तो टेरिटोरियल में दी जाएगी और अगर वाईल्ड लाइफ में पोस्टें खोली होंगी तो वाईल्ड लाइफ में दे दी जाएगी।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने स्वयं कहा कि पिछले साल आपने 205 पोस्टें भरीं और एक वर्ष में फिर इतनी वैकेन्सी हो गई। जहां तक मेरी जानकारी है जितनी आप भरने जा रहे हैं इतनी रिक्तियां और हो जाएंगी जब आप गार्ड को बी.ओ. बनाएंगे। चिन्ता यह है कि फिर एक वर्ष तक जंगल खाली रहेंगे। अभी तो 18 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ अगले साल यह नुकसान 36 करोड़ पहुंच जाएगा। इसलिए वहां गार्ड होना चाहिए । क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि जैसे ही पदोन्नति के बाद ये रिक्तियां होंगी, वित्त विभाग से पद स्वीकृत करवा करके जो रिक्तियां होंगी उनको इसी वर्ष में भरेंगे या नहीं भरेंगे?

26.03.2015/1145/negi/jt/2

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है , this is a continuous process. जब पोस्ट खाली नही है तो फिर एकदम कहां से भरी जाएगी। जब कोई पोस्ट खाली होंगी तभी भरेंगे।

जैसे ही पोस्ट खाली होगी उसके बाद भरेंगे । लेकिन इसके साथ इसका कोई कंसर्न नही है। हम पहले इन पदों को भरेंगे फिर उनको ट्रेनिंग देंगे । जैसे पहले वाले 205 को हमने ट्रेनिंग दी है और वे अब फील्ड में आ गये हैं। इनको भी हम पहले ट्रेनिंग देंगे और ये फिर उसके बाद फील्ड में आ जाएंगे। उसके मुताबिक अगला प्रोसैस जारी कर दिया जाएगा।

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से एक बात पूछी है कि वाईल्ड लाइफ रेंज डिनोटिफाई हो गई और वह एरिया टेरिटोरियल में आ गया है और उसमें गार्डज़ की 11 पोस्टें थी । वह एरिया तो कहीं नही गया, एरिया तो वहीं है लेकिन वो 11 पोस्टें ले गए। फिर वहां गार्ड कहां से आएंगे? ये 11 पोस्टें उठा करके चम्बा ले गए या भरमौर ले गये इसका मुझे पता नही । परन्तु इस तरह से बिलासपुर के साथ अन्याय हुआ और वहां जो 11 पोस्टें कम हुई है उसका क्या होगा? यह रेशनेलाइजेशन की बात कर रहे हैं, रेशनेलाइज़ेशन तो यह कर चुके हैं और उसमें इन्होंने चम्बा की पोस्टें बढ़ा ली परन्तु हमारी पोस्टें समाप्त कर दी। अगर रेशनेलाइज़ होना है तो क्या ये जो रिक्रूटमैन्ट का प्रोसैस है उससे पहले रेशनेलाइजेशन हो जाएगी? यह तो हमें पता है कि वन्य प्राणी विंग में 46 पोस्टें भर रहे हैं। अब नैनादेवी तो उसमें है ही नहीं।

वन मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो पोस्टें हैं ये रिक्वॉयरमैन्ट के मुताबिक ही होती है और इनको इधर-उधर ले जाने का मतलब ही कोई नही है, कि चम्बा ले गये, कुल्लू ले गए कि शिमला ले गये। जहां जितनी पोस्टें खाली हैं उसके मुताबिक पोस्टें दी जाती है। It is not a question of Chamba. What do you mean by Chamba? अगर चम्बा में पोस्टें खाली होंगी तो नेचुरली चम्बा में जाएगी। अगर चम्बा में पोस्टें खाली होगी तो उसके मुताबिक वहां पोस्टे जाएगी।....(व्यवधान) ..अब

26.03.2015/1145/negi/jt/3

जहां हमने 80-80 और 87-87 पोस्टें दी हैं. it is due to the vacancy. _____(व्यवधान)____ यह पहली बार हुआ है । आपने क्यों नहीं भरी? ....(व्यवधान).

श्री रणधीर शर्माः जब वाईल्ड लाइफ रेंज टेरिटोरियल में गया तो वहां की पोस्टें दूसरी जगह क्यों ले गये?.... (व्यवधान)..

वन मंत्री : माननीय सदस्य, आपके हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ....(व्यवधान)..

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, जब रेंजर की पोस्ट वहीं है, बी.ओ. की पोस्ट वहीं है परन्तु 11 गार्डों की पोस्टें वहां से चली गई। फिर वहां गार्ड का काम कौन करेगा? फिर वही अवैध कटान होगा जिस तरह से पिछले 2 साल में 8 हजार मामले आए हैं अब और आएंगे। तो वो 11 पोस्टें वहां से कहां चली गई, कैसे चली गई, मंत्री महोदय इसका जवाब दें।

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो गार्ड की पोस्ट है, जहां रूल के मुताबिक खाली होंगी वहीं भरी जाएगी। There is no problem.

अध्यक्षः मंत्री जी इनको यह बताइये कि जब 11 पोस्टें वाईल्ड लाइफ से चली गई हैं उसके बाद जो टेरिटरी रह गई है उसको कौन कंट्रोल करेगा?
वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो पोस्टें कंवर्ट हुई है उनको उसी रेंज में दे दी जाएगी। क्या प्रॉब्लम है? दे दी जाएगी। ....(व्यवधान) ..देनी कहां जब खाली नही है। ....(व्यवधान)..दे दी जाएगी।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

26/1150/03.2015.यूके/एजी1/

प्रश्न संख्या---1767जारी----
(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, कह रहे हैं कि पोस्टें दे दी जायेगी।

26/1150/03.2015.यूके/एजी2/

प्रश्न संख्या- 1768

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना माननीय मंत्री जी ने सभा पटल पर रखी है उसमें झंडुता CHC में OPD सबसे ज्यादा है और वहां 3 पोस्टें खाली हैं। वह ब्लॉक हैड-क्वार्टर है। दूसरे PHC मरोत्तन में एक पोस्ट है और भरी हुई है। दो PHC बुहार और PHC गाह-घोरी ये दो पी0एच0सी0 ऐसी हैं, जो MPW द्वारा चलायी जा रही हैं और यहां इन्होंने दर्शाया है कि पोस्टें भरी हुई हैं। क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि जो डॉक्टर यहां लगाए गए हैं, वे कहां तैनात किए गए हैं ? अगर उनको कहीं बाहर डेपुटेशन पर तैनात किया गया है तो क्या इन PHCs में जहां पोस्टें खाली पड़ी हैं वहां उनको भेजने का आश्वासन देंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय सदस्य कह रहे हैं कि MPW लगाए गए हैं। लेकिन ये ए0एम0ओ0 है, आयुर्वेदिक मैडिकल ऑफिसर। They are also Doctors.

श्री रिखी राम कौंडलः सर, मैं 5 साल विधायक रह चुका हूं। मुझे MPW और AMO के बारे में मालूम है कि कौन होता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः ये MPW द्वारा भरी गयी है।

श्री रिखी राम कौंडल : MPW इधर नहीं है। MPW is running the hospital. He was sitting in the Hospital, not AMO. आप ऐसा समझते हैं कि इस माननीय सदन में हम सारे मूर्ख बैठे हैं।

26/1150/03.2015.यूके/एजी/3

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः आपने कहा कि MPW द्वारा, दो MPW लगाए गए हैं। आप रिकॉर्ड देखिए यहां। (व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि हमने जो जवाब दिया है कि आयुर्वेदिक मैडिकल ऑफिसर दो में लगे हैं। एक बात और PHC

ऋषिकेश खोला लेकिन उसमें पोस्ट कोई नहीं है, न फार्मासिस्ट की है न डाक्टर की है । हमने वहां भी डाक्टर लगाया है । जब कि पोस्ट कोई सैंक्शन नहीं है । यह ठीक है कि झंडुता में 5पोस्टों के अगेन्स्ट दो डॉक्टर लगे हैं, वहां जरूरत है, वहां हम डॉक्टर लगाएंगे । हर मंगलवार को डॉक्टरों का इन्टरव्यू होगा उसके बाद जो ब्लॉक लैवल के हमारे PHCs हैं, उनमें डॉक्टरों की संख्या बढ़ाएंगे । वैसे आपके यहां की पोजीशन ठीक है ,कोई ज्यादा पोस्टें खाली नहीं है । जो आयुर्वेदिक मैडिकल ऑफिसर हैं ये भी डॉक्टर है । लकिन यदि आप इनको विदड्रा करना चाहते हैं और MBBS डॉक्टर ही चाहते हैं तो उस पर भी सरकार विचार करेगी ।

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, मैने AMO का प्रश्न खड़ा नहीं किया । मैने कहा PHC बुहार में MPW दवाइयां देता है । वहां न AMO न MBBS डॉक्टर है । जो वहां पोस्टिड किया हुआ है वह वहां नहीं है । At present नहीं है । वह इस वक्त वहां नहीं बैठता है । कहीं दूसरी जगह, जहां विभाग ने भेजा है, तो क्या जिन डॉक्टरों को डेपुटेशन पर भेजा हुआ है उनको उन PHCs में वापिस लाने की कृपा करेंगे, इतना आश्वासन देंगे आप?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी सूचना दे रहे हैं । अगर उनको कहीं डेपुटेशन पर भेजा होगा तो आज ही हिदायत हो जायेगी कि उनका डेपुटेशन खत्म करके उसी जगह पर भेज दिया जायेगा और जो आपके पद खाली हैं, मैं जानता हूं आप पुराने विधायक हैं, हमारे सहयोगी रहे हैं तो आपका विशेष ध्यान रखा जायेगा ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी ---

26.03.2015/1155/sls-ag-1

Question : 1769

Shri Ravi Thakur: Hon'ble Speaker, Sir, has there been a procedure followed earlier, for example retired Tashi Angrup had given undertaking that he does not live in Lahaul, henceforth, TD given in Kullu for new construction and repair of house? DFO Lahaul endorsed that "for seven years" and TD was granted to him in Kullu twice? I would also like to ask

the Hon'ble Minister is the Forest Department concerned about the people of tribal areas settled elsewhere to protect their rights in their interest and feel responsible? I would also like to ask the Hon'ble Minister, if yes, what steps are taken for them?

वन मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि रवि जी ने भरमाया कि उनके बारे में क्या स्टैप्स ले रहे हैं, the Forest Department does not maintain the record of voting rights of the people. As regards forest rights, there is no such record available with Divisional Forest Officers, Kullu, Parvati and Seraj indicating that people of Lahaul & Spiti who have shifted after 1911 and enrolled in voter lists of Kullu have given up their forest rights in Lahaul.

In view of reply at (a), question does not arise. T.D. is granted on the basis of recorded rights in the settlement.

26.03.2015/1155/sls-ag-2

Shri Ravi Thakur: I would like to apprise and also bring to the notice of the Hon'ble Minister and also ask the Hon'ble Minister that before there was a procedure, like if anyone settled after 1911, he was in Kullu, so he used to get it endorsed from DFO, Lahaul that for seven years he will not take any TD rights in Lahaul and he was given TD rights in Kullu, but now this procedure is not followed because *roti, kapda or makan* everyone needs and like Civil Supplies Department endorses everyone gets ration cards and ration. So, this is also the Government policy to give TD to all the tribal areas and it is not only of Lahaul & Spiti, but it also includes Bharmour, Pangi and elsewhere Kinnaur who are settled outside. My question is this.

वन मंत्री : नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक स्थान पर अपना टी.डी. अधिकार छोड़कर दूसरे स्थान पर इसे लिया जाए। यदि कोई ऐसा स्पैस्फिक केस है तो बताएं, उस पर गौर करेंगे।

समाप्त

26.03.2015/1155/sls-ag-3

प्रश्न संख्या : 1770

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अख़बारों में ख़बर लगी है। 03.03.2015 को अमर उजाला में लिखा है -सरकार की लापरवाही से प्रदेश में ओपन हार्ट सर्जरी बंद। पंजाब केसरी में ख़बर लगी है कि प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में हार्ट के ऑप्रेशन पूरी तरह से बंद। यह ख़बरें लगी हैं। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं वह सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके जो डायरैक्टर हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि इस बारे में सरकार को लिखित रूप में जानकारी दे दी गई है। यह सच है कि वहां पर ऑप्रेशन बंद हो गए हैं। वजह यह बताई गई है, जो प्रिसीपल ने कहा है कि उसमें ओपन सर्जरी के दौरान प्रोफ्यूजनिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है और वह रिटायर हो गया है। उसकी वजह से ऑप्रेशन बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है लेकिन उसके बाद भी मंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय ,आप प्रश्न के 'ख' भाग को देंखे जिसमें पूछा है कि 'दिनांक 15.02.2015 को कितने मरीजों को हृदय शल्य चिकित्सा हेतु dates दी गई।' अध्यक्ष महोदय, ऑप्रेशन ठीक हो रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे सी.टी.वी.एस. जो आई.जी.एम.सी. में हैं, वहां जनवरी महीने में हार्ट के 13 ऑप्रेशन हुए, फरबरी में 12 ऑप्रेशन हुए।

जारी ...गर्ग जी

26/03/2015/1200/RG/JT/1

प्रश्न सं. 1770---क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री----क्रमागत

जनवरी महीने में हर्ट के 13 ऑपरेशन हुए, फरवरी में 12 ऑपरेशन हुए और जो अभी मार्च महीना चला हुआ है उसमें 14 हर्ट सर्जरी हुई हैं। यह ठीक है कि एक परफ्यूजनिस्ट रिटायर हुआ है और दूसरा अभी रिटायर होना है, लेकिन उसको हम री-ऐम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। अभी हमने कैबिनेट से एक पोस्ट सैंक्शन कर दी है और भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड को भेज दी है ,लेकिन अब हम आर.के.एस.

के माध्यम से भी सोच रहे हैं कि अगर कोई परफयुजनिस्ट मिलेगा ,तो उसको लगा दिया जाएगा। लेकिन ऑपरेशन बन्द होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री जय राम ठाकुर : यह अखबार में लिखा है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : ठीक है अखबार में लिखा है ,आप मेरा भी बयान पढ़ो कि ऑपरेशन बन्द नहीं हुए हैं ,ऑपरेशन हो रहे हैं। इसलिए आप अखबारों में न जाएं।

श्री जय राम ठाकुर : यह प्रिंसीपल ने भी माना है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण : प्रिंसीपल ने क्या मानना जब मैं मान रहा हूं कि ऑपरेशन बन्द नहीं हुए। अब आपको सूचना दे दी कि कितने ऑपरेशन हुए क्या मैं गलत बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मार्च महीने में अभी तक 14 ऑपरेशन हुए हैं। आपने जो प्रश्न पूछा है आपने पूछा है 15 फरवरी को डेट दी गई थी, लेकिन उस डेट में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। उस दिन तो इतवार था उस दिन क्या ऑपरेशन होना था।-----(व्यवधान)----नहीं कब किया होगा, यह 2/15की डेट है और उस दिन इतवार है।

श्री जय राम ठाकुर : आपके अधिकारियों ने माना है व आई.जी.एम.सी. के प्रिंसीपल ने माना है। उन्होंने अखबार में बयान दिया है कि सच्चाई है कि उनको ऑपरेशन बन्द करने पड़े और रोगी को वापस भेजना पड़ा है। सिर्फ एक मात्र हृदय रोगी जो वहां भर्ती था उसका उपचार हो रहा है। इसके अलावा किसी भी रोगी का उपचार आई.जी.एम.सी. में इस विभाग में नहीं हो रहा है। ऐसा उन्होंने कहा है। माननीय मंत्री जी यहां गलत सूचना दे रहे हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं ये सदन के अंदर उत्तर रहे हैं।

26/03/2015/1200/RG/JT/2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : जो मैंने डेट दी हैं ऑपरेशन कीं, यह सूचना बिल्कुल सही है चाहे, तो आप वैरीफाई कर लें। Whatever I speak on the Floor of the House, I speak from the correct information. आपकी तरह नहीं कि अखबारों को उठाकर गुमराह करें। मैं जो सूचना यहां दे रहा हूं, वह ठीक दे रहा हूं। 15का दिन देखो। आप क्या बात करते हैं? आप प्रश्न पढ़ो। आपका प्रश्न क्या है?-----(व्यवधान)---

(विपक्ष के कुछ सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर बोलने लगे)

प्रश्नकाल समाप्त

26/03/2015/1200/RG/JT/3

-----(**व्यवधान**)----

डॉ. राजीव बिन्दल : बिना परफयुजनिस्ट के क्या ये सारे ऑपरेशन करा दिए? ऐसा कैसे हो गया?

अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। कृपया आप लोग बैठ जाइए।-----(व्यवधान)---प्लीज, बैठ जाइए। There is no question now.---(Interruption)-----Please keep the order. आप लोग मेरी बात सुनिए। मंत्री जी ने सदन में जो सूचना दी है ,unless you disapprove it और आप प्रूव कर सकते हैं कि यह गलत है, इसलिए अभी जो सूचना दी है उस पर बिलीव कीजिए। यदि गलत होगा, तो आप बाद में इनसे पूछ लेना।

26/03/2015/1200/RG/JT/4

<u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन</u>

अध्यक्ष : अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2014-15) लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।

श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2014-15) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर रखती हूं:-:-

(i) समिति का **36वां मूल प्रतिवेदन** (वर्ष 2014-15) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09(वाणिज्यिक) में शामिल ऑडिट पैरा संख्या:3.6 से 3.14 तक के स्वयंमेव उत्तरों की समीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य **विद्युत परिषद्** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के **58वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना तृतीय कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि **हिमाचल पथ परिवहन निगम** से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष : अब श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति (वर्ष 2014-15) मानव विकास समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।

26/03/2015/1200/RG/JT/5

श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2014-15) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

(i) समिति का **15वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 7वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित **तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के **22वें मूल प्रतिवेदन** (दसवीं विधान सभा) (वर्ष 2004-05) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर 47वें कार्रवाई प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) (वर्ष 2006-07) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि **आयुर्वेद विभाग** से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष : अब श्री कर्ण सिंह, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति (वर्ष 2014-15) ग्रामीण नियोजन समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री कर्ण सिंह, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2014-15) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण नियोजन समिति का 11वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि उद्योग विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

एम.एस. द्वारा अगली मद शुरू

26/03/2015/1205/MS/AG/1

तारांकि प्रश्न संख्या 1604 के बारे में मुख्य मंत्री का वक्तव्य

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री तारांकित प्रश्न संख्या 1604 :जिसका दिनांक 19 मार्च, 2015 को सदन में उत्तर दिया जा चुका है, में शुद्धि करने के बारे में वक्तव्य देंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्याः 1604 जोकि दिनांक 19 मार्च, 2015 को निर्धारित था, के उत्तर में निम्नलिखित संशोधन करता हूं।
-1क्रम संख्या 13 पर दिए गए आंकड़ों 19.36 लाख रूपये के स्थान पर 193.70 लाख रूपये पढ़ा जाए।
-2सकल योग में दर्शाई गई संख्या 71,309.43 लाख रूपये के स्थान पर 7 1483.77 लाख रूपये पढ़ा जाए।

26/03/2015/1205/MS/AG/2

<u>वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमान</u>ः

सामान्य चर्चा एवं चर्चा का समापन।

अध्यक्षः अब बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 16-2015पर सामान्य चर्चा एवं चर्चा का समापन होगा।

अब वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा आरंभ होगी और आज ही माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर के साथ चर्चा का समापन भी होगा। अभी चर्चा में भाग लेने हेतु सात माननीय सदस्य शेष हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे निश्चित समय में अपनी बात कहें। जो बातें पहले कही जा चुकी हैं, उन्हें न दोहराएं और कोई नई बात करें। यदि चर्चा को संक्षिप्त में ही करे तो अच्छा रहेगा। अब मैं डॉ0 राजीव सैजल को चर्चा करने हेतु आमंत्रित करता हूं।

डॉ0 राजीव सैजलः अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में जो बजट अनुमान प्रस्तुत किए हैं, मैं उस पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष जी, मुझे बड़ा ताज्जुव हो रहा था जब हमारे सत्ता पक्ष के मित्र इन बजट अनुमानों पर बोल रहे थे। इनके द्वारा सरकार के पक्ष में और मुख्य मंत्री जी के पक्ष में कसीदे-पर-कसीदे पढ़े जा रहे थे यानी तारीफ के पुल बांधे जा रहे थे। एक

प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री जी को इतिहास पुरूष सिद्ध करने का प्रयास हमारे सत्ता पक्ष के मित्र कर रहे थे।

अध्यक्ष जी, मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि किसी कवि ने बहुत खूब कहा है कि-

इस जग में मिलता नहीं मान,
सिर्फ अपना गोत्र बतलाकर,
इस जग में मिलती है प्रशस्ति,
कुछ करतब दिखलाकर।।

यद्यपि इस बजट को शेरो-शायरी से सजाया गया है और कुछ आंकड़े प्रस्तुत करके यहां पर प्रदेश के जख्मों को ढकने का प्रयास भी किया गया है। इस सदन के

26/03/2015/1205/MS/AG/3

अंदर आज तक बजट अनुमान प्रस्तुत होते रहे हैं और आंकड़े इसी प्रकार साल-दर-साल यहां पर रखे जाते रहे हैं। लेकिन मैं यहां पर बड़े जोर से कहना चाहता हूं कि प्रदेश आंकड़ों से नहीं चला करता, प्रदेश शेरो-शायरी से नहीं चला करता बल्कि प्रदेश सद्भावना और दूरदर्शिता से चला करता है। मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी को बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आपकी कार्यशैली में न तो मुझे कोई सद्भावना दिखाई देती है और ही कोई दूरदर्शिता दिखाई देती है। सद्भावना नहीं दिखाई देती है लेकिन दुर्भावना जरूर दिखाई देती है। वर्तमान सरकार का ढाई वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। यह जो ढाई साल का इतिहास है और हम तो इनको इतिहास पुरूष की संज्ञा देने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत बड़ा इनको साबित करने का प्रयास कर रहे हैं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

26.3.2015/1210/जेटी/जेके/1

श्री राजीव सैजलः-----जारी--

बहुत बड़ा हम उनको साबित करने का प्रयास कर रहे है। लेकिन अगर हम ढाई वर्ष का कार्यकाल देखें तो यह दुर्भावना का कार्यकाल है। यह दमन का कार्यकाल है। हमारे सम्माननीय पूर्व मुख्य मंत्री और प्रतिपक्ष के नेता, प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी पर मामले पर मामले बनाए गए। उन पर तो मामले बने हैं लेकिन यहीं तक बात सीमित नहीं रही उनके परिवार के सदस्यों के ऊपर माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी और उनके जो दूसरे छोटे सुपुत्र हैं जिनका राजनीति से कोई संबंध ही नहीं है, उनको भी लपेटने का प्रयास इस सरकार ने किया है। इसे हम दुर्भावना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अभी जो ताज़ातरीन मामला जिसमें माननीय धूमल जी को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है पूर्व आई.पी.एस. अधिकारी, ए.एन. शर्मा जी की पूर्व नियुक्ति के बारे में। आपने पूर्व राज्यपाल महोदया से सम्माननीय धूमल जी के खिलाफ प्रोसिक्युशन सेंक्शन मांगा था, उन्होंने सरकार को क्या उत्तर दिया उसकी प्रतिलिपि अभी मेरे पास है? मैं यहां पर उसको पढ़ना चाहूंगा। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय इसको मैं आपको भी सौंप दूंगा। माननीय पूर्व राज्यपाल महोदया कहती हैं कि "As regards offences under IPC are concerned, prima facie the nature of the alleged offences in the instant case under sections 420 and 120B of IPC does not seem to be reasonably connected with the discharge of official duty of the public servant." यानि पूर्व राज्यपाल महोदय ने स्पष्ट तौर से सरकार को यह लिखा है कि जो धाराएं इस केस में सम्माननीय धूमल जी को घेरने के लिए लगाई गई हैं उन धाराओं को उनके विरूद्ध लगाया जाना अनुचित था। सम्माननीय राज्यपाल महोदया भी इस चीज़ को मान रही है और प्रदेश सरकार को चेता रही है। सम्माननीय वर्तमान जो हमारे राज्यपाल महोदय, कल्याण सिंह जी हैं उन्होंने भी यही बात कही है। अब यह मामला कोर्ट में जाएगा। मैं, मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या कोर्ट में पूरी ईमानदारी के साथ पूरे तथ्य वहां पर रखेंगे? पूर्व राज्यपाल महोदया ने क्या कहा वह भी आप रखें? वर्तमान राज्यपाल महोदय ने क्या कहा उसको भी आप रखें? इस प्रकार से न सिर्फ धूमल जी को,

26.3.2015/1210/जेटी/जेके/2

उनके परिवार को हमारे विधायकों को भी विज़िलैंस के माध्यम से परेशान करने का प्रयास हो रहा है। प्रदेश में कानून-व्यवस्था बिगड़ रही है। हिमाचल ट्रिब्यून का यह अंक मेरे पास है। महिलओं के ऊपर अत्याचार इस प्रदेश के अन्दर निरन्तर बढ़ रहे हैं। यह अखबार लिखता है -one rape, two molestations, one abduction every second day in Himachal. यदि इतनी बूरी कानून-व्यवस्था की हालत हमारे प्रदेश की हो गई है, पूरे का पूरा पुलिस तंत्र हमारे विधायकों के ऊपर, हमारे पूर्व मुख्य मंत्री के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर और हमारे कार्यकत्ताओं के ऊपर केस बनाने में जुटा है, इसको हम दुर्भावना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हमारे कार्यालय के ऊपर जबरदस्त हमला हुआ। कांग्रेसी कार्यकत्तओं ने हमला किया। मुख्य मंत्री जी के सुपुत्र खुद उस हमले का नेतृत्व वहां पर कर रहे थे। पुलिस की भूमिका उस हमले से पूर्व और उस हमले के बाद आज तक क्या है यह किसी से छिपा नहीं है? आज सरकार की भर्त्सना पूरे प्रदेश में हर आदमी कर रहा है कि सरकार ने अपना ढाई वर्ष का कार्यकाल धूमल जी के ऊपर केस बनाने, इनके परिवार के ऊपर केस बनाने और भाजपा नेताओं के ऊपर केस बनाने में व्यतीत कर दिया है। भाजपा कार्यकर्त्ताओं, भाजपा विधायकों और नेता प्रतिपक्ष तक बात सीमित रहती तो भी ठीक था। आप लोगों ने तो संतों को भी नहीं छोड़ा। बाबा रामदेव जो कि विश्व प्रसिद्ध योग ऋषि के रूप में जाने जाते हैं। पूरे विश्व में उनके केन्द्र है। मैं तो वहां पर जाता रहा हूं। योग का वहां पर प्रशिक्षण प्राप्त करता रहा हूं। मैं यहां पर सत्ता पक्ष के मित्रों से भी निवेदन करूंगा कि वहां पर एक बार जा कर तो देखिए। हिमाचल में भी एक अवसर आया था। ऋषिकेश को हम कहते हैं "Yoga Capital of the World". ऋषिकेश का वातावरण जिस प्रकार से आजकल बन गया है वहां पर इतना शोर और प्रदूषण है मुझे नहीं लगता है कि हिमाचल जैसे उपयुक्त स्थान योग के लिए साधना के लिए अन्यत्र कहीं विश्व में हो सकता है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी------

26.03.2015/1215/SS-JT/1

डॉ0 राजीव सैजल क्रमागतः

साधुपुल के अंदर जिस प्रकार से उनको पूर्व मुख्य मंत्री महोदय के नेतृत्व वाली सरकार ने भूमि आबंटित की थी और एक मौका दिया था कि हमारे प्रदेश में भी एक

अच्छा योग संस्थान आए। जिसका स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए पूरे विश्व के लोग यहां आ सकें। पर्यटन को योग के साथ जोड़ करके जो एक विज़न था, सपना था, जिससे प्रदेश को भी लाभ होना था, टूरिज्म को बढ़ावा मिलना था और किस प्रकार से साधुपुल को पुलिस की छावनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यह किसी से छिपा नहीं। केन्द्र सरकार ने भी बाबा रामदेव को बहुत सताया। आपने भी बहुत सताया। केन्द्र सरकार ने फल भोग लिया और अब आप भी संतों को सताने का फल भोगने के लिए तैयार रहें। मैं दावे से कहना चाहता हूं कि अगली बार आप कोई भी इस सदन में नज़र नहीं आने वाले हैं। बदले की भावना से कॉलेज बंद हुए। मैंने जब कॉलेज बंद हुआ उसके तुरन्त बाद यहां जो सत्र हुआ था उसमें मामला उठाया था। मैंने मुख्य मंत्री जी से पूछा था कि कॉलेज क्यों बंद हुआ तो मुख्य मंत्री जी ने अपनी सीट पर खड़े होकर यह जवाब दिया था कि आप एक टॉयलैट से रैस्ट हाउस नहीं चला सकते। ये उनके शब्द हैं इस सदन के अंदर। उन्होंने यह कहा था कि धर्मपुर का जो कॉलेज है वह ब्लॉक प्राईमरी एजुकेशन ऑफिसर के तीन कमरों में चल रहा है तो ऐसे तीन कमरों के अंदर कॉलेज नहीं चला करते। कल भी मेरा इस कॉलेज को लेकर प्रश्न था और उसमें उत्तर आया है। मैंने पूछा था कि वर्तमान में यह कॉलेज कहां चल रहा है? आपकी सरकार ने वह कॉलेज बंद किया और फिर दोबारा उसको 6 महीने के बाद शुरू किया। आज भी वह कॉलेज आपने वहीं शुरू किया है जो आप यहां पर आलोचना कर रहे थे कि तीन कमरों के अंदर धर्मपुर का कॉलेज चल रहा है। कल आपके उत्तर में यहां आया कि वहीं तीन कमरों में आज भी वह कॉलेज चल रहा है। इसको हम दुर्भावना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे।

प्रदेश में चोर सक्रिय हो गए हैं। ड्रग, शराब माफिया सक्रिय हो गया है। जिसके बारे में मैंने अभी न्यूज़पेपर से पढ़कर सुनाया था। कानून-व्यवस्था के अंदर अगर मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात करूं तो परवाणू जोकि हर दृष्टि से संवेदनशील भी है और हमारे पूरे प्रदेश के अंदर बड़े महत्व का स्थान भी है वहां मैं इस सदन में यह कहना चाहूंगा कि एक परिवार जिसको वर्तमान सरकार का संरक्षण प्राप्त है उस परिवार के द्वारा किस प्रकार से दहशत का माहौल परवाणू के अंदर बनाया जा रहा है। इसको

मैं सदन में उठाना चाहूंगा। अगर आप कसौली चौंक से ले करके सैक्टर-6 तक आएं तो सड़क की दोनों ओर (बाईं व दाईं ओर) अवैध ढंग से ट्रकों की पार्किंग की गई है। ठीक है आपके पास सारी व्यवस्था है। आपके पास पुलिस, सी0आई0डी0, विजीलैंस है, आप पता करवाई कि किस परिवार के द्वारा वह यूनियन संचालित है जिसके ट्रक सड़क की दोनों ओर लगे हुए हैं। कोई सामान्य व्यक्ति कई बार गलती से अपना वाहन गलत ढंग से पार्क कर देता है तो पुलिस वाले तुरन्त धौंस जमा करके उसका चालान करते हैं। उससे पैसे वसूलते हैं। लेकिन सड़क के दोनों ओर सैंकड़ों ट्रक खड़े हुए हैं लेकिन पुलिस का ध्यान उस अवैध पार्किंग की ओर नहीं जाता। मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस भी उस परिवार से डरती है। उस परिवार से निश्चित तौर से डरती है। अभी एक ताज़ा तरीन घटना सैक्टर-6 के अंदर हुई। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसमें तथ्य क्या रहे हैं आप उसकी जानकारी प्राप्त करें। सैक्टर-6 में दिन-दिहाड़े एक लड़की को उसके घर से उठाया गया। उसके घर से उठाया गया और सैक्टर-6 में ही कुछ लोग उसे किराये के मकान में ले गए। जैसे ही हम सैक्टर-6 में मेन रोड से एंटर होते हैं तो एक नई बिल्डिंग वहां पर बनी है। वहां पर लोगों ने एक कमरा किराये पर ले रखा है। किस प्रकार से उस लड़की को उठा करके उस कमरे के अंदर ले गए और उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ। उसके माता-पिता पुलिस स्टेशन में गए। आप पता लगाईये कि वे लोग किस परिवार से संबंधित हैं जिन्होंने उसको अगवा किया और उसके साथ दुर्व्यहार किया। किन लोगों ने उसके मां-बाप पर दबाव डाला कि आप मामला वापिस ले लो।

जारी श्रीमती के0एस0

/1220/26.03.2015केएस/जेटी1/

डॉ0 राजीव सैजल जारी---

कि आप मामला वापिस लें। इस प्रकार की स्थिति परवाणू में है। इस प्रकार से अगर अपराध को संरक्षण मिलता रहेगा, अगर गलत लोगों के ऊपर सरकार का संरक्षण रहेगा तो क्या यह प्रदेश ऐसा ही रहेगा जैसा वर्तमान में है? हम अपने भोलेपन और स्वच्छ वातावरण के लिए जाने जाते हैं और अगर पूरे देश में अच्छी राजनीति की चर्चा होती है तो हमारे प्रदेश की राजनीति का उदाहरण पूरे देश में दिया जाता है। तो हिमाचल को हम बिहार न बनाएं और ऐसे लोगों को राजनीति में सरकार का संरक्षण न मिले तो यह प्रदेश की सेहत के लिए अच्छा रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों की हालत बहुत खराब है। जिस प्रकार से हमारे मित्रों ने अपने-अपने चुनाव क्षेत्र की सड़कों की दूर्दशा का वर्णन यहां पर किया है, मेरे चुनाव क्षेत्र में भी सड़कों की हालत बहुत खराब है। चाहे भोजनगर-मल्ला के रोड़ को देखें, हमारी सरकार के समय में इसका निर्माणकार्य धूमल जी के आशीर्वाद से शुरू हुआ था। जो अच्छा काम हुआ, धूमल जी के ही कार्यकाल में हुआ उसके बाद जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है, जाकर देखिए कि किस प्रकार से सड़क में सरकारी फंड का दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी फंड वेस्ट हो रहा है। भोजनगर-नेरीकलां-टिक्करी और जितनी भी सड़कों का निर्माण कसौली निर्वाचन क्षेत्र में हो रहा है, उसके लिए धन की और अन्य सारी व्यवस्थाएं माननीय धूमल जी ने की थी, उन्हीं सड़कों का निर्माण हो रहा है और हमारे द्वारा आपकी सरकार के कार्यकाल में जो सड़कों की डी.पी.आर. में जो हमने अपनी प्रायोरिटी सौंपी है सड़कें बनाने के लिए

/1220/26.03.2015केएस/जेटी2/

अभी तक ढाई वर्ष का कार्यकाल हो गया मेरे चुनाव क्षेत्र के अंदर एक भी सड़क की डी.पी.आर. आप तैयार नहीं करवा पाए हैं तो यह भी मुझे सरकार की दुर्भावना लगती है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अधिकारियों को निर्देश है कि जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वहां विकास कार्यों को थोड़ा-थोड़ा ब्रेक लगाया जाए। यह नीति ठीक नहीं है। सरकार तो सबकी है और ऐसा नहीं है कि मेरे पूरे निर्वाचन क्षेत्र के अंदर भाजपा से सम्बन्धित लोग ही रहते हैं। वहां कांग्रेस के लोग भी है, न्यूट्रल लोग भी है, सारी विचारधाराओं के लोग हैं । उनमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बूढ़े भी हैं और नौजवान भी हैं। इस प्रकार कल्याण करने की सरकार की जो भावना होनी चाहिए, ढाई वर्ष के कार्यकाल के दौरान यह भावना बिल्कुल लुप्त रही।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि अभी और भी हमारे मित्र बोलने वाले हैं, उनको भी समय मिलना चाहिए । विधायक निधि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जरूर बढ़ाई है, मैं उसके लिए इनका धन्यवाद करना चाहूंगा। जो 20 लाख रुपये लघु सिंचाई योजनाओं पर खर्च करने का राइडर इन्होंने लगाया है, मैं चाहूंगा कि उसको समाप्त किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, एक और विषय के बारे में बताना चाहूंगा कि जैसे एम.पी. ने किसी भवन के निर्माण के लिए पैसा दिया, उसका निर्माण उस पैसे से पूरा नहीं हुआ और उस कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त राशि चाहिए तो विधायक चाह कर भी वह पैसा नहीं दे सकता और दूसरा

/1220/26.03.2015केएस/जेटी3/

विषय इसमें यह है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें भी कच्ची हैं और बारिश के कारण नुक्सान भी बहुत होता है । कहीं सड़क गिर जाए, किसी घर को कोई खतरा हो जाए, कोई सामुदायिक भवन बना है, कोई महिला मण्डल भवन बना है उसकी अगर ईमारत को खतरा हो जाए और डंगा लगाने की आवश्यकता है तो विधायक डंगा लगाने के लिए पैसा नहीं दे सकते। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि इसमें गाईड लाइन में संशोधन करके व्यवस्था की जाए कि इन कार्यों के लिए भी हम पैसा दे सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की इस सरकार की भावना है मैं इस सरकार की नीतियों और कार्यशैली से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। और ये जो बजट अनुमान यहां पर प्रस्तुत किए गए, इनसे भी मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हां तारीफ करेंगें कि अगले साल, जो सारे मामले धूमल साहब के ऊपन बनाए गए हैं, मुख्य मंत्री जी बड़ा दिल करके, ठीक है कि आप सबसे ज्यादा समय इस प्रदेश के मुख्य मंत्री रहें हैं, अगर आप बड़ा दिल करते हैं, सद्भावना दिखाते हैं और इस प्रकार से अगर अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करने का संकल्प लेते हैं तो निश्चित तौर पर अगले साल जो बजट आने वाला है उसका हम समर्थन करेंगें परन्तु वर्तमान में मैं इस बजट का समर्थन करने में बिल्कुल असमर्थ हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

/1220/26.03.2015केएस/जेटी4/

अध्यक्षः चर्चा में भाग लेने के लिए श्री जगत सिंह नेगी, मा0 उपाध्यक्ष ने भी बोलने की इच्छा जाहिर की है । ये भी चर्चा में भाग लेंगें।

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट अनुमान 2015-16 माननीय मुख्य मंत्री जी ने 18 मार्च को इस माननीय सदन में पेश किया उस पर अपने विचार रखने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा---

26.3.2015/1225/jt/av/1

उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए जो बजट अनुमान 18मार्च को इस सदन में प्रस्तुत किए, मैं उसी पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

इस बजट में ट्राइबल सब प्लान के तहत पिछले वर्ष के मुकाबले 37 करोड़ रुपये का इज़ाफा हुआ है। ट्राइबल सब प्लान का बजट 432 करोड़ रुपये का है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत आभारी हूं क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है। सही मायने में जनजातीय क्षेत्रों में विकास माननीय मुख्य मंत्री जी के समय में ही हुआ है। बहुत सारी जनजाति सब प्लान के तहत है जिसमें विशेषकर वर्ष 2010 से लगातार प्लानिंग डिपार्टमैंट ने जनजातीय योजना के तहत बजट की ईयर मार्किंग करनी शुरु की है। जिसके फलस्परूप अब 60 प्रतिशत से ऊपर जनजातीय सब प्लान का बजट ईयर मार्क किया जाता है। यह जो ईयर मार्किंग की जाती है इससे बिजली बोर्ड को पैसा जाता है। इसका पैसा ट्रांसमिशन ऑफ लाइन्ज के लिए जाता है। इसका पैसा हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को लोन के रूप में दिया जाता है। कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर और हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय, नौणी को भी इसी सब प्लान में से ईयर मार्किंग करके पैसा दिया जाता है जिससे ट्राइबल सब प्लान में भारी नुकसान होता है। काफी कम पैसा ट्राइबल सब प्लान में रहता है। जैसे मैंने कहा कि 60 प्रतिशत से ऊपर यह ईयर मार्किंग हुई है और यह लगातार वर्ष 2010 के बजट के बाद शुरु किया गया। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से क्योंकि ट्राइबल डिपार्टमैंट भी इनके पास है। इनसे विशेष आग्रह रहेगा कि सब प्लान की जो ईयर मार्किंग की जा रही है इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है ताकि जनजातीय क्षेत्रों में धन की कमी न हो और जनजातीय क्षेत्रों का ज्यादा-से-ज्यादा विकास हो। इसी के साथ, जनजातीय क्षेत्रों में ट्राइबल सब प्लान है तो वहां पर सिंगल लाइन ऐडमिनिस्ट्रेशन भी है। इसी

तरह से जो विभागों के सचिवों को ए.ए.एण्ड ई.एस. की पावरज दी गई है वह भी प्रींसिपल सैक्रैटरी, ट्राइबल डिवैल्पमैंट को दी जानी चाहिए। अकसर यह देखने में आता है कि जैसे शिक्षा विभाग है। मेरे चुनाव क्षेत्र में

26.3.2015/1225/jt/av/2

एक ही स्कूल में पिछले तीन-चार वर्षों से ए.ए.एण्ड ई.एस. नहीं कर पाये जबकि उसमें बजट का प्रावधान है। उसमें लगभग 40-50 लाख रुपये पड़ा हुआ है मगर ए.ए.एण्ड ई.एस. की वजह से वहां यह काम नहीं हो रहा है। इससे पहले भी ए.ए.एण्ड ई.एस. की पावर प्रींसिपल सैक्रैटरी, ट्राइबल डिवैल्पमैंट को थी। अतः यह पावर दोबारा से सभी विभागों से वापिस लेकर प्रींसिपल सैक्रैटरी, ट्राइबल डिवैल्पमैंट को दी जाए ताकि ए.ए.एण्ड ई.एस. जल्दी-से-जल्दी हो जाए और वहां विकास के काम आगे बढ़ें।

इसी के साथ, मैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में भी कुछ बात करना चाहूंगा। मैं मुख्य मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी का भी आभारी हूं कि पहली बार जनजातीय क्षेत्रों में सभी पी.एच.सीज. में डॉक्टर्ज के पद भरे गये हैं। मैं अपने जिला के जोनल अस्पताल में स्पैशेलिस्ट डॉक्टर्ज (पी.जी. डॉक्टर्ज) की तैनाती के बारे में भी अपने विचार रखना चाहूंगा। जनजातीय क्षेत्रों में केवल दो ही जोनल अस्पताल हैं। एक रिकाँगपियो और दूसरा लाहौल स्पिति के केलाँग का है। वहां दोनों अस्पतालों में 7-7, 8-8 स्पैशेलिस्ट डॉक्टर्ज की जरुरत है। यानि दोनों जगहों को मिलाकर कुल 1-6 17 स्पैशेलिस्ट डॉक्टर्ज की जरुरत है। जनजातीय क्षेत्रों में जो मैडिकल ऑफिसर काँट्रैक्ट पर भेजे जाते हैं उनको 45 हजार रुपये का इनसैंटिव दिया जाता है। मगर जो रेगुलर डॉक्टर्ज जाते हैं उनके लिए कोई इनसैंटिव नहीं है। पी.जी. के डॉक्टर्ज को कोई इनसैंटिव नहीं है। इनसैंटिव न होने के कारण पी.जी.डॉक्टर्ज वहां के लिए आकर्षित नहीं होते। मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा कि अगर जनजातीय क्षेत्रों में 16-17 स्पैशेलिस्ट डॉक्टर्ज को तैनात किया जाता है तो उनको भी काँट्रैक्ट वाले डॉक्टर्ज को दिए जा रहे इनसैंटिव की तरह तनख्वाह के ऊपर कुछ इनसैंटिव दिया जाए। नेशनल रूरल हैल्थ मिशन के तहत फण्ड की कमी नहीं है यह इनसैंटिव उसमें से दिया जा सकता है। इस तरह का इनसैंटिव देकर हम ज्यादा-से-ज्यादा

पी.जी. डॉक्टर्ज को जनजातीय क्षेत्रों की तरफ आकर्षित कर सकते हैं----------
-

श्री बी.जे.नेगी द्वारा जारी

26.03.2015/1230/negi/ag/1

मा0 उपाध्यक्ष महोदय.. .जारी..

और हम ज्यादा से ज्यादा जो पी.जी. डॉक्टर्ज़ हैं, स्पैशलिस्ट डॉक्टर्ज़ हैं उनको जन-जातीय क्षेत्रों में आकर्षित कर सकते हैं।

इसी के साथ में, एकलव्य स्कूल जो 6वीं से लेकर 12वीं तक इंगलिश मीडियम का फ्री, कांस्टिट्युएशन के आर्टिकल-271 के तहत जन-जातीय क्षेत्र में खुला है, मेरे चुनाव क्षेत्र में उसके नए भवनों के लिए 23 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान है। यह सारा पैसा केन्द्र सरकार के आना है। जन-जातीय विभाग से आना है और कांस्टिट्युएशन के तहत आना है। पिछले 7 सालों में केवल मात्र 3 करोड़ रूपये ही उपलब्ध हुए हैं। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि इस मामले को केन्द्र सरकार से उठाया जाए। कांस्टिट्युएशन के तहत हमें जो पैसा मिलना है इसको तुरन्त उपलब्ध करवाया जाए ताकि जो हमारा इंगलिश मीडियम एकलब्य स्कूल जो निचार में स्थापित किया गया है, जिसके भवनों का निर्माण होना है, इसको तुरन्त शुरू किया जा सके।

इसके साथ, यहां पर बन्दरों के बारे में बहुत चर्चा हुई । मैं भी जब पहली बार विधायक बना वर्ष 1995 में तब से जब-जब मौका मिला इस मान्य सदन में आने का, पक्ष और विपक्ष ने हमेशा बन्दरों के बारे में बहुत चर्चा की । परन्तु नतीज़ा कुछ नही निकला। सरकार ने करोड़ों रूपये बन्दरों के नसबन्दी के ऊपर खर्च किये हैं। कहते हैं कि 2001 से लेकर 2015 के बीच में करीब 95 हजार बन्दरों की नसबन्दी की गई है परन्तु बन्दरों की तादाद कम नही हुई है। बता रहे हैं कि फिगर 3 लाख की है अगर इनका सही सर्वे किया जाए तो ये ज्यादा भी हो सकते हैं।

अध्यक्षः बिन्दल जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या व्यवस्था का प्रश्न है?

डॉ0 राजीव बिन्दलः सर, व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, कोरम पूरा नही है।

अध्यक्षः आप (उपाध्यक्ष महोदय) जारी रखें।

26.03.2015/1230/negi/ag/2

उपाध्यक्षः मैं बन्दरों के विषय में अपने विचार रख रहा था। बन्दरों पर करोड़ों रूपये खर्च हो गए हैं। नसबन्दी केन्द्र भी स्थापित हो गए हैं । बन्दरों को पकड़ने के लिए कई लोग लखपति बनाए गए हैं। अभी विधान सभा के अन्दर एक प्रश्न लगा था उसमें जो सूचना दी गई उसके मुताबिक एक-एक व्यक्ति को 28-28 लाख रूपये भी बन्दर पकड़ने के लिए दिए गए हैं। हमने भी देखा इधर, हमारे एम.एल.ए. हॉस्टल के सामने भी पिंजरा लगाया गया था परन्तु मैंने उसमें एक भी बन्दर को जाते हुए नही देखा। क्योंकि बन्दर एक बहुत ही तीक्ष्य बुद्धि का जानवर है और एक बार उसको पता लगता है कि यह पिंजरा है तो वह हट करके उसमें नहीं जाता है बल्कि पिंजरा लगाने वाले को भी पहचान जाता है । अब यहां बहुत बड़ी-बड़ी बातें हो रही थी कि अखबारों के माध्यम से आया कि हांगकांग में बन्दरों को contraceptive देकर उनकी पपुलेशन कम किया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि हांगकांग में केवल 2000 बन्दर हैं। उन्होंने भी कोई ऐसा contraceptive या पिल नही बनाया जो बन्दर को खिला दे और उसके बाद आगे प्रजनन नही होगा। क्योंकि बन्दरों का कोई ब्रिडिंग सीजन नही है। आप किस तरह से पिल देंगे ? हांगकांग वाले वर्ष 2000 से लगे हुए हैं और 2015 तक वे 15 परसेन्ट बन्दर कम नही कर सके, 2 हजार बन्दरों की। हिमाचल में बन्दरों की संख्या 3 लाख है। मलेशिया में भी यह प्रॉब्लम था और सिंगापुर में भी यह प्रॉब्लम था परन्तु वहां की सरकारों ने कलिंग का माध्यम अपनाया। अभी हमारे विपक्ष के नेता माननीय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी ने भी यहां पर जब बन्दरों के बारे अपना विचार रखा तो इन्होंने भी जो कलिंग है, इनको खत्म करने की बात की, समाप्त करने की बात की है। इन्होंने भी साथ दिया है।जब विपक्ष का भी साथ है तो फिर सरकार को उसमें क्या दुविधा है? बजट में भी यह प्रावधान है कि वाईल्ड लाइफ अधिनियम की धारा 62-के तहत इनको वर्मिन डिक्लेयर करने के लिए सरकार केन्द्र सरकार से आगे कार्रवाई करेगी । यह बजट में दिया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। इसमें यही तरीका है कि वाईल्ड लाइफ के सेक्शन-62 के

तहत केन्द्र सरकार से इसको वर्मिन डिक्लेयर कीजिए, इसको पेस्ट डिक्लेयर कीजिए और उसके बाद एक समय सीमा में बन्दरों की तादाद को खत्म कीजिए।

26.03.2015/1230/negi/ag/3

हिमाचल में 5 हजार बन्दर बहुत है। बाकी बन्दरों को आप समाप्त कीजिए। कुछ लोग कह रहे थे इनको यहां से एक्सपोर्ट करेंगे । एक्सपोर्ट किसलिए होता है? एक्सपोर्ट एक्सपेरिमेन्ट के लिए होता है। वहां पर चाहिए होते हैं कुल 100 के हिसाब से बन्दर । एक्सपेरिमैन्ट में वो हमारे 3 लाख बन्दर नहीं लेंगे। तो मैं समझता हूं कि इसको कलिंग करना ही एक सबसे बड़ा समाधान है। आज यह बताया जा रहा है, एक अनुमान के हिसाब से 2006 से लेकर अभी तक 380 करोड़ रूपये किसानों का और बागवानों का नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोगों की खेती उज़ड़ गई है। आज लोग खेती करना छोड़ गए हैं। हजारों की...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

26/1235/03.2015.यूके/1

उपाध्यक्ष----जारी----

हजारों की तादाद में लोग बेरोजगार हो रहे हैं । ऐसे समय में एक ऐक्शन लेने का समय है । आज आपने ईको बटालियन का गठन किया है, जिस पर करोड़ों रूपया खर्च किया जा रहा है । इस ईकों बटालियन में हमारे जो सेना से सेवा-निवृत्त अधिकारी या सैनिक है, उनको रखा गया है । उनको प्लांटेशन में लगाया गया है । आप इस ईको बटालियन को यह कार्य सौंप सकते हैं । आप होमगार्ड के नौजवानों को सौंप सकते हैं ताकि बंदरों को तुरन्त समाप्त किया जाए । इसमें जहां धार्मिक आस्था की बात है , ऐसी कोई बात नहीं है । बंदरों की 262 से ज्यादा प्रजातियां हैं । तो कौन से बन्दर भगवान राम के थे, इसके बारे में आपके पास या हमारे पास कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं है । भगवान राम ने भी बालि का वध किया था, वह आवश्यकता थी उस समय के हिसाब से । तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है इस प्रदेश के अन्दर अन्यथा आने वाले समय में लोग खेती करना छोड़ देंगे और जब

खेती करना छोड़ेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी । तो जो अमन-शांति हमारे प्रदेश में है, इसके ऊपर भी बहुत बड़ी मुश्किलात आने वाली है ।

अध्यक्ष महोदय, एक बिजली के प्रोजेक्टों के बारे में भी यहां पर चर्चा हुई । बहुत कुछ कहा गया कि हम इतने मेगावाट बिजली जनरेट करेंगे । परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि आज बिजली बोर्ड या बिजली विभाग में नए रक्त के संचार की जरूरत है । वे प्रोजेक्ट जिनको 5 साल में बनना था वह 15 साल में नहीं बन रहे हैं । मेरे चुनाव क्षेत्र में एक बिजली का कशंग प्रोजेक्ट है, 68 मेगावाट का बनना था । सन् 2000 में जब धूमल साहब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने उसका फाऊंडेशन रखा । फिर उसके बाद कांग्रेस की सरकार आयी । फिर दोबारा धूमल साहब की सरकार आयी । फिर दोबारा से कांग्रेस की सरकार आयी । आज 15 साल होने जा रहे हैं । परन्तु उस 68 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट नहीं बन पाया । अभी एक प्रोजेक्ट है, पॉवर कारपोरेशन का, जो मेरे चुनाव क्षेत्र में है जो 400 मेगावाट का बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कम

26/1235/03.2015.यूके/2

लागत से बनने वाला प्रोजेक्ट है । सारी पंचायतों ने NOC दिया हुआ है । परन्तु जिस तरह से एच0पी0 पॉवर कॉरपोरेशन काम कर रही है, मुझे नहीं लगता कि 20 साल में भी यह प्रोजेक्ट बनेगा । सब-कुछ क्लियर है ,NOC मिला हुआ है । उसके बाद भी छोटे-छोटे कमिटमैंट्स को पूरा नहीं करने पर लोगों ने जब उन प्रोजेक्टों को बन्द करना शुरू किया । एच0पी0सी0एल0 एक छोटा सा फैसला करने में एक-एक साल लगायेगी तो किस तरह से यह प्रोजेक्ट बनेंगे, इसके ऊपर भी चिंता करने की सख्त जरूरत है । एक लोकल एरिया डवेलपमैंट फंड जिसके तहत वर्ष 2011में पॉलिसी बनी । उस पॉलिसी में यह था कि ऑफ्टर जनरेशन उसमें बिजली का जो भी प्रॉफिट होगा, जो पॉवर बनाने वाली कम्पनी और सरकार जिनको 12% रॉयल्टी मिलेगी, उसमें से 2% प्रभावित क्षेत्र के लोगों को डायरैक्ट कैश के रूप मे देने का प्रावधान था । परन्तु साल 2011में भी इसको इम्पलीमैंट नहीं किया गया । आज साल 2015भी आ गया, लेकिन इम्पलीमैंट नहीं किया गया । ये कहेंगे कि यह मामला कोर्ट में है । कोर्ट की तरफ से कोई भी स्टे नहीं है । कोर्ट की तरफ से यदि कोई भी स्टे नहीं है तो फिर इसको देने में क्या दिक्कत है? आज लोगों में अगर रोष है तो इस बारे मे है कि हमने अपना पानी, जमीन, जलवायु दे दी परन्तु जो पॉलिसी हमारे

फायदे के लिए, प्रभावित लोगों के लिए बनी थी, वह पैसा हमें नहीं दिया जा रहा है। तो मेरा सरकार से विनम्र आग्रह रहेगा कि जो 2% पॉवर बनाने वाली कम्पनी ने और सरकार ने देना है, यह तुरन्त जितने भी हमारे बड़े-बड़े पॉवर प्रोजैक्ट्ज़ हैं, उनसे दिला कर इफैक्टिड इलाकें के लोगों को यह बांटा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बढ़िया, संतुलित तथा दूरदर्शी बजट पेश किया उसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। आपने समय दिया आपका धन्यवाद।

अध्यक्षः अब श्री जगजीवन पाल, मुख्य संसदीय सचिव चर्चा में भाग लेंगे।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

एस0एल0एस0 द्वारा जारी ---

26.03.2015/1240/sls-jt-1

श्री जगजीवन पाल (मा० मुख्य संसदीय सचिव) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह जी ने जो 16-2015 का बजट यहां पेश किया है, आपने मुझे उस पर बोलने का समय दिया है। मैं इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे पहले इस सरकार ने आपने दो बजट पेश किए हैं और इस बार आपने जो बजट पेश किया है वह 18वीं बार किया है। इस बजट के पढ़ने के बाद लगता है कि आपका जो अनुभव है वह इस किताब में झलकता है। आपने समाज के हर वर्ग को कवर करने की कोशिश की है, उन्हें सुविधाएं देने की कोशिश की है और हर विभाग को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। साथ ही मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद भी करता हूं कि हमारे विधायकों की ,जो सदन के सदस्य है, उनकी निधी 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 70 लाख रुपये कर दी है। यह काबिले तारीफ है। मैं आपको इसकी बहुत-बहुत बधाई देता हूं। इस बजट में आपने कोशिश की है कि जो 2012 में चुनाव हुए, उसमें जो कांग्रेस का घोषणा-पत्र था, उसको लगभग पूरा करने की, उसमें किए वायदों को पूरा करने की आपने कोशिश की है। जैसे कंट्रैक्ट कर्मचारी या अध्यापक हैं, उनको 5 साल में पक्का करने का वायदा किया था। इसी तरह के कई उदाहरण हैं। मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन

वह वायदे आपने इसमें निभाए हैं। इस तरह एक खुशी का संदेश हमारे कर्मचारियों और अध्यापकों में गया है। सबसे बड़ी बात यह हुई है कि इस बजट के आने के बाद, हमारे पत्रकार भाई यहां बैठे हैं ,हमारे विपक्ष के आदरणीय नेता पूर्व मुख्य मंत्री प्रो० प्रेम कुमार धूमल जी तथा विपक्ष के बाकी साथियों ने, जिन्होंने यहां कहा है, इसमें किसी को ऐसी आलोचना करने का अवसर नहीं दिया है। अख़बारों में भी जब आपने 18 मार्च को बजट पेश किया, उसके दूसरे दिन कोई ऐसी आलोचना नहीं आई जिसके ऊपर कोई ऐसी बात हो। सबने इसका स्वागत किया है जिसके लिए आप बधाई के हकदार हैं। जहां तक मैंने इस बजट को पढ़ा है, आपने मद नंबर 128 के ऊपर जो नेशनल अवार्डी हमारे अध्यापक हैं या जो स्टेट अवार्डी होते थे, पहले ये था कि सरकार उन्हें पैसे नकद देती थी। अब इसमें दो साल का सेवा में विस्तार

26.03.2015/1240/sls-jt-2

किया है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग में तो अध्यापक हैं लेकिन बाकी विभागों में भी ऐसी अवार्डी हैं। अगर उनको भी इस सुविधा में शामिल किया जाए तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा। इसके बाद आपने जो पिछले दो वर्षों में कार्य किए हैं, जिनका विवरण महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में आया है, उसमें जो थोड़ी-बहुत कमी रह गई थी वह इस बजट में पूरी की है। पूरे प्रदेश ने इसको सराहा है। लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि हमारे विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी के भाई इसकी सराहना क्यों नहीं करते। खासकर बिक्रम सिंह जी, आदरणीय सदस्य, आपस में ज्यादा बात कर रहे हैं। मैं एक निवदेन आपसे करना चाहता हूं कि जब आप बोले थे, आपने अपने विचार रखे थे तो हम भी उस वक्त गप्पें नही मार रहे थे। ...(व्यवधान)... बाहर चले गए थे या कहीं थे।

मुख्य मंत्री जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। 13 वें वित्तायोग ने जो हालात हमारे प्रदेश को ..

जारी ..गर्ग जी

26/03/2015/1245/RG/AG/1

श्री जगजीवन पाल(मुख्य संसदीय सचिव)-----क्रमागत

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि 13वें वित्तायोग ने जो हालात हमारे प्रदेश को दिए हैं और उसका जो सामना करना पड़ा,

उसके लिए चाहे कोई भी दोषी रहा है, लेकिन 13वें वित्तायोग में सरकार चलाने में मुश्किल आई है इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी सहमत हैं। लेकिन अब मैं मुख्य मंत्री महोदय को मुबारकवाद देना चाहता हूं कि 14वें वित्तायोग में जो आपने हिमाचल प्रदेश का पक्ष रखा और जो अधिकारी आपके साथ वहां गए थे उन्होंने भी वहां जो पक्ष रखा ,उस पश्चात 14वें वित्तायोग की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार टैक्स में 32से सीधे 42 प्रतिशत फायदा हमारे प्रदेश को हुआ है और इससे जनता में खुशी की लहर है। लेकिन उसके साथ ही जो केन्द्रीय बजट आया, हमें बहुत उम्मीद थी कि केन्द्रीय बजट में हमारे पहाड़ी प्रदेश को एक बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने वाला है , लेकिन कई स्कीमें तो ऐसी हैं मैं गिनूंगा नहीं जिनको सौ प्रतिशत ही प्रदेश सरकार पर छोड़ दिया और कह दिया है कि यदि आप इन्हें चलाना चाहते हैं, तो अपने स्रोतों से चलाओ और यदि नहीं चलाना चाहते, तो इन्हें बन्द कर दें। इससे हमारे प्रदेश को नुकसान हुआ है। जिन स्कीम या योजनाएं में 90:10 या 85:15 के रेश्यो के हिसाब से केन्द्र सरकार से पैसा मिलता था जिनमें 10या 15 प्रतिशत का शेयर प्रदेश सरकार को देना होता था ,वे बन्द हो गईं। योजना अयोग के साथ प्रदेश के मुख्य मंत्रियों/ वित्त मंत्रियों की एक मीटिंग होती थी जिसमें प्रदेश का पक्ष वहां रखा जाता था , लेकिन इस बार वह मौका नहीं मिला। अब केन्द्रीय बजट में हमारी सारी योजनाओं को लगभग 50:50 के रेश्यो के हिसाब से कर दिया है। यह सोचने योग्य और गंभीर बात है। इसके ऊपर प्रदेश को चिन्तन करना पड़ेगा ,चाहे वे पक्ष के लोग हों या भारतीय जनता पार्टी के लोग हों।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक लोक सभा चुनावों की बात है। लोक सभा का चुनाव हुआ, ऐसी कोई बात नहीं, हार-जीत तो चलती रहती है। यह सही है कि हम चारों सीट लोक सभा की हारें हैं। भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे मुख्य मंत्री महोदय को कह रहे थे कि आपको तो त्याग-पत्र दे देना चाहिए था या आपको ऐसा करना चाहिए था ,वैसा करना चाहिए था। क्यों? आप लोग आज यह बात भी सुन लो कि आज तक हिन्दुस्तान में जितनी सरकारें हुई हैं।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आप बीच में डिस्टर्ब न करें।

26/03/2015/1245/RG/AG/2

श्री जगजीवन पाल(मुख्य संसदीय सचिव) : कोई बात नहीं उपाध्यक्ष महोदय, इनको आदत है और ये अपनी आदत से बाज नहीं आ सकते। ये मजबूर हैं। आपने कहा है, तो सुनो भी और सुनने का माद्दा रखो। तो मैं कह रहा था कि लोक सभा चुनावों से पहले प्रदेश में इन्होंने सबसे बड़ी बात क्या कही और प्रदेश के लोगों को इतने तरीके से गुमराह किया। आदरणीय पूर्व मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी और जितने ये विपक्ष की सीटों पर बैठे हैं ये प्रदेश की जिस सभा, गांव या अन्य किसी भी रैली में बोलते थे, तो कहते थे कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी और हिमाचल प्रदेश की सरकार दूसरे दिन चली जाएगी एवं हमारी सरकार प्रदेश में आ जाएगी। प्रदेश के लोगों को इन्होंने यह सपना दिखाया।)-- व्यवधान---(आपको पता लग जाएगा कि हम क्या चाहते हैं, सरकार मजे से चल रही है और खूब चल रही है, बजट पेश कर रहे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं। मैं आपका (विपक्ष की ओर इशारा करते हुए) जवाब देने के लिए यहां खड़ा नहीं हुआ हूं।-----जारी

एम.एस. द्वारा जारी

26/03/2015/1250/MS/AG/1

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव)जारी-------

इनके कार्यकर्त्ताओं की भी और ये जो भाई बैठे हैं ,इनकी जुबां और चाल दोनों बदल गई। इन्होंने दफ्तरों में जाकर अधिकारियों को धमकाना शुरू कर दिया कि दिल्ली में हमारी सरकार आ गई है और अब सोच लो क्या होगा। यहां भी उठा रहे थे। जब बजट भाषण पर ये बोल रहे थे, उस समय भी ये अधिकारियों को कह रहे थे कि आप लोगों ने देख लेना। परन्तु ये आदत से मजबूर हैं। (व्यवधान)भगवान बहुत बड़ी चीज है। फिर दिल्ली का चुनाव आया। ऐसा घमासान दिल्ली में चला कि इनको वहां मुख्य मंत्री का उम्मीदवार नहीं मिला। (व्यवधान) हम तो हारे हुए थे। हम नहीं सोच रहे थे कि हमारी सरकार दिल्ली में आएगी। हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ना था और चुनाव लड़ा। हमें तो उम्मीद थी कि हमारी सरकार नहीं बनने वाली है। (व्यवधान) रवि जी, आप अभी चुप रहिए, मैं आपके ऊपर भी बोलूंगा। (व्यवधान) मैं ढूंढकर लाउंगा और आपके पास पहुंचा दूंगा। आपने उसका ईलाज कर देना। दिल्ली में आदरणीय

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने उस वक्त 6-6 बैठकें और 6-6 रैलियां कीं और पैसे देकर लोगों को रैलियों में लाया गया। रामलीला मैदान में रैली के लिए लोग नहीं आ रहे थे। चार-चार सूट दिन में बदलना, चलो यह बात बाद में आएगी। साथ में मिश्रा जी बैठकें करते हैं और बोलते हैं कि 11 प्रदेशों के RSS के वर्करों दिल्ली आ जाओ। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री, राजस्थान के मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री और सारे प्रदेशों के मुख्य मंत्री दिल्ली पहुंच गए। सारे मंत्री दिल्ली में, सारे विधायक दिल्ली में और जब नॉमिनेशन्ज हो रही थीं तो मुख्य मंत्री का कण्डीडेट आपको नहीं मिल रहा था। उस वक्त कहीं से रिटायर्ड आई0पी0एस0 अधिकारी श्रीमती किरण बेदी जी को ढूंढकर लाए। उस वक्त शत्रुघ्न सिन्हा जी का पता है क्या बयान आया? दिल्ली के लोगों को मुख्य मंत्री चाहिए थानेदार नहीं चाहिए। उसके बाद मनोज तिवारी जो इनके एम0पी0 है उन्होंने भी कहा कि दिल्ली वालों को थानेदार नहीं चाहिए और उसके बाद साबित हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब चुनाव चल रहे थे तो 2 00.बजे ऐसी हड़कम्प मची, पता नहीं क्या हो गया और मिश्रा जी ने तुरन्त मीटिंग बुलाई। उन्होंने कार्यकर्त्ताओं को कहा कि भाइयो, फटाफट एक काम करो। जहां अमीर लोग हैं ,जिनकी यह पार्टी है तो जिन्होंने वोट नहीं डाले हैं, उनको कहो कि वोट डालें नहीं तो पार्टी हार रही है।

26/03/2015/1250/MS/AG/2

श्री रिखी राम कौंडलः ऐसा कहां लिखा है?

श्री जगजीवन पालः अखबारों में ऐसा लिखा था। उस दिन टी0वी 0में भी आया और आपने भी देखा और सुना है लेकिन आप बहरे बन रहे हैं। फिर शाम को चर्चा आ गई और वहां बहस शुरू हो गई कि देखो 2.00 बजे के बाद वोट बी0जे0पी0 को पड़े हैं। हम जीतेंगे भी। जिस दिन परिणाम आए तो मेरे ख्याल में ,(व्यवधान) क्या हुआ क्लीन बोल्ड। (व्यवधान) हमने तो मानकर रखा था कि हमारी सीटें नहीं आएंगी। अब मैं बोलता हूं। आप हमारे मुख्य मंत्री का इस्तीफा चार सीटों को हारने की वजह से मांग रहे थे । अब मैं मांगता हूं कि प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। आपने दिल्ली की सातों सीटें हारी और वे सीटें जो 8 9-महीने पहले जीती थीं। इस बारे में चिन्तन करो और अपनी जुबान सुधारो। (व्यवधान) सुनो, मैं आप लोगों की बातों का जवाब देने वाला नहीं हूं। (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं।

Deputy Speaker: Please be quiet. Let him speak.

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

26.3.2015/1255/जेटी/जेके/1

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव)---:जारी------
उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद यह साबित हो गया और मैंने कह दिया।

Shri Rikhi Ram Kaundal: Sir, he should speak on the budget and not make a political speech.

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव): क्या आपने इस बजट बुक पर ही बोला? ---(व्यवधान)----आप अपना पढ़ लीजिए। अब इनकी सोच देखो। बंगलुरू में मीटिंग शुरू हो गई है। अब आर.एस.एस. ने चिन्तन शुरू कर दिया है। केन्द्र सरकार 10 महीने में ही बदनाम हो गई। इसकी जो मशूहरी थी वह गिर रही है। अब बिहार में देखो वहां पर भी इनका यही हाल होगा। इन्होंने मांझी को वहां पर मरवा दिया। उनके साथ केवल तीन आदमी रह गए। ये कहते रहे कि हम तुम्हारा साथ देंगे। मैं थोड़ा सा पीछे इतिहास में जाना चाहता हूं। वर्ष 1925 में आर.एस.एस. बनी और उसके बाद 1952 में जनसंघ बनी। हमारी आदरणीय सदस्या, श्रीमती आशा कुमारी जी ने कहा कि दिल्ली में यह पूंजीपतियों की सरकार है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जनसंघ पूंजीपतियों की पार्टी थी। वर्ष 1977 में एक गलती हुई। ---(व्यवधान) ----उपाध्यक्ष महोदय क्या मैं बैठ जाऊं।

Shri Ravinder Singh: Sir, on a Point of Order.

उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य प्लीज आप बैठ जाएं। What is your Point of Order.
श्री रविन्द्र सिंह जी आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री रविन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2015-16 के बजट अनुमानों के ऊपर चर्चा है। यह कोई राजनीतिक भाषण तो नहीं है। इशारों में हमने कह दिया और इशारों में

चल भी जाता है। लेकिन अभी तक एक भी शब्द बजट में इन्होंने नहीं बोला है। यह राजनीतिक भाषण है या बजट के ऊपर बोल रहे हैं। इशारों-इशारों में सब कुछ होता है। ---(व्यवधान)----

26.3.2015/1255/जेटी/जेके/2

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य आप बैठ जाएं। आपके सदस्यों ने भी यहां पर आर.एस.एस. के बारे में चर्चा की है। They have also the right to rebut it. आप कह रहे हैं कि माननीय सदस्य ने आर.एस.एस. के बारे में चर्चा की है। आप लोग बैठिए। ---(व्यवधान)----

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने माननीय सदन से बहिर्गमन किया)

संसदीय कार्य मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, ये मैच देखना चाहते हैं इसलिए सदन से जाना चाहते हैं।

उपाध्यक्षः जो प्वाईन्ट ऑफ ऑर्डर माननीय सदस्य, श्री रविन्द्र सिंह रवि जी ने यहां पर रखा है। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि इससे पूर्व वक्ताओं ने और इनके माननीय सदस्यों ने भी आर.एस.एस. के बारे में चर्चा की है इसलिए पक्ष के लोगों को भी बोलने का पूरा मौका मिलना चाहिए।

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को बड़ी तकलीफ हुई है। हमारे ऊपर जब कहते हैं तो इनको तकलीफ नहीं होती है। मैंने कहा था कि मैं सच बोलूंगा और अगर आपको कड़वी लगेगी तो बैठे रहना। लेकिन भाग गए। वर्ष 1952 में जनसंघ बना और उसके बाद जनता पार्टी बनी। वह हमारे देश की सबसे बड़ी भूल हुई। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह जी ने इनको जनता पार्टी का नाम दिया। 1980 में इन्होंने बी.जे.पी. का नाम रखा। लेकिन इनको गांवों में बढ़ने का मौका मिला। जहां तक काले धन का सवाल है। काले धन के ऊपर इनको वोट मिले। काले धन के ऊपर दिल्ली के चुनाव में अमित शाह जी पहले बोलते थे कि 15-15 लाख

रूपया हम एक-एक व्यक्ति के खाते में डालेंगे। वहां पर हजारों करोड़ों रुपया स्विस बैंक में पड़ा हुआ है। वहां अगर पैसा पड़ा है और इतना शोर आप लोगों ने मचा के

26.3.2015/1255/जेटी/जेके/3

रखा है जो विदेशों में धन भेज रहे हैं क्या वे नालायक हैं? आप लोग बोलते रहेंगे और क्या वे वहां पर अपने खातों में पैसा छोड़ कर रखेंगे या और जमा करेंगे?

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

26.03.2015/1300/SS-AG/1

श्री जगजीवन पाल, मुख्य संसदीय सचिव क्रमागतः
वे अपने खातों में रख छोड़ेंगे वहां या और जमा करेंगे? इनका इंतजार करेंगे कि इन्होंने आना है और हमारा काला धन पकड़ना है। हम सच बोलते हैं। लोग इनके भ्रम में आ गए कि शायद 15 लाख दे देंगे, इनको वोट दे देते हैं। हम सच बोलते हैं कि वह एक जुमला था। एक मज़ाक था। ये हिन्दुस्तान के लोगों को गुमराह करने वाले हैं। उनको अनपढ़ समझते हैं कि यह एक जुमला था। उसके बाद हमारे केन्द्रीय वित्त मंत्री, अरूण जेटली जी कहते हैं कि एक उदाहरण था और आदरणीय प्रधान मंत्री, मोदी जी बोलते हैं कि मुझे नहीं पता। भाषणों में तो मैंने कहा दिया कि मुझे ही नहीं पता। मन की बात में कहा मुझे नहीं पता वहां कितना धन है। वहां है कितना? आज इंतजार कर रहे हैं जन-धन योजना का। आज लोग इंतजार कर हैं। लोगों से उधार लेकर उन्होंने खाते खुलवा दिए। वह योजना भी फेल है। वे देख रहे हैं कि एक लाख रुपया कब आयेगा।

Deputy Speaker: Please wind-up now.

श्री जगजीवन पाल, मुख्य संसदीय सचिवः वाइंड अप कर रहा हूं। उसके बाद दिल्ली के चुनाव में प्रधान मंत्री जी कहते हैं जब पैट्रोल-डीज़ल के रेट नीचे आते हैं तो किस्मत वाला। आजकल जब केन्द्रीय बजट सवेरे पेश किया तो तीन-चार बजे तक पैट्रोल-डीज़ल के दाम तीन-साढ़े तीन रुपये बढ़ गए। यह क्या है? फिर किस्मत

वाला कहां गया? इसके बाद आजकल एक नई टिप्पणी आई है। जहां राम जेठमलानी जी बड़े सीनियर वकील हैं। उनकी उम्र भी काफी हो गई है। वे कहते हैं कि आदरणीय प्रधान मंत्री, मोदी जी विष्णु अवतार हैं। अरे, यह क्या हो गया है इनको? अगर विष्णु जी का अवतार हैं तो यह जो आजकल नुकसान हो रहा है, फसलों का नुकसान हो रहा है, ये जो ओले पड़ रहे हैं, विष्णु भगवान् तो ऐसे उंगुली उठाते थे तो सब कुछ रोक देते थे। उन्होंने यह क्यों नहीं रोका? बारिश रोक देते थे। ये कौन-से विष्णु आ गए? कौन-सा अवतार हो गए? यह हो क्या गया इनको? उसके बाद श्लोक सोचते रहे कि विकास पैदा होगा। विकास पैदा होगा। अरे, नौ महीने हो गए। एक गाय भी बछड़ा या बछड़ी देती है तो 10 किलो दूध मालिक को मिलना शुरू हो जाता है और उसको पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन नौ महीने के बाद भी कुछ नहीं आया। भैंस 10 महीने के बाद बच्चा देती है। अब 10 महीने भी मई में पूरे होने

26.03.2015/1300/SS-AG/2

वाले हैं। कोई उम्मीद नहीं है कि उसमें भी कोई कटड़ा या कटड़ी पैदा होगी और कोई दूध आयेगा। वह भी मुश्किल है।

आजकल साधु-साध्वी को पता नहीं क्या हो गया है। पहले तो साक्षी महाराज जी का बयान आ गया। वे एम0पी0 हैं। उनका बयान आ गया कि चार लड़के पैदा करो, लड़कियां नहीं। प्रधान मंत्री जी बोलते हैं बेटी है अनमोल। साक्षी जी क्या बोलते हैं? साक्षी जी महाराज बोलते हैं कि चार लड़के पैदा करो। एक बॉर्डर में जायेगा। एक आर0एस0एस0 में जायेगा। एक कहीं और जायेगा और एक माता-पिता की सेवा करेगा। लड़कियां कोई नहीं। उसके बाद एक साध्वी दिल्ली में आती है। वह भी मंत्री है। वह कहती है कि दिल्ली में सरकार बनेगी वह या तो आरामजादों की बनेगी या हरामजादों की बनेगी। अरे ये क्या है? इनको क्या हो गया है? अब एक और साध्वी बोलती है कि एक हिन्दुस्तान परिवार में एक महिला दस-दस बच्चे पैदा करे। आपने भगवां कपड़े डाल लिये हैं पहले इनको उतारो, एग्जैम्पल पेश करो। अच्छे कपड़े डालो। शादी करो। फिर दस बच्चे पैदा करके बताओ पहले। हमारी देश की महिलाओं को क्या बच्चे पैदा करने की फैक्टरी समझ लिया? इतना अपमान!

Deputy Speaker: Please wind-up now.

श्री जगजीवन पाल, मुख्य संसदीय सचिवः उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट में वाइंड अप कर रहा हूं। मेरे ख्याल में अब सत्ता पक्ष से एक-आध वक्ता ही बोलने के लिए शेष होगा, इसलिए मुझे और टाइम दे दीजिए। मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं। सच कह रहा हूं। मनरेगा के ऊपर इनके जो कार्यकर्ता चुनाव में गए, ये (विपक्ष) सारे उठकर बाहर चले गए, इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 100 दिन किया है हम 200 दिन करेंगे।

जारी श्रीमती के0एस0

/1305/26.03.2015केएस/एजी1/

श्री जगजीवन पाल ,मुख्य संसदीय सचिव जारी--
हम 200 दिन करेंगें। हम मनरेगा में ये करेंगें, वो करेंगें। एक साल इनकी सरकार का होने वाला है। मनरेगा में गांव की महिलाओं का जो हाल है, हाथ पे हाथ धर कर वे बैठी हैं, जब हम गांव में जाते हैं तो वे हमसे पुकार करती हैं कि हमें मनरेगा में लगाओ। अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आने वाले है। प्रधान मंत्री जी रैलियों में कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं लेकिन अच्छे दिन चले गए। मैं भारतीय जनता पार्टी के भाईयों को भी कहना चाहता हूं और उनके वर्करों को भी और इनके प्रधान मंत्री जी को भी कहना चाहता हूं कि जो भाषण उन्होंने लोकसभा में दिया है, बड़ा ललकार कर भाषण दिया है कि मैं राजनीतिक सूझबूझ रखता हूं, मनरेगा को बन्द करने वाला नहीं हूं। मैं कांग्रेस का मकबरे का ढोल 60 सालों का पीटता रहूंगा। उन्होने लोकसभा में यह भाषण दिया है और अगर हिम्मत है तो यहां आकर जनता में एक बार तो कहो कि हम मनरेगा को बन्द कर देंगें और मनरेगा गलत है। अगर उस सभा में एक आदमी भी बैठा रह जाएगा तो मेरा नाम बदल देना, हम राजनीति छोड़ देंगें। मन की बात ये रेडियो में ही करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मदर टेरेसा के ऊपर जो टिप्पणी की है वह निन्दनीय है। उन्होने गरीब लोगों के लिए क्या नहीं किया? उनके ऊपर जो टिप्पणी की है, एक समुदाय को जो चोट पहुंचाई है वह निन्दनीय है। रिटायर्ड जस्टिस काटजु ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में जो टिप्पणी की है, आप सभी लोगों ने पढ़ा

होगा। अरे, यह क्या हो रहा है। एक रिटायर्ड जज महात्मा गांधी जी को कहता है कि वे अंग्रेजों के एजैंट

/1305/26.03.2015केएस/एजी2/

थे। अरूण जेटली जी लन्दन गए थे वहां उनकी मूर्ति का अनावरण करके आए हैं । सारे संसार में उनका मैसेज है लेकिन ये आज कहते हैं कि नत्थू राम गोडसे के मंदिर बनाओ और प्रधान मंत्री जी उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करते । यह क्या है? आज हमारे कुछ वर्ग में एक भय सा पैदा हो गया है। चर्चों और मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं । ये इन्हीं के राज में क्यों हो रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी यू.पी.ए. की सरकार के समय में किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छा भूमि अधिग्रहण बिल पास किया गया था। क्या जरूरत थी उसको बदलने की। आज बंगलूरू में जा कर कार्यकारिणी फैसला करती है कि पूरे देश में छा जाओ, आर.एस.एस. के कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं कि लोगों को जाकर, किसानों को जा कर समझाओ कि हम तो आपकी भलाई के बारे में बिल पास कर रहे हैं। आपने जमींदारों का भट्ठा बैठा कर रख दिया है और आप जिन

अन्ना हज़ारे जी के कंधे पर चढ़कर ऊपर आए हैं उन्होंने भी भूमि अधिग्रहण बिल के विरुद्ध आन्दोलन जारी कर दिया है जो कि पूरे देश में होगा।

उपाध्यक्ष :माननीय सदस्य, अब वाइंड अप करिए।

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव) :उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि भूमि अधिग्रहण बिल को वापिस लिया जाए जैसा यू.पी.ए. की सरकार ने पास किया था उसको वैसी ही शक्ल में रखा जाए। रविन्द्र रवि

/1305/26.03.2015केएस/एजी3/

जी मेरे अच्छे पड़ौसी है, मेरे मित्र है, इन्होंने यहां पर क्या कहा? ये बहुत ही शालीन व्यक्ति थे । मैं 1987 में वाईस चेयरमैन बन गया था और ये 1993 में नौ सौ कुछ वोटों

से जीतकर थुरल क्षेत्र से विधायक बने थे। जब भी ये हमें मिलते थे, बड़ी शालीनता से मिलते थे । इनकी दुकान थी ये हमें जरूर चाय का कप पिलाते थे। इनमें वह शालीनता खत्म हो गई है। यह बात ठीक है कि खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। अब ये सत्ता में पांच बार जीतकर यहां पर आ गए हैं । मेरा और इनका ससुराल एक ही गांव में हैं मगर पता नहीं अब ये शालीनता क्यों भूल गए हैं? ये एक दिन यहां

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

26.3.2015/1310/jt/av/1

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव)जारी----------

एक दिन तो यहां मुख्य मंत्री जी को बोल रहे थे कि आप सीमा में रहो। मैं यहां खड़ा हुआ और मैंने कहा कि आप क्या मुख्य मंत्री जी को धमका रहे हैं? आप मुख्य मंत्री जी को यह बोलने वाले कौन होते हैं कि सीमा में रहो। परसों दूसरी बार फिर हुआ। जब मैं खड़ा हुआ तो मुझे हाथ से बैठने के लिए इशारा करने लगे कि बैठ जा, बैठ जा। मैं यह कहने लगा कि क्या आपने शालीनता खत्म कर ली। क्या आपको घमण्ड हो गया है ,मैं कोई बन्धवा मजदूर हूं? मैं यहां चुनकर आया हूं। अगर हाथ से भी इशारा करना हो तो वह भी शालीनता से करना चाहिए। हाथ को ऐसे, ऐसे हिलाकर करना कि बैठ जा, बैठ जा; ठीक नहीं है। हम कोई बन्धवा मजदूर है या दास है। बैठ जा ,बैठ जा; यह क्या है? मैं भी अपने पक्ष के भाइयों से कहना चाहता हूं कि जब विपक्ष से कोई सदस्य बद्तमीजी करता है तो उसको शालीनता से हाथ हिलाकर चुप रहने के लिए बोलें। आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। इनकी तरह हाथ मत हिलाना , यह बद्तमीजी है। जैसे मैंने कहा कि खुदा जब आभूषण देता है तो नजाकत आ ही जाती है। वह नजाकत इनको भी आ गई है।

यहां पर सी.एफ.एल. बल्ब के बारे में बड़े जोर-शोर से कहा गया कि हमने सी.एफ.एल. बल्ब बांटे। मगर आज किसी भी घर में वह सी.एफ.एल. बल्ब नहीं है। खराब होने पर जैसे वे फेंके गये हैं उसके परिणाम आने वाले समय में पता चलेंगे। खराब होने पर एक विधि है कि उसको दबा दिया जाए। दबाने के बावजूद भी उसका हमारे पर्यापरण पर असर पड़ सकता है। मगर उसका इन्होंने कोई इन्तजाम नहीं किया। इसके अतिरिक्त इन बल्बों को देने के लिए लोगों से जो इन्होंने चार-चार

जलते हुए बल्ब लिए उनका क्या हिसाब है? वैटेरनरी फार्मासिस्ट लगा दिए जिनको बिल्कुल तुजुर्बा नहीं है। उसके बारे में हमारे मंत्री श्री अनिल शर्मा जी ने कल जवाब दिया है। इसके अतिरिक्त नशा माफिया की बात आती है। मैं शराब के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। जब से धरती है उस पर सुर-आसुर भी तभी से हैं। इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि जब भारत आज़ाद नहीं था तब भी शराब थी।

26.3.2015/1310/jt/av/2

मगर खनन माफिया, वन माफिया और चर्स माफिया; ये सारी मुश्किलें हमारे लिए भी हैं, इनके लिए भी हैं तथा इस समाज के लिए भी हैं। मगर ये सभी चीजें इनके पिछले 5 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा पनपी हैं। आज हमारी सरकार के लिए भी एक चुनौती हो गई है। जैसे पंजाब में नौजवानों के साथ हो रहा है, नौजवान नशा कर रहे हैं, उनका बुरा हाल है। ऐसा न हो कि हमारे प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति आए। मैं मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि इस बारे में पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जाए। काला सोना माफिया के ऊपर शिकंजा कसा जाए। आपने कसा है मगर और ज्यादा कसा जाए। इनके कार्यकाल में यह पनपा है। यहां हमारे एक साथी खनन माफिया पर बोल रहे थे। हमारे यहां न्युगल खड्ड पर एक नौण नामक जगह है। वहां एक-एक दिन में 20-20 लाख रुपये का खनन होता है। उसमें कौन व्यक्ति थे? वह व्यक्ति जो इस वक्त चले गये और उस वक्त वहां के मंत्री थे। वे लोग उन मंत्री के हितैषी थे। आज वे लोग चले गये हैं लेकिन हमारे लोग बोलते हैं कि इन्होंने अपने समय में लोगों को रेत-बजरी से लखपति/करोड़पति बना दिया, आप हमें कानून के दायरे में क्यों ला रहे हैं? आज हमारे लिए ही मुश्किल हो गई है। उनको कैसे रोकें?

आज कश्मीर में क्या हो रहा है? इनको कुर्सी की इतनी ज्यादा भूख है? वहां पर जब मुफ्ति मोहम्मद सईद और उनकी केबिनैट ने शपथ ली तो हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी वहां बैठे थे, आदरणीय आडवाणी जी वहां बैठे थे। आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी वहां बैठे थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि कश्मीर में जो चुनाव हुआ है इसको पूरा व सफल करवाने में पाकिस्तान, हुर्रियत और उग्रवादियों का हाथ है। उन्होंने यह नहीं कहा कि हमारा इलैक्शन कमीशन, फौज, पुलिस और दूसरे अधिकारियों ने यह सफल चुनाव करवाया है। चाहिए तो यह था कि हमारे

प्रधान मंत्री उसी वक्त पहले की तरह कहते कि अगर वे दो काटेंगे तो हम चार काटेंगे। 56 ईंच का सीना चाहिए, वहां उस वक्त वह सब कुछ कहां छिप गया------

श्री बी.जे.नेगी द्वारा जारी

26.03.2015/1315/negi/ag/1

माननीय मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन पाल) ..जारी..

चाहिए तो यह था कि उसी वक्त, प्रधान मंत्री जैसे पहले भाषण देते थे अगर वो दो काटेंगे तो हम चार काटेंगे, 56 इंच का सीना चाहिए। लेकिन उस वक्त वहां क्या हो गया? चाहिए तो यह था कि उसी वक्त अडवाणी जी भी उठते, प्रधान मंत्री जी भी उठते, मुरली मनोहर जोशी जी भी उठते और पी.एम.ओ में जो मंत्री हैं, वह भी उठते। उसी वक्त वे वहां से छोड़ करके जाते तो देश को एक मैसेज़ जाता कि वाकयी ये कुर्सी के भूखे नहीं हैं। बाद में फिर आप एक कमेटी बना रहे हैं, जब उन्होंने एक कैदी/उग्रवादी को छोड़ दिया, मसरत आलम को छोड़ दिया। उसके बाद जागना शुरू किया और ब्यान देने शुरू कर दिये। लेकिन उसको दोबारा पकड़ नही सके। आप फिर उनके साथ समझौता करके बैठे हुए हैं जिन्होंने यह हालात पैदा किए हैं। अंत में, मैं यह कहते हुए कि हमारे रिटायर्ड जनरल, रिटायर्ड चीफ ऑर्मी ऑफ स्टॉफ, विदेश राज्य मंत्री श्री वी.के.सिंह पाकिस्तान में चले गए, पाकिस्तान के एम्बेसी में चले गए। जब आलोचना हुई तो कहने लगे यह तो मेरी मजबूरी थी । अगर मजबूरी थी तो फिर आप इस्तीफा दो, आप तो फौज़ी हो। आप तो लड़ने वाले व्यक्ति हो। कहते हैं कि स्व0 इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री थी और उन्होंने 1971 में जब जंग जीता था और 93 हजार पाकिस्तानी फौजियों अरेस्ट किया था तब उनको आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी यह कहा था कि यह तो दुर्गा की रूप है। यह कह रहे हैं कि उन्होंने रिवाज़ डाला था। अगर उन्होंने रिवाज डाला था तो आप तो उनके नाम की सारी योजनाओं के नाम अलग रख रहे हैं। आप उनके परिवार से संबंधित लोगों की योजनाओं को बदल रहे है। और इसके लिए इंदिरा गांधी जी के पद चरणों पर चलने की आपको क्या जरूरत पड़ी ? देश का सिर झुका दिया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और बजट के ऊपर मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पटवारी उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के लिए 1000 रूपये मिलता था उसको बढ़ा करके 3000 रूपये किया है।

करूणामूलक आधार पर नौकरी लगने के लिए पहले आय सीमा 75 हजार रूपये थी उसके बाद इसको 1.25 लाख रूपये किया ..

26.03.2015/1315/negi/ag/2

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य प्लीज़ समाप्त कीजिए।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन पाल) : उपाध्यक्ष महोदय ,और उसके बाद अब 1.50 लाख रूपये किया है उसके लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय को मुबारक देना चाहता हूं। जहां तक होर्म गार्डज की दिहाडी का सवाल है इसको 260 रूपये से बढ़ा कर 280 रूपये कर दिया है। हमारे बेलदारों की दिहाडी चाहे वे आई.पी.एच. में हों, पी.डब्ल्यू.डी. में हों और चाहे किसी भी विभाग में हों उनकी दिहाड़ी 180 रूपये कर दी गई है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है कि अनुबन्ध कर्मचारियों को नियमित करने के लिए जो हमने 5 साल का वायदा किया था उसको हमारी सरकार ने पूरा करके 5 साल कर दिया है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को मुबारक देता हूं। इसी के साथ एक बात कहते हुए,

हे भाजपा वालो, अब तो दस महीने होने वाले हैं, अरे यह तो बता दो कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं, अच्छे दिन कब आने वाले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष :अब इस मान्य सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए अपराह्न 2.20 बजे तक स्थगित की जाती है।

* * *

26/1430/03.2015.यूके/1

(माननीय सदन की बैठक 2 बज कर 30मिनट पर पुनः आरम्भ हुई ।)

Speaker: Now, we continue with the discussion.

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री जगजीवन पाल जी ने अपनी बात कहते-कहते, शायद मंशा उनकी यह थी कि जम्मू-कश्मीर के मुख्य मंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद हैं, उनका जिक्र करना था, जब जम्मू-कश्मीर में चुनाव हुए उसके बारे में, जिन्होंने एक बड़ी विवादास्पद टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी का जिक्र करते हुए इनके मुंह से शब्द, मुरली मनोहर जोशी जी का आया है, जो कि रिकॉर्ड में आया है। उस रिकार्ड को आप देखें। उसमें अगर इस तरह से यह नाम इस प्रकार से आया है तो उसको करेक्ट करने जरूरत है।

श्री जगजीवन पालः यदि आया होगा तो निकाल देना। लेकिन मेरे कहने की मंशा यह थी कि जब जम्मू-कश्मीर के मुख्य मंत्री जी ने यह कहा तो उस वक्त मैने ये जो नाम लिए हैं, वे वहां बैठे थे। तो उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मुख्य मंत्री ने यह कहा था कि जो चुनाव हुआ है, यह पाकिस्तान हूर्रियत की वजह से शांतिपूर्वक हुआ है। उस बारे में मैने यह कहा है कि उनके सामने यह बात हुई है। तो उस समय उनको वहां से उसका बॉयकाट करना चाहिए था। वहां से यह मैसेज जाना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यह कहा है मैने। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। यदि यह शब्द आ गया होगा तो उसको निकाल दें। कोई बात नहीं, मैं गलती मान लेता हूं।

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष जी, मेरा सिर्फ यह कहना है कि यह चीज़ रिकॉर्ड में चली गयी है और उसको दुरूस्त करने की आवश्यकता है।

Speaker: The name of "***" may be deleted from the proceedings.

We are running short of time please. There are still five more Members to speak.

*** Expunged as ordered by the Chair.**

26/1430/03.2015.यूके/जेटी/ 2

मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी थोड़ा सा को-ऑपरेट कीजिए। कल भी रात के 8.30 बजे तक बैठे रहे। अब माननीय मुख्य मंत्री जी ने जवाब भी देना है। So,।

think, either we cut down the names or आप 5-5 या 10-10 मिनट बोलिए । And if somebody is speaking not less than half an hour, that makes no sense. Everybody has spoken and everybody knows what is the budget. If they want to speak, I will call them and after exactly 10 minutes, I will ask the Reporters not to record. Please don't mind it.

संसदीय कार्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हमारी सहमति है कि प्रत्येक सदस्य 1 10-0 मिनट बोलेंगे ।

Speaker: I have decided that if they don't stop, I will stop the recording. Please cooperate.

Now, Shri Bikram Singh Jaryal will start the discussion.

26/1430/03.2015.यूके/3

श्री बिक्रम जरियालः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो वर्ष 2015-16 का बजट दिनांक 8.3.2015 को इस माननीय सदन में 3 घंटे से ज्यादा का समय लगा कर पेश किया उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । यह बजट प्रदेश के हित में न हो कर कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के हित में ही प्रतुतत किया गया था। मेरे से पूर्व पहले आदरणीय जगजीवन पाल जी ने बोला । उसके बारे में मेरे साथी ये बात कर रहे थे कि ये बजट पर भाषण दे रहे हैं या यह देश और प्रदेश का भाषण दिया जा रहा है । तो मेरा मुख्यतः कहने का मतलब यह है कि बजट

एस0एल0एस0 द्वारा जारी --

26.03.2015/1435/sls-ag-1

श्री बिक्रम सिंह जरयाल... जारी

बजट के ऊपर बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए इन्होंने कशमीर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बातें रखीं। ये सच्चे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। बजट में ऐसा कुछ था ही नहीं कि ये बजट की बात करते। सत्तापक्ष के जो मेरे सीनियर लोग यहां

बैठे हैं, इन्होंने पूछा कि आप लोगों ने वॉकआऊट किसलिए किया? अध्यक्ष महोदय, हमने वॉकआऊट इसलिए किया क्योंकि ऐसी लगा कि सामने से कोई *** भाषण कर रहा है, इसलिए वॉकआऊट किया।

अध्यक्ष : आप तो बजट पर ही बोल रहे हैं न? आप बजट पर बोलिए।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल : जी। बजट में प्रदेश की जनता ने सोचा था और उम्मीदें लगाई थीं कि बजट जनता के हित में होगा। ...(व्यवधान)...

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव) :आपने मेरा नाम लेकर कहा है। मैं कहना चाहता हूं कि मैं नेशनालिस्ट हूं।...(व्यवधान)...

श्री बिक्रम सिंह जरयाल : इन्होंने तो प्रधान मंत्री तक का नाम लिया। जो लोग यहां पर नहीं हैं, उनकी भी नाम लिया। ...(व्यवधान)... इसमें क्या ऑब्जैक्शन है? मुरली मनोहर जोशी जी का नाम लिया गया, जो सदन में नहीं हैं। ...(व्यवधान)...इन्होंने स्पीच दी है, इसमें बुरी बात क्या है?

Speaker: I order to delete the words "***"। माननीय धूमल जी, आप कहिए।

*****अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।**

26.03.2015/1435/sls-ag-2

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सी.पी.एस. जब बोल रहे थे तो मैं अपने कमरे में बैठा सुन रहा था। किसी भी सदस्य को इन्होंने नहीं छोड़ा। मेरा भी नाम लिया। अगर किसी का नाम लेकर कहा जाए कि इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिया। हमने तो सोचा कि जिसकी जितनी सोच है, उतना ही बोलेगा। इसलिए इस तरह नाम आनें से डिलीट की बात क्यों? जब पहला वक्ता बोला, उसके बाद दूसरा बोला तो क्या वह उसका नाम नहीं लेगा। इसमें डिलीट क्या

होगा? या तो सारे नाम डिलीट करो, जिनके भी नाम लिए हैं। जो जगजीवन पाल ने नाम लिए हैं, let them all be deleted. हमें भी कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष : डिलीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिनकी रैफरैंस नहीं है। Musharaf is not here. Musharaf is nobody for us; no entity for us.

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : मैं भी यही कह रहा हूं कि जिनके नाम विद्आऊट रैफरैंस लिए हैं, वह भी सारे डिलीट किए जाएं।

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) : जगजीवन पाल जी का नाम विपक्ष चाहे जितनी बार ले, हमें खुशी होगी। आप लें। लेकिन सिर्फ़ मुशर्रफ के साथ जुड़ने पर ऐतराज़ था जिसे आपने डिलीट किया। इसके लिए हम आपके आभारी हैं।

Speaker: Shri Jaryalji, please continue.

श्री बिक्रम सिंह जरयाल : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जनता ने सोचा था कि जो बजट आएगा उससे उनको उम्मीदें थीं। पर उन सब उम्मीदों पर ,जब यह बजट भाषण पढ़ा गया ,तो पानी फिर गया। यह बजट दिशाहीन है। न ही ये मज़दूर वर्ग, कर्मचारी वर्ग, विधवाएं, महिलाएं, किसान, बागवानी आदि वर्गों के लिए सही है जो यहां पर 3 घण्टे पेश किया गया। प्रदेश अपने पावों पर खड़ा हो, अच्छा वीजन हो, प्रदेश का समूचा विकास हो, प्रदेश को अच्छा शासन मिले ,ऐसा न होकर केवल पुरानी बातों को पुराने बजट को तोड़-मरोड़ कर यहां पेश किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सड़क, महिला सुरक्षा, बागवानी, युवाओं को रोज़गार के साधन,

26.03.2015/1435/sls-ag-3

कोशल विकास भत्ता, एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., आई.आर.डी.पी. परिवारों के लिए हैल्थ योजनाएं, पैंशन, गृह निर्माण, मज़दूरों की दिहाड़ी, कर्मचारियों की कोई भी बात इस बजट में नहीं है। इस बजट में समूचे हिमाचलियों के हितों पर कुठाराघात हुआ है। बातें बड़ी-बड़ी पढ़ी गईं। मज़दूरों की दिहाड़ी 10 रुपये बढ़ाई जिससे एक कप चाय का नहीं आता। पैंशन 1.60 पैसे प्रतिदिन बढ़ाई और बताते हैं

कि हमने इतनी पैंशन बढ़ा दी। यह सब बिल्कुल गरीबों के हित में नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं और श्री जी.एस. बाली, माननीय मंत्री जी का कि ..

जारी.. श्री गर्ग जी

26/03/2015/1440/RG/JT/1

श्री बिक्रम सिंह जरयाल----क्रमागत

मैं श्री जी.एस. बाली, माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि कम-से-कम इन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का नाम लिया कि परिवहन के लिए तीन सौ करोड़ रुपये उन्होंने दिए हैं ,तीन गुणा बजट दिया है। माननीय मुख्य मंत्री जी का इसके लिए धन्यवादी हूं कि इन्होंने विधायक क्षेत्र विकास निधि पचास लाख रुपये से बढ़ाकर सत्तर लाख रुपये कर दी है। परन्तु मेरी सोच यह थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसको पचास लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि बीस लाख रुपये जो सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के लिए इस निधि में जरूर खर्च करने की शर्त लगाई गई है ,उसको untied money रखा जाए ताकि विधायक जहां मरजी उस पैसे को खर्च कर सकें। मेरा आपसे ऐसा अनुरोध रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से एक और निवेदन है कि जो हम बजट देते हैं चाहे वह एम.पी. लैड या डी.सी. हैड या किसी भी हैड से आता है जहां जिस विकास कार्य के लिए बजट दिया जाता है वह कार्य पूरा नहीं होता। जब हम अपनी निधि से पैसा देते हैं ,तो कंडीशन लिखी होती है कि आप 33 प्रतिशत से ज्यादा पैसा नहीं दे सकते। जबकि हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं ,हैड लोड बहुत होता है और इस 33 प्रतिशत से पूरा नहीं होता। इसलिए इस कंडीशन को भी हटाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा एक और अनुरोध रहेगा ,जैसे कि हमारे विधायक क्षेत्र विकास निधि में लिखा गया है कि डंगे, रिटेनिंग वॉल ,ब्रेस्ट वॉल नहीं होनी चाहिए ,अब हिमाचल तो एक पहाड़ी क्षेत्र है और जिला चंबा का तो आपको पता है कि अति दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है। वहां बर्फ पड़ती है,

भारी बरसात होती है ,स्लाइडिंग होती है, लोगों के घरों को खतरा होता है ,सरकारी भवनों को भी खतरा होता है ,सड़कों को खतरा होता है, कुहलों को खतरा होता है। इसलिए इस कंडीशन को भी हटा दिया जाए। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा एक विशेष अनुरोध और है कि विधायकों की ऐच्छिक निधि को दो लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया जाए। पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्य इसके लिए आपके बहुत आभारी रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आदरणीय विधायक श्री रणधीर शर्मा जी ने भी ठीक कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के पास कर्मचारियों का वेतन देने के लिए पैसा नहीं है।

26/03/2015/1440/RG/JT/2

पिछले कल जब मैंने अपने ब्लॉक में बी.डी.ओ. को फोन किया ,हमारे यहां बी.डी.ओ. एक महिला हैं उन्होंने कहा कि अढ़ाई करोड़ रुपये चाहे वह एम.पी., एम.एल.ए. या चाहे डी.सी. हैड या किसी भी हैड का है वह सभी, जितना भी पैसा था, हमसे ट्रेजरी में जमा करवा लिया गया। तो अढ़ाई करोड़ रूपये भटियात ब्लॉक से जमा हुआ है। यह बहुत शर्म की बात है कि प्रदेश के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है और यहां बड़ी-बड़ी डींगे मारी जा रही हैं कि हमने बजट में यह कर दिया ,वह कर दिया। सत्ता पक्ष के लोग यहां बड़ी-बड़ी बातें बजट के बारे में कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो जितने भी माननीय सदस्य वहां बैठे हैं वे भी अपने ब्लॉकों में फोन करके पूछ सकते हैं। हमने जो पैसे अपनी निधि से दिए थे आज लोग हमसे पूछते हैं कि वे काम क्यों नहीं हो रहे? हमने डी.सी. को शैल्फ बनाकर दे दिए ,पैसा विदड्रॉ हो चुका है, लेकिन वे काम कहां से होंगे? यह बहुत चिन्ता का विषय है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय जनता और प्रदेश के हित में आईन्दा ऐसा न किया जाए ,तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी।

अध्यक्ष महोदय, बजट के बारे में यहां जो डींगें मारी जा रही हैं ,बजट में 50 प्रतिशत हिस्सा निगम, बोर्ड आदि के जो वाईस चेयरमैन और चेयरमैन बनाए हैं उनकी जेबों में जा रहा है जबकि वह पैसा गरीबों की जेबों में जाना चाहिए। ऐसा बजट पेश किया गया है। आदरणीय बहन श्रीमती सरवीन चौधरी जी ने यहां ठीक कहा कि सारे निर्णय निगम और बोर्ड के चेयरमैन एवं वाईस चैयरमैन ले रहे हैं और

उन्हीं के ऊपर यह प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं ये 6-6 और 7-7 बार जीतकर आ चुके हैं----जारी

एम.एस. द्वारा जारी

26/03/2015/1445/MS/AG/1

श्री बिक्रम सिंह जरयाल जारी----------

ये लोग 6-6 और 7-7 मर्तबा यहां जीतकर आए हैं और मंत्री रहे हैं। मंत्री आप लोग नहीं हैं बल्कि जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं ,उनको मंत्री का पूरा ओहदा दिया हुआ है। पूरी शक्तियां उनको दी हुई है। अगर ऐसा नहीं है तो विधान सभा क्षेत्रों में जाकर देखिए उनके नाम की पट्टिकाएं लगी हुई हैं, आप विजिट कर सकते हैं। उद्घाटन वे करते हैं। स्कूलों में मार्च में पेपर होते हैं लेकिन स्कूलों में प्रोग्राम चल रहे हैं। वहां सभी अधिकारियों और स्टाफ को बुला लिया जाता है। दफ्तरों में कोई नहीं होता, दफ्तर खाली होते हैं जिससे जनता हताशा हो रही है। कर्मचारी अनावश्यक रूप से प्रोग्राम्ज में जा रहे हैं और गाड़ियों पर तेल खर्च किया जा रहा है। लेकिन उसका घाटा किसके ऊपर पड़ रहा है? हिमाचल प्रदेश की जनता के सिर से वह घाटा निकल रहा है। इसलिए मुख्य मंत्री जी से मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि इन चीजों का ध्यान रखें।

यहां ठीक कहा कि ट्रांसफर्ज हो रही हैं और उनके कहने पर हो रही हैं। पट्टिकाओं की भी यहां बात चल रही थी। कल राकेश कालिया जी ने ठीक कहा कि विधायकों के नाम उन पट्टिकाओं पर नहीं लिखे जाते। हमारे समय जब प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी मुख्य मंत्री थे, उस समय विपक्ष के विधायकों के भी पट्टिकाओं पर नाम लिखे जाते थे। उसका प्रूफ आज भी मेरे पास है। मुख्य मंत्री जी के नाम के साथ श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी का नाम लिखा हुआ है। वह उद्घाटन किशन कपूर जी ने किया था लेकिन वहां विधायक का भी नाम लिखा है। वह विपक्ष के विधायक थे फिर भी हमारी पार्टी इतनी संस्कार वाली है कि विपक्ष के स्थानीय विधायक का वहां पर सभी जगह पट्टिकाओं में नाम लिखा हुआ है। आज जब मुख्य मंत्री जी का कोई प्रोग्राम हमारे क्षेत्र में होता है तो हमें चिट्ठी तक नहीं भेजी जाती। किसी अधिकारी या एस0डी0ओ0 ने हमें चिट्ठी तक नहीं भेजी कि मुख्य मंत्री जी आ रहे हैं।

अध्यक्षः आप क्या बजट पर बोल रहे हैं?

श्री बिक्रम सिंह जरयालः जी, सर बजट पर ही बोल रहा हूं।

अध्यक्षः आपको बोलते हुए 10-15 मिनट हो गए हैं। आपने स्वयं डिसाइड किया था। फिर मैं सारा डिलीट कर दूंगा।

26/03/2015/1445/MS/AG/2

श्री बिक्रम सिंह जरयालः और वे जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं, आज वे रेड बत्ती वह भी फ्लैशर वाली लगाकर घूम रहे हैं और उनके आगे पायलट चली होती है। जब विधायकों को बत्ती देने की बात आती है तो मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि कोर्ट के आदेश हैं। उनके लिए क्या कोई कोर्ट नहीं है? उनके लिए क्या कोई कानून नहीं है? इसलिए मेरा थोड़ा सा अनुरोध रहेगा कि उनके ऊपर थोड़ी लगाम कसी जाए। उनको कहें कि जो कार्य उनको दिए हैं, उन्हें करें, नहीं तो अगली बार जो विषय आपको दिया है उसमें भी फेल हो जाओगे। उनको बताओ कि अपने विषय पर ध्यान दें।

Speaker: Kindly wind up in two minutes.

श्री बिक्रम सिंह जरयालः मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का, शिक्षा का, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। मेरे पास बहुत लम्बी लिस्ट पड़ी है। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी चाहें तो मैं इनको लिखकर दे सकता हूं। पुलिस, एस0डी0एम0, फॉरैस्ट, आई0पी0एच0 और पी0डब्ल्यू0डी0 के जितने भी कर्मचारी हैं, ठेकेदार जितने भी लगाए हुए हैं सिर्फ वे पैसा वसूलने में लगे हुए हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में चुवाड़ी में एक एस0डी0ओ0 मि0 परमार थे। वह पी0डब्ल्यू0डी0 का काम रात को 12.00 बजे तक करवाते थे। उस एस0डी0ओ0 की बदली करवा दी। उसके चहेते ठेकेदार बोलने लगे कि विभाग में हमसे भी पैसे मांगे जाते थे कि हमें पैसे दो। लेकिन हम पैसे कहां से देते? वह एस0डी0ओ0 तो हमें एक पैसा भी बचाने नहीं देता था। उसकी बदली करवा दी और अब जो एस0डी0ओ0 लगाया है ,यहां बड़े अधिकारी लोग बैठे हैं। उसने तारकोल तक बेच दिया और

उसके साथ जो असैसरीज आती थी, वह भी बेच कर खा ली और प्रशासन सोया रहा। पिछली बार मैंने ENC, चीफ इंजीनियर, एस0ई0 और XEN से भी बात की थी। लेकिन उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। बजट देते भी हैं लेकिन आगे जो आपके कर्त्ताधर्त्ता बैठे हुए हैं वे खाए जा रहे हैं। हमारी विधायिका यहां बैठी हुई हैं। इनका एक सकरेन नाला का पुल है। उस पुल का दो साल से काम पूरा नहीं हुआ है। बी0डी0ओ0 कभी कहते हैं कि उसको दिया है, इसको दिया है, यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, ऐसे ही टालते रहते हैं। मतलब लोगों को इतनी दिक्कतें हैं। अपनी निधि से पैसे दिए हैं या सेंटर से पैसा

26/03/2015/1445/MS/AG/3

दिया है, फिर भी काम नहीं होते। जो हमने एम0एल0ए0 फण्ड दिए हुए हैं, उनमें भी दो साल से काम पूरे नहीं हुए हैं। डी0पी0आर्ज0 तो बहुत दूर की बात है। इन पर तो ध्यान ही नहीं दिया जाता। प्रश्न लगाया जाता है तो उत्तर आता है कि तैयार की जा रही हैं। अगर यहां प्रश्न लगाते हैं तो उत्तर आता है कि सूचनाएं प्राप्त की जा रही हैं।

अध्यक्ष जारी श्री जे0के0 द्वारा"------

26.3.2015/1450/एजी/जेके/1

श्री बिक्रम सिंह जरयालः----जारी------

अध्यक्षः माननीय सदस्य, जरयाल जी, प्लीज वाईंड अप करें। दो मिनट के अन्दर आप जल्दी से अपनी स्पीच खत्म करें।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः अध्यक्ष महोदय, मैं अभी दो मिनट में खत्म कर रहा हूं। पिछले दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र भटियात के साथ विकास कार्यों में सोतैला व्यवहार किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है। बी.जे.पी. के कार्यकाल मेंमाननीय धूमल जी ने मेरे चुनाव क्षेत्र में जो भी विकास के कार्य शुरू किए थे, चाहे आई.पी.एच. के,पी.डब्ल्यू.डी. के या अन्य बिल्डिंग्ज के, वे सारे के सारे आज अधर में लटके हुए हैं या कोई कार्य चला भी हुआ है तो उसकी गति ज़ीरो कर दी है। यहां

तक कि एक पुल का उदघाटन जिसको माननीय धूमल जी ने किया था वह पुल तो नहीं बना लेकिन जो पैदल चलने के लिए रास्ता था वह भी उस ठेकेदार ने बन्द कर दिया। दो साल हो गए हैं और लोग उस रास्ते के लिए रो रहे हैं। वह पुल सांझीनाला में है। वहां के लिए गाड़ी तक नहीं जाती है। कितनी जनता वहां पर रहती है वह जनता रो रही है। कई बार एस.ई. को बोला, एक्सियन को बोला, एस.डी.ओ. को बोला और ठेकेदार को बोला है लेकिन उनके कान में जूं तक नहीं रेंगी है। ऐसे-ऐसे काम हो रहे हैं। छः सालों से द्रमण-सिंहुता का डबल लेन का एक काम चला हुआ है लेकिन आज उस रोड़ पर पैदल तक नहीं चला जा रहा है। जब हम घर जाते हैं तो हमें अपनी गाड़ियां छोड़ करके दूसरी गाड़ियां मंगवा कर घर जाना पड़ता है। माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ सोतैला व्यवहार न करें।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, अब हो गया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः अध्यक्ष महोदय, लॉ एण्ड ऑर्डर का बहुत खस्ता हाल है। रेप, मर्डर, क्राईम, चोरियां, डकैतियां हो रही है और इनमें पहले से कई प्रतिशत बढ़ौत्तरी हो गई है। चालान आज किसकी गाड़ियों के हो रहे हैं ? भारतीय जनता

26.3.2015/1450/एजी/जेके/2

पार्टी के वर्करों के हो रहे हैं। यहां पर प्रकाश चौधरी जी भी बैठे हैं। आज एक्साईज वाले किसकी रेड करते हैं? सबसे पहले बिक्रम सिंह जरयाल की कि इसकी फलां दुकान है। ये लोग बी.जे.पी. के लोगों की दुकानों में जाते हैं और दूसरों को बिल्कुल नहीं पूछते हैं। मेरा अनुरोध है कि चालान सभी का करें, उसमें हमारा कोई रोष नहीं होगा परन्तु इस तरह की द्वेष भावना से काम क्यों हो रहा है? .....(व्यवधान).....

अध्यक्षः माननीय सदस्य जी आप खत्म करिए। Not to be recorded now. अब कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। (Interruption) आप बैठ जाएं प्लीज। डॉ0 बिन्दल आप मेरी बात सुनिए। ..... (व्यवधान)..... Dr. Bindal .. बात सुनिए। What I am going to speak, listen to me. (Interruption) Dr. Bindal, you were absent from the House and the House decided that everybody will speak only for ten

minutes. ... (व्यवधान)....वह पहले हो गया था और उसके बाद हाऊस ने डिसाईड किया कि प्रत्येक सदस्य 10 मिनट तक बोलेंगे and he has spoken for eighteen minutes now. इनको बोलते हुए 18 मिनट हो गए हैं।..... (व्यवधान) ... When the House decided it, you were not present here. हमने अभी हाऊस में डिसाईड किया था 15 मिनट पहले।--- (व्यवधान)-- This is wrong. (Interruption) This is wrong. हाऊस ने डिसाईड किया मैंने नहीं किया था। ...(व्यवधान)...मैं यह कह रहा हूं कि it is not my verdict. It is the verdict of the august House. आपने खुद हाऊस में डिसाईड किया कि 10 मिनट तक प्रत्येक सदस्य बोलेंगे और मैंने कहा कि उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा then you agreed for that and you were absent from the House. When it was decided, you were not here. ..... (व्यवधान) ...उसके बाद ही डिसाईड किया आपने अभी। अब आपने क्या बोलना है?

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

26.03.2015/1455/SS-AG/1

अध्यक्ष क्रमागतः
अब आपने क्या बोलना है? आप कितनी देर बोलेंगे? Just see the watch. मैं आपको दो मिनट के लिए एलाऊ करता हूं। आपने ही डिसाइड किया और आप की उसकी खिलाफ़त कर रहे हैं।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज संस्थाओं को स्ट्रैंथन करने की बात की जा रही है। हमारे टाइम में जब मुख्य मंत्री, प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार थी तो थ्री टायर सिस्टम को मजबूत करने का निर्णय लिया था कि पंचायती राज के तीनों टायर (जिला परिषद्, पंचायत समिति और प्रधान) काम करेंगे। परन्तु आज उनका मानदेय बढ़ाना तो दूर उन टायरों को इस सिस्टम से अलग कर दिया। टायर पैंचर क्या करना उनको वैसे ही अलग कर दिया। तो कैसे काम चलेगा?

तीसरी बात, किसी माननीय विधायक ने इधर से कहा था कि हमारे प्रधानों के साथ ज्यादती हो रही है। मैं उसका एक उदाहरण देता हूं। मेरे पास प्रूफ हैं। एक प्रधान के खिलाफ आई0पी0सी0 की धारा 420, 409 ,468 ,467 ,506 के तहत

23.7.2000 को मुकद्दमा दर्ज़ हुआ। कोर्ट ने पंचायती राज ऐक्ट में 145 (1a) और 145 (10c) के तहत चार्ज फ्रेम कर दिए परन्तु वह प्रधान आज भी काम कर रहा है। यह कहां का कानून है? दोहरा कानून कहां से चलाया हुआ है? वहां की प्रधान ऊषा देवी के खिलाफ कोई भी एलीगेशन नहीं है उसको सस्पैंड करके घर में बिठाया हुआ है और वह प्रधान ऑल एंड ऑल है। सर, मेरे पास कोर्ट का दस्तावेज़ भी है। यही नहीं एक टीचर को अक्तूबर, 2014 से तनख्वाह नहीं मिल रही है। एक श्री कृष्ण सिंह, सी0एच0टी0, दद्रयाड़ा में लगा हुआ है।

अध्यक्षः आप खत्म करो।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः सर, मैं वाइंड अप कर रहा हूं। उसे अक्तूबर 2014 से तनख्वाह नहीं मिली। उसका क्या कारण है? क्यों नहीं दी गई? कोर्ट ने उसको रिस्टेंड किया है कि आप वहां पर रहोगे। कोर्ट के आदेश हैं परन्तु उसको आज तक तनख्वाह नहीं मिली। अगर यहां पर एजुकेशन डिपार्टमैंट के डायरेक्टर बैठे हों तो कृपया इस चीज़ को नोट करें और इसका हल निकालें। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। परन्तु मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय वाइंड अप करने के लिए बोल रहे हैं इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। परन्तु इतना जरूर बोलूंगा कि स्कूलों की हालत

खराब है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितने भी विभाग हैं उनकी हालत बहुत खस्ता है। वे बहुत मजबूर हैं। उनको डराया जा रहा है कि वे अपनी मर्जी से कुर्सी से नहीं उठते हैं और न ही बैठते हैं जब तक कि उनको आदेश नहीं देते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 2015-16 का बजट पेश हुआ है इसमें हमारे सत्ता पक्ष के सदस्य, जिन्होंने 47 मिनट भाषण दिया, उन्होंने ठीक बोला है कि इसके ऊपर बोलने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए हमने सभी बाहर की बातें कीं। धन्यवाद, जयहिन्द।

समाप्त

26.03.2015/1455/SS-AG/3

अध्यक्षः अब श्री अजय महाजन चर्चा में भाग लेंगे। Kindly wind-up in ten minutes. I won't give you more time. —

Shri Ajay Mahajan: Sir, they have been given more time. You cannot be impartial to us.

I rise to support the 18th Budget and I am proud to participate in the Budget which shows a new light to the State's population and predominantly rural but looks to new initiatives whether jobs or State economy.

The Budget is pragmatic, inclusive and has a rural face. It is for the first time that the Chief Minister, Raja Virbhadra Singh has created history by delivering a highly motivating speech lasting for over three hours.

Prof. Prem Kumar Dhumalji, Leader of the Opposition and several other Hon'ble BJP Members stated in their speeches again and again that the Hon'ble Chief Minister gave a speech which lasted over three hours but it lacked content. I am surprised in fact astonished that such a senior and learned Leader who has been the Chief Minister twice and also Member of the Parliament several times along with his various colleagues failed to comprehend and understand the contents of the Budget, which the common man has understood and appreciated highly.

Contd. By AG in English . . .

26032015/1500/KS- AG/1

Shri Ajay Mahajan Continued . .

Some of my BJP friends have been saying that Raja Virbhadra Singh is going old, but let me tell you that it seems that he has defined the age

and can beat many people of my age or younger to me. May God give him a long life so that the State of Himachal Pradesh continues to grow under his stewardship.

The State's development can be attributed to all the previous Governments towering figures like Dr. Parmar and others but contribution of Shri Virbhadra Singhji is unparallel in many respects. Prof. Prem Kumar Dhumalji has referred to the Economic Survey and tried to figure out gaps and then equate with figures of earlier regimes.

I am not a student of Economics, yet can say Economic Survey takes us through a steady growth, scenario and has several positive indicators on States economy, agriculture sector, horticulture sector, power sector and tourism. There is positivity in all core areas of growth.

Most striking factor I don't like to take you all through education. Massive efforts have been made to reach out to the less reached sections to make them literate. Now, the Opposition says that the Chief Minister talks about opening schools, even for two students. What is wrong? It's not all

26032015/1500/KS- AG/2

about the numbers but - a resolve, a determination and a commitment to the people living in remote areas. I think this is a big story that how Himachal Government is treating people who struggle their way to make saving to see their children getting educated. I compliment the Chief Minister on it and request he should move ahead and fulfil the dream of the people - looking at him from their homes in the glaciers, tough valleys and untouched villages. Hundreds posts of teachers which were lying vacant have been filled up to provide teachers. One Speaker

after the other spoke about schools having a single teacher and it seems they were very worried. Let me remind my friends not to be so hypocritical. In the year 2009, there were 1502 single teacher primary schools and 86 single teacher middle schools and subsequently the position became worse in the years after. Let me remind you that these were the years when your Government was in power - so why the noise. It's with this agenda that regularized services of PTA teachers removed by the previous Government. Their grant was also increased by our Government. The PTA teachers have been brought on Government contract. It is a welcome move.

A record 719 new schools have been opened/upgraded, 14 new degree colleges have also been opened in this short span of two years. Three medical colleges are being opened with the

26032015/1500/KS- AG/3

assistance of Government of India and accordingly sits have been finalized for medical colleges at Chamba, Nahan and Hamirpur. Besides IIIT in Una District, IIM in Sirmaur District and AIIMs in Bilaspur District are also being established in the State shortly.

Students of plus two have been provided free travelling facility in HRTC buses for journey between their residences and school. Free HRTC buses travel facility will now be available for students of Kendria Vidayalaya also.

Another area which the Government focussed on - its skill development and has launched an ambitious scheme of skill development allowance, whereby an allowance of Rs. 1000/- is being provided per month to the educated unemployed youth to increase their employability

by improving their skills. This allowance has been increased to Rs. 1500/- per month to the persons with disability. 64389 Himachalis youth have availed benefit under the scheme in the initial two years.

Another area which has been given due importance is the horticulture sector and the agriculture sectors. It is very important. Keeping in view today's practical situation where the population is growing rapidly and the job opportunities are
26032015/1500/KS- AG/4

not growing in the same proportion and where the majority of the population of our State is dependent on horticulture and agriculture. I think it has been most prudent on the part of the Chief Minister to give importance to these sectors so that the unemployed youth can start earning their livelihood with honour. A lot of required importance has been given to these segments.

Continued by AG in English . . .

26.3.2015/1505/av/ag/1

Shri Ajay Mahajan Continued . . .

If I will go through then my time will be over. Rs. 1000 crores have been given in one sector and covered for poly houses etc. etc. Keeping in view today's three biggest problems - the monkey menace, the stray cattle menace and the most unpredictable weather growing vegetable, flowers etc. under controlled conditions is very-very important. If we take poly houses then we can avoid monkey menace, the stray cattle menace. Under controlled conditions, we can make these vegetables grow unseasonal. The price is almost 100 per cent. So, this is the very-very important area and segment, which the Hon'ble Chief Minister is taken

care of and if it is put across in the right spirit, we would be able to face the issue of unemployment in a very-very large way. Rs. 45/- crores have been allotted to the Medium Irrigation Fina Singh Scheme and Nadaun. Fina Singh Scheme is in my constituency, Sir. It was the dream project of my father, late Shri Sat Mahajanji. I am thankful to you for the allocation of Rs. 45 crores for this Scheme. I would be even more grateful if you could look after this Scheme. Money is allocated to it so that we can complete it in time.

Disaster management is another area. Budget provision for Rs. 236 crores has been proposed for disaster relief - a relief is the end result of disaster - but the pre-management of disaster should be given priority. In this context I would like to point out that a NDRF Centre was proposed to be set up in Copra village. Hon'ble Prof. Prem Kumar Dhumalji and Shri Ravinder Singhji also brought up in the House so did I. I would request you - this was coming up in Copra Village and in your time also it was

26.3.2015/1505/av/ag/2

going through, then eventually Punjab Government offered free land in Ladowal Village and our area in Copra, the sanctions have been over. So, I would request you if you could kindly take it up with the Central Government as this is situated in the centre of three States, that would be very-very kind of you and this would be a big help to the State.

Prof. Prem Kumar Dhumalji has quoted lot of figures. He quoted 2012 - 1.56 crores were domestic tourists, foreign tourists 5 lacs and something; 2013 - he said that the domestic tourists were 1.47 lacs and the foreign tourist came down, rightly so. But I would like to tell you and even you know and everybody knows that in Uttarakhand there were maximum floods and it was so much publicity so the foreign tourists did not come. In 2014 - that is very interesting that domestic tourists have

gone up to 1.59 crores whereas the foreign tourists has come down to 3.89 lacs. Now, with the coming up of BJP in the Centre, the national figure has gone down. The domestic figure has gone up but the figure of foreign has gone down. So, in spite of that the Central Government has not given one per cent aid to the State. So, I am telling you the situation.

अब मैं नूरपुर विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने पिछले दो सालों में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए 21 स्कूल दिए। जबकि पिछले पांच साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वहां केवल एक स्कूल ही अपग्रेड हुआ था और उसमें भी स्टाफ हमारी पार्टी की सरकार के सत्ता में आने के बाद मिला। वहां पर मिनी सचिवालय का माननीय मुख्य मंत्री जी और स्वर्गीय श्री सत महाजन जी ने शिलान्यास किया था। वह कार्य 5 साल बंद रहा। अब जाकर उसकी इनोग्रेशन हुई। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में

26.3.2015/1505/av/ag/3

पिछले 5 सालों में कोई भी बड़ी पेयजल योजना या सिंचाई योजना नहीं दी गई थी मगर पिछले दो वर्ष के कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में वहां 30-40 करोड़ रुपये की स्कीमें आई हैं। 12 करोड़ रुपये की गम्भीरी स्कीम 21 ,ट्यूब वैल तथा दस पेयजल योजनाएं और आई हैं जिनसे हमारे लोगों को वहां बहुत राहत मिलेगी। (---व्यवधान---) बाकी जो मैंने पोलिटिकल बातें कहनी थी वे जगजीवन पाल जी ने कह दी है। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि यहां पर सुजानपुर टीहरा की रैली की बहुत चर्चा हुई। वहां रैली में माननीय प्रधान मंत्री श्री मोदी जी ने कहा था कि मुझे इस प्रदेश के साथ बहुत लगाव है। जब मैं आऊंगा तो इसके लिए विशेष पेकेज दूंगा। दिया; उन्होंने 37 सैंट्रल लिंक्ड स्कीम्ज कैंसिल कर दी। उन्होंने अपना वायदा पूरा किया मगर जो 37 सैंट्रल स्कीम्ज डीलिंक्ड कर दीं उनसे हमारे प्रदेश को बहुत नुकसान होने जा रहा है It is very surprising that majority of the BJP MLAs have spoken and discussed the previous Budgets whereas I think we were discussing the Budget - 2015-2016. I would advice my friends on the other side to read and study the Budget with an open mind then they will probably understand the tone and tenor

of the Budget and then appreciate it. Most of the speeches made by my friends on the other side had more volume and manipulative figures. मुझे एक स्टोरी याद आती है। I think probably I made it earlier that there was a lawyer, and the first day when he had to go to court, he asked his senior that how should I conduct myself, the senior said that it is not a problem, he said if you have law on your side then hammer on the law; if you have the facts on your side then hammer on the facts; and if you are nothing on your side, then hammer on the table, so that is exactly what you are being doing. (---व्यवधान---) आपको लग रहा है न। 'थर्स्टी क्रो' वाले आप बैठे हैं, मैं वह नहीं हूं। Mr. Speaker, Sir, I will cut of my speech.

श्री बी.जे.द्वारा जारी

26.03.2015/1510/negi/jt/1

श्री अजय महाजन जी के अंग्रेजी के पश्चात ..जारी...

बैल बज गई है, मेरी आधी स्पीच हो गई थी । But Mr. Speaker, Sir, I am surprised that my friends in the Opposition have not been able to see the stamp of human consideration for which Virbhadra Singh is known for and his vast experience and sentiments are effected in every para lined up in this budget. I want to remind you that many of us were not even born when Raja Virbhadra Singh was sitting in the Treasury Benches along with late Pt. Jawaharlal Nehru and other stalwarts of Indian politics in all parties. I may remind you that when he was a Member of Parliament, he took part in the historic debate on the merger of areas of Punjab into Himachal Pradesh. Had he not made his historic speech in the Parliament, we would not have 68 Vidhan Sabha seats in Himachal Pradesh.

Speaker, Sir, this is one of the most imaginative budgets which covers almost every segment of our society. We are proud of our Chief

Minister who brought such a beautiful budget which is pro poor and you can evidently see the face of the common man in it.

With these words, I support the budget, Sir.

(Concluded)

Speaker: You spoke exactly for 10 minutes.

Sh. Krishan Lal Thakur ji. You might also take 10 minutes.

26.03.2015/1510/negi/jt-2

श्री कृष्ण लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर पिछले 4 दिन से चर्चा हो रही है, उसमें भाग लेने के लिए मुझे भी अवसर मिला , आपका धन्यवाद। बजट एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होता है और इसको अन्तिम रूप देने तक अलग-अलग स्तरों पर बहुत गहरा मन्थन होता है और प्रयास होते हैं। क्योंकि इसपर प्रदेश के हर वर्ग का आशाएं और आकांक्षाएं जुड़ी होती है और किस सेक्टर में कितना विकास होना है वह भी इससे पता चलता है। जैसे ही बजट प्रस्तुत होता है उसी समय यह पता चलता है कि किसको क्या मिलने वाला है और किस सेक्टर में कितना विकास होने वाला है? परन्तु जब इस बार बजट प्रस्तुत हुआ इससे ऐसा कोई आभास नही हुआ क्योंकि इससे किसी भी वर्ग को कोई खास मिलने वाला नही है। जैसे हमारी केन्द्र सरकार ने, प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने 14वें फाइनैंस कमीशन के माध्यम से और सेन्टर टैक्सिज़ में स्टेट शेयर के माध्यम से प्रदेश सरकार को जो आर्थिक मदद की है उसका समावेश इसमें दिखाई नही देता है। जो कुछ सेन्टर स्पांसर्ड स्कीमें अन-टाईड की है वह प्रदेश के हित में ही की है ताकि प्रदेश सरकार स्टेट नीड बेसड स्कीमें बना सके।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में अगर हम मजदूरों की बात करें तो मजदूरों की दिहाड़ी मात्र 10 रूपये बढ़ायी है जो 6परसेंट इन्क्रीज़ है। जब पिछली बार प्रदेश में आदरणीय धूमल जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार थी तो इन्होंने पहली बार ही बजट में मजदूरों की दिहाडी 75 रूपये से बढ़ा कर 100 रूपये की थी जो लगभग 33

परसेन्ट बनती थी । इससे ही अन्ताजा लगाया जा सकता है कि उस समय के बजट और इस बजट में क्या फर्क है ।

इसके अलावा, यही हाल हमारे होमगार्डज के साथ हुआ है और सामाजिक सुरक्षा पैंशन का भी यही हाल हुआ है । बाकी यह बजट न तो विजनरी है और न ही इसमें रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर कोई प्रयास किया लगता है। इसमें कोई भी ऐसी महत्वकांक्षी योजना दिखाई नही देती जिसके दूरगामी परिणाम प्रदेश हित में

26.03.2015/1510/negi/jt-3

होने वाले हैं। एल.ई.डी. के लिए जो प्रावधान किया गया है जरूर यह स्वागत योग्य है । परन्तु इसके लिए भी पैसे रखे हुए हैं अगर इसको फ्री कर दिया जाए तो लोगों का भला होगा जैसे पिछली सरकार ने बल्बों के लिए किया था। इसके अलावा इस बजट में थोड़ी अच्छी बात यह है कि इरिगेशन टयूब-वैल्ज़ के लिए जो 50 परसेन्ट सबसिडी दी है, यह अच्छी बात है । मैं चाहता हूं कि इसको बढ़ा करके 75 परसेन्ट कर दिया जाए। जैसे एन्टी हेलगन्ज़ वगैरह के लिए 80परसेन्ट सबसिडी है इसलिए इसमें भी कम से कम 75 परसेन्ट कर दिया जाए। मेरा आपसे यह आग्रह है। इससे किसानों को लाभ मिलेगा। इस बजट में सबसे ज्यादा चिन्ता का विषय यह है कि जो हमारे हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेने लिए कोई फर्म़ज नहीं आ रही है, यह चिन्ता का विषय है। प्रदेश में टूरिस्टों की संख्या घट रही है। इससे सरकार की कार्य-प्रणाली का पता चलता है । तो ये सब चीज़ें ऐसी है जो सोचने वाली हैं और सरकार इस ओर ध्यान दे। इसमें जो भी स्टेप्स लेने हैं वो सरकार लें। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेन्ट बात है वह इसमें यह है कि जो भी किया गया है...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

/26.03.2015यूके/1515/1

श्री कृष्ण लाल ठाकुर--- जारी---

जो भी किया गया है और जो पिछले बजट मे कहा गया था, उसमें मैक्सिमम चीज़े पूरी नहीं हुई हैं । इसमें भी जो कहा गया है, कम से कम वह पूरी हो जाएं तो अच्छी और बड़ी बात होगी । बाकी स्टेट के बजट के बारे में हमारे विपक्ष के सीनियर नेताओं

ने काफी बोल दिया है । मैं सिर्फ अपने नालागढ़ चुनाव क्षेत्र के बारे में कॉनसन्ट्रेट करना चाहूंगा ।

माननीय मुख्य मंत्री जी आपके ध्यान में एक बहुत बड़ी बात लाना चाहता हूं मैं सड़कों के बारे मे बात करूंगा क्योकि PWD डिपार्टमैंट आपके पास है । तो सबसे पहले मैं नेश्नल हाईवे-21-ए की बात करना चाहता हूं जिसका कि स्वारघाट से पिंजौर तक जो उसको एन-21 और 22 के बीच में लिंक है, वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट सड़क है । मुख्य मंत्री जी चले गये, लेकिन यहां अन्य वरिष्ठ मंत्री और अधिकारीगण बैठे हैं । तो इस सड़क के लिए हमने पिछले दो साल से बड़े प्रयास किए । इसके लिए हमने केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार को चिट्ठियां भी लिखीं हैं । केन्द्र सरकार ने इसके लिए पूरा बजट दे दिया है । अब काम प्रदेश सरकार और नेश्नल हाई वे विभाग के माध्यम से करना है । इसके लिए हमने बहुत प्रयास किए । धरने पर भी बैठे, हंगर स्ट्राइक की,चक्का जाम तक किया क्योंकि यही सारे डेमोक्रेटिक स्टैप्स थे जो हम कर सकते थे । इसके बाद भी स्थिति वहीं है ,काम बहुत धीमा चला हुआ है । सबसे दुख की बात यह है कि सड़की की कनस्ट्रक्शन की क्वालिटी इतनी पुअर है कि जैसे सड़क बन रही है तो 10 दिन बाद वह टूट जाती है । यह बहुत चिंता का विषय है । इसके लिए मैं सदन के नेता तो चले गए हैं, लेकिन मैं सदन में आग्रह करना चाहता हूं कि सदन के सदस्यों की एक ज्वाइंट कमेटी बनाई जाए जिसमें पक्ष और विपक्ष के सदस्य हों और वे जल्दी से जल्दी इसका विजिट करें क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से माननीय सदस्य नालागढ़-स्वारघाट के रास्ते से नहीं जाते हैं । यदि आप उसकी हालत देखें तो वे भी मेरी बात को ऐपरिशएट करेंगे । इसके साथ-साथ सबसे बड़ी बात यह है कि यदि इसका वर्क टाइमली नहीं हुआ तो हमने सभी

/26.03.2015यूके/1515/2

स्टेप्स उठा कर देख लिए । डेमोक्रेटिक स्टेप्स भी उठा कर देख लिया है । अब लास्ट में हमारे क्षेत्र के लोग यह प्लान बना रह हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं, तो हम वहां ऐसा करेंगे, ध्यान देने योग्य बात है, अधिकारी वर्ग भी नोट कर लें इसको कि हम हजारों की संख्या में हिमाचल सचिवालय में इकट्ठे होंगे । मैं और नालागढ़ के कुछ और महत्वपूर्ण लोग हैं वे सैल्फ इमोलेशन की कोशिश करेंगे । इसको ध्यान दें, यह बहुत बड़ी बात है । किसी विधायक को ऐसा कहना पड़ रहा है । तो इससे इसकी

आवश्यकता का पता लगता है । अगर सरकार में थोड़ी भी सैंसटिविटी है, सरकार थोड़ी सी रैसपाँसिव है तो इस बात को ध्यान दे वरना बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड बनेगा । इसको अच्छी तरह से नोट कर लें क्योंकि मैं लाईफ में बहुत कम बोलता हूं लेकिन जब बोलता हूं तो उसका मतलब गंभीर ही होता है । मैं कहता हूं कि यदि किसी को इसमे विश्वास नहीं है तो चाहे सत्तापक्ष के लोग हैं, वे जा कर देख लें नालागढ़ से स्वारघाट तक । उसका पूरा पैसा केन्द्र सरकार से आ चुका है । पहले पैसे की कमी थी, लैंड एक्वीजिशन के लिए सरकार के पास पैसा नहीं था । नवम्बर में डी0पी0आर0 बनाई हुई है, मैने अपने पर्सनल प्रयास करके केन्द्र में मंत्री से मिले । उसके लिए 4.94 करोड़ रुपए भी लगभग डेढ़ महीने पहले आ गए हैं । लोगों को एक्वीजिशन के लिए पैसे दें । तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसकी ओर मैं धन दिलाना चाहता हूं । क्योंकि यह सिर्फ भाषण के लिए भाषण नहीं है । अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत बड़ी बात होने वाली है, यह बहुत सीरियस ईशू है । इसके अलावा दूसरी सड़कें भी हैं । इस नेश्नल हाईवे की एक और बात बताने वाली है कि वहां एक क्रशर लगा है । शायद उसे इस बात की परमिशन मिली होगी कि उसने मटिरियल यूज़ करके वहां क्रश करना है । उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी, जब वह यूज़ किया तो साथ-साथ वहां की सारी सड़क टूट गयी और अब वहां कम से कम हंर्डेड्ज़ में हैवी टिप्पर है जो पंजाब के लिए जा रहे हैं। तो उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि उसको कौन सी परमिशन मिली हुई है ? क्योंकि यदि कोई ट्रैक्टर भी अपने घर के लिए ले

/26.03.2015यूके/1515/3

जाना चाहता है तो उसके ऊपर बड़े हैवी फाईन्स होते हैं । तो यह भी देखा जाए कि वह किस माध्यम से वह टिपर ले जा रहा है । क्योंकि इनकी संख्या बड़ी भारी है और अवैध रूप से हो रहा है । उस कांट्रैक्टर का इंटरस्ट काम करने में कम है, नेश्नल हाईवे बनाने में कम है और अपना खनन का धंधा करने में ज्यादा है । इसके अलावा दूसरी सड़क की हालत भी उसके बराबर ही है कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ है । नालागढ़ की कुछ सड़कों के मैं नाम लेना चाहता हूं जिनकी हालत भी खराब है । उनकी कंडीशन भी सेम है । (घंटी) जैसे नालागढ- ढेरोवाल रोड है रामशहर-डोली-नेहरली रोड है, सोबनमाजरा-बरोला-बघेरी, गढ़ामोड़ रोड है । इन सब की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है । तो इसमें भी ध्यान दिया जाए । एक बात और

कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारा चुनाव क्षेत्र पंजाब के बॉर्डर से टच करता है और 6 रोड़ज़ पंजाब से टच करती हैं, जैसे ही हम एंटर करते है तो लगता है कि हम अच्छी जगह पर आ गए । जब वापिस हिमाचल मे एंटरी करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कहां पहुंच गए हैं । तो हमारे लिए यह बड़ी शर्म की बात है ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी-----

26.03.2015/1520/sls-ag-1

श्री कृष्ण लाल ठाकुर... जारी

तो मेरा सुझाव है कि जो यह छः रोड पंजाब बाऊंडरी को टच करते हैं, इसमें कलस्टर ऑफ रोड की डी.पी.आर. बनाकर इंटर स्टेट कनैक्टिविटी में जल्दी-से-जल्दी भेजे जाएं ताकि वहां लोगों को राहत मिले। इससे पंजाब के रोडज को देखकर शर्मिंदा होने वाली बात से भी निजात मिलेगी। एक हमारी और महत्वपूर्ण सड़क है घनौली-नालागढ़-रामशहर-कुनिहार-शिमला सड़क। यह स्टेट हाई वे है। पिछली सरकार ने इसको गवर्नमैंट ऑफ इंडिया को नेशलन हाई वे में इनक्लूजन के लिए स्पौंसर किया था। इससे न केवल नालागढ़ को ही फायदा होगा बल्कि हमारे साथ लगते ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा और साथ लगते पंजाब के लोगों के लिए भी शिमला जाने के लिए नजदीकी रोड़ है। यह महत्वपूर्ण सड़क है और इसमें बहुत ट्रैफिक होगा। मेरा सरकार से आग्रह है कि इसको गवर्नमैंट ऑफ इंडिया को स्पौंसर करें ताकि नेशनल हाई वे में इसका इनक्लूजन हो। इससे लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। रोडज के बारे में जो हमारी डी.पी.आर्ज़ हैं, जो 6-7 सालों से एम.एल.ए. प्रायरटी में मेरे प्रीडीसैसर ने दी थीं, उनकी कोई डी.पी.आर्ज. नही बनीं। कहा जा रहा है कि उसमें फोरैस्ट क्लीयरैंस नहीं हैं। आप फोरैस्ट क्लीयरैंस के लिए केस भेजिए। विभाग ने इसमें क्या प्रयत्न किए? मैंने विधान सभा के माध्यम से भी कई बार यह पूछा है। रोड़ज का यह बड़ा सीरियस इसु है। इसके अलावा हमें पी.एम.जी.एस.वाई. और सी.आर.पी. में भी नालागढ़ निर्वाचन क्षेत्र के लिए पर्याप्त फंडिंग हो।

सिंचाई क्षेत्र में देखें तो नालागढ़ क्षेत्र में ट्यूबवैल और बोरवैल की काफी ज़रूरत है। वहां इसकी पोटैंशियल है। वहां पर सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा एरिया बचा हुआ है।

आप सब जानते हैं कि नालागढ़ की वैली में पहाड़ों से पानी आता है। वहां बरसाती खड्डे हैं। बरसात में उनमें बहुत ज्यादा पानी होता है लेकिन बाद में सूख

26.03.2015/1520/sls-ag-2

जाती हैं। मैंने पिछले साल भी इसको एम.एल.ए. प्रायरिटी में डाला था कि वहां खड्डों की चैनेलाईजेशन की जाए। साथ-साथ जहां फिजीबिलिटी है, वहां स्मॉल हैड डैम्ज बनाए जाएं ताकि लोगों की फर्टाईल लैंड कटने से बच सके। इसको एफ.एम.पी. के माध्यम से भारत सरकार को स्पौंसर किया जाए। यह बात मैंने एम.एल.ए. प्रायरिटी में डाली है, और यह बहुत ही सीरियस इसु है। एक साल में उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ।

इसके बाद इंडस्ट्री की बात है। नालागढ़ में बहुत-सी ज़मीन इंडस्ट्री के लिए उपलब्ध है लेकिन उद्योग अभी तक बहुत कम आए हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि वहां पर इंडस्ट्री के लिए और इनविटेशन दें ताकि उद्योग आएं। जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसमें भी नालागढ़ के लोकल लोगों को बहुत कम प्रैफर किया जाता है। उनको भी वहां पर नौकरी दी जाए ताकि बेरोज़गार नौजवानों को काम मिले। आपने दो इंडस्ट्रियल एरियाज तो डिक्लेयर कर दिए लेकिन जो धबोटा इंडस्ट्रियल एरिया सरकार ने डिक्लेयर करना था, वह अभी बीच में पड़ा है। उसको भी शीघ्र फाइनल किया जाए।

इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र की बात मैं करना चाहता हूं। कुछ स्कूलों को अपग्रेड किया गया है लेकिन जो ज़रूरी थे वह रह गए हैं। इनमें मिडल से हाई करने के लिए कुमारहट्टी ,पल्ली और मुसामपुरा हैं। हाई से प्लस टू के लिए राजपुरा और साईथरोग हैं ।

इसके अलावा हैल्थ डिपार्टमैंट की बात करना चाहता हूं। नालागढ़ अस्पताल का बहुत बुरा हाल है। उसमें as per OPD, proportionate Doctors, Specialists

and Para-medical की स्ट्रैंथ प्रोवाईड की जाए। वहां जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैंथ है, वह as per OPD नहीं है। पीछे कहा गया था कि as per OPD उपलब्ध करवा दी जाएगी, लेकिन वह अभी तक नहीं हुई है। राम शहर की बहुत समय से डिमांड है लेकिन न जाने क्यों पोलिटिकल बेसिज पर राम शहर एरिया के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही

26.03.2015/1520/sls-ag-3

है। वह 3 निर्वाचन क्षेत्रों का केंद्र बिंदु है। वहां अभी PHC ही है। कई बार मांग की गई कि वहां PHC को CHC में अपग्रेड किया जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : आपके नालागढ़ में 100 बैड कर दिए गए हैं।

श्री कृष्ण लाल ठाकुर : नहीं सर, मैं राम शहर की बात कर रहा हूं। आप जो यह बात कर रहे हैं वह मात्र टाल रहे हैं।

मैं राम शहर को PHC को CHC अपग्रेड करने की बात कर रहा हूं। वह तीन निर्वाचन क्षेत्रों का केंद्र बिंदु है। जो एबुंलैंस की 108 नंबर की सुविधा है वह भी राम शहर के लिए दी जाए और जहां-जहां डॉक्टर्ज़ की कमी है, वह भी पूरी की जाए। इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण वहां पर रोगियों का काफी रश रहता है।

इसके अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण इसु है, हमारे स्वॉयल कंजर्वेशन विंग ने इरिगेशन ड्यूबवैल्ज लगाए हैं ,उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, though they are very few in number. नालागढ़ में 10-12 होंगे। ऐसे ही कोई नूरपुर में होंगे, कोई ऊना में होंगे। यह प्लेन एरियाज में लगाए गए हैं। इनको बाद में कमेटीज संभालती हैं। इनके जो रेट्स हैं, जो चार्जिज हैं, that are double than the private and IPH tubewells. तो मेरा आग्रह है कि अगर इनको आई.पी.एच. टेकओवर कर ले तो कोई ज्यादा लायबिलिटी भी नहीं बढ़ेगी। जब तक टेक ओवर नहीं होते हैं तब तक इसके चार्जिज लगभग उतने ही रखें जितने आई.पी.एच. के या प्राईवेट ट्यूबवैल्ज के हैं।

Speaker : Please wind up.

श्री कृष्ण लाल ठाकुर : इसके अलावा मैं स्पोर्टस के बारे में सरकार से आग्रह करना चाहता हूं। जो इंटरनेशनल प्लेयर्ज़ हैं, उनको कम-से-कम ऐसा इंसैंटिव दें ताकि और भी लोग आगे आएं। अभी रिसैंटली नालागढ़ से जो एक इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर अजय ठाकुर है .

.जारी.. श्री गर्ग जी

26/03/2015/1525/RG/JT/1

श्री कृष्ण लाल ठाकुर----क्रमागत

अध्यक्ष महोदय, मैं स्पोर्ट्स के बारे में भी कुछ आग्रह करना चाहता हूं कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार कुछ इन्सेन्टिव दे। कम-से-कम जो अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनको तो ऐस इन्सेन्टिव दे ताकि प्रदेश से और भी खिलाड़ी निकलकर प्रदेश का नाम रोशन करें। अभी हाल ही में नालागढ़ से अन्तरराष्ट्रीय स्तर के कबड्डी खिलाड़ी श्री अजय ठाकुर ने एशियन गेम्स में अभी गोल्ड मैडल लिया है। लेकिन अभी तक उसको कोई नौकरी नहीं मिली है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि उसको कम-से-कम या तो पुलिस में डी.एस.पी. लगाया जाए या फिर स्पोर्ट डिपार्टमेंट में डी.एस.ओ. लगाया जाए। यदि डी.एस.पी. लगाना संभव नहीं, तो पुलिस विभाग में इंस्पैक्टर लगाया जाए।

अध्यक्ष : कृपया अब समाप्त करिए।

श्री कृष्ण लाल ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं थोड़ा कानून-व्यवस्था की बात करना चाहता हूं।

अध्यक्ष : नहीं-नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जल्दी बोलिए और समाप्त करिए।

श्री कृष्ण लाल ठाकुर : यहां कानून-व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है और प्रशासन एवं पुलिस अपना काम नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। अभी आज ही पेपर में छपा है 'पंजाब केसरी' और 'दैनिक भास्कर' में और ई-टी.वी. पर भी यह न्यूज चल रही है कि कण्डाघाट में जो लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह है। एक काफी

प्रभावी नेता हैं ,शायद माननीय मुख्य मंत्री जी को पता होगा, उन्होंने वहां सड़क खोद दी है और वे वहां अपना निजी भवन वहां बना रहे हैं। अगर कोई आम आदमी या गरीब आदमी ऐसा कोई काम करे, तब तो उसे एकदम रोक दिया जाता है। लेकिन वह सड़क खोदकर अपना मकान बना रहे हैं। इसलिए इसकी जांच की जाए। क्योंकि यह सारा काम वे नेशनल हाइवे के पास कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन को तो अपना काम करना नहीं है।-- (घण्टी)--पुलिस और प्रशासन तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर झूठे केस बनाने में जुटी हुई है। विशेषकर धूमल जी और उनके परिवार के विरूद्ध झूठे केस बनाए जा रहे हैं। यह प्रदेश के लिए बहुत चिन्ता और दुःख का विषय है। बाकी मुद्दे तो बहुत अधिक हैं बोलने के लिए।

अध्यक्ष : नहीं, अब आप नहीं बोलेंगे।

श्री कृष्ण लाल ठाकुर : मुद्दे तो बहुत थे, मैंने तो सारी बातें रैलीवैंट की हैं, परन्तु सामने बैठे कुछ लोगों ने काफी इरैलीवैंट बातें की हैं। मुझे बोलने के लिए बहुत कम

26/03/2015/1525/RG/JT/2

समय मिला, लेकिन आपने जितना समय भी दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिन्द।

समाप्त

3/-

26/03/2015/1525/RG/JT/3

अध्यक्ष : आपने गागर में सागर भर दिया, तो अब क्या चाहिए? अब श्री बम्बर ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे। कृपया समय का ध्यान रखिए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी चर्चा का उत्तर भी देना है इसलिए इनको भी समय चाहिए। We will finish it before 5 p.m.

श्री बम्बर ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिनांक 18 मार्च, 2015 को सदन में प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ

हूं आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अभी-अभी माननीय सदस्य ने बोला है। इन्होंने भी बजट का समर्थन किया क्योंकि इन्होंने जब बजट का विरोध नहीं किया, तो इसका मतलब समर्थन किया है। इसलिए मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। ये विपक्ष से ऐसे पहले विधायक हैं जिन्होंने सही बात की हैं और अच्छी बातों के लिए इन्होंने धन्यवाद भी किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के एक तजुर्बेकार मुख्य मंत्री जिन्होंने 18वीं बार अपना ऐतिहासिक बजट सदन में पेश किया और करमुक्त बजट पेश किया। एक तरफ तो पूरे प्रदेश में इनकी तारीफ हो रही है और दूसरी तरफ चन्द लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं ,मुझे दुःख इस बात का है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने हर तबके को बजट में राहत दी है। मैं किसानों से शुरू करूं कि इस बजट में आपने किसानों के लिए 154करोड़ रुपये की राजीव गांधी सूक्ष्म सिंचाई योजना चालू करने का ऐलान किया है जिससे हमारा किसान आर्थिक तौर पर मजबूत होगा। उसके खेत में पानी लगेगा। भारतीय जनता पार्टी वाले इसका विरोध कर रहे हैं कि किसानों के खेतों में पानी नहीं लगना चाहिए। यह बहुत दुःख का विषय है। कांग्रेस पार्टी के जितने भी प्रदेश के विधायक हैं मैं उनसे यहां कहना चाहूंगा कि इन चीजों को लेकर जनता में जाएं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने किसानों के हितों का बजट प्रस्तुत किया है, उनके खेतों में पानी लगे ताकि वे आर्थिक तौर पर मजबूत हों ,ऐसा बजट प्रस्तुत किया है, लेकिन उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस बात को हमें प्रदेश के कोने-कोने में जाकर कहना पड़ेगा और यह कांग्रेस के लोगों को करना है। ऐसा मैं निवेदन करना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें यह एक अहम विषय है। आप बताइए क्या यह नहीं हुआ? आप कह रहे हैं कि बजट में कुछ नहीं है----जारी

एम.एस. द्वारा जारी

26/03/2015/1530/MS/AG/1

श्री बंबर ठाकुर जारी----------

आप बताइये कि ये नहीं हुआ? आप बोल रहे हैं कि बजट में कुछ नहीं है। बजट खोखला है। क्या यह 154 करोड़ रूपये नहीं है?

Speaker : Please don't interrupt.

श्री बंबर ठाकुरः जब श्री वीरभद्र सिंह जी पहली बार मुख्य मंत्री बने तो हिमाचल प्रदेश की सबसे महंगी पानी की स्कीम बमसन के लोगों को दी। कहां पर भेदभाव हुआ? आपने उस वक्त भी कहा कि यह केवलमात्र घोषणा है। आज वह पानी की स्कीम बनकर तैयार हो गई है। वीरभद्र सिंह जी हमीरपुर के लोगों को पानी दे रहे हैं। क्या यह खोखली घोषणा है? मैं बताता हूं कि आपने खोखली घोषणा क्या की? महेन्द्र सिंह जी मेरे चुनाव क्षेत्र के अन्दर गए और 5 करोड़ 80 लाख रूपये से जो मटियाल पुल अब बनकर तैयार होगा, उसका 15 वर्ष पहले यह शिलान्यास करके आए थे। अब मैंने उसको चूना और पेंट वगैरह करवाकर बढ़िया कर दिया ताकि लोग देखें कि 15 वर्ष पहले आपके माननीय महेन्द्र सिंह जी ने उसका शिलान्यास किया था। वह पुल आज भी वैसे का वैसे खड़ा है। अब मैंने उसको विधायक प्राथमिकता में डाला है और मुख्य मंत्री जी ने उसके लिए 5 करोड़ 80 लाख रूपये दिए हैं। अब रिखी राम कौंडल जी धन्यवाद मुख्य मंत्री जी का न करें तो क्या आपका करें? (व्यवधान)

अध्यक्षः आप लोग बीच में क्यों बोल रहे हैं ?(विपक्ष की ओर इशारा करते हुए।)

श्री बंबर ठाकुरः अली खड्ड का पुल भी श्री वीरभद्र सिंह जी ने बनवाया। आप केवलमात्र उद्घाटन करने के लिए गए थे। बेरी-दड़ोला पुल के लिए हमने आंदोलन किया। मैं इस विधान सभा के अंदर आया था। आपने मुझे चार दिन के लिए कण्डा जेल में भेजा था। आपको यह बात याद होनी चाहिए। मैं मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उसका शिलान्यास किया। फिर सरकार बदली और बेरी-दड़ोला पुल जिसकी आप बात कर रहे हैं (व्यवधान) आप मुझे छेड़िए मत, नहीं तो सुनने के लिए तैयार हो जाइए। आपने मुझे जेल भेजा। यह जगत प्रकाश नड्डा जी के समय की बात है। आपने रात तो 2.00 बजे मेरे माता-पिता को घसीटकर जेल के अंदर डाला। उस पुल का जिसका शिलान्यास वीरभद्र सिंह जी करके गए और

26/03/2015/1530/MS/AG/2

उसके बाद आपकी सरकार आई, पूरे पांच वर्ष आप बताइये कि उस पुल पर एक भी फूटी कौड़ी लगी ?बताइए? (व्यवधान) हमने जेल में जाने के लिए क्या किया था ?

हमने रात को क्या किया था जेल में जाने के लिए? आप बताइए? आप झण्डुता के विधायक हैं। बबखाल पुल का शिलान्यास श्री वीरभद्र सिंह जी ने किया था। उसके बाद यदि उसमें कोई तकनीकी खराबी आई, तो आप बताइए कि पांच साल में आपने उसमें क्या किया? अभी पीछे राजा वीरभद्र सिंह जी बिलासपुर गए थे। राजा साहब ने कहा कि उस पुल में यदि कोई तकनीकी खराबी भी है तो पूरे-का-पूरा पुल नये सिरे से बनाया जाएगा। इसके लिए हम मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। आपने क्या किया? आप धन्यवाद भी नहीं कर सकते? आप कह रहे हैं बजट खोखला है। (व्यवधान)

Speaker: Please don't discuss. कौंडल जी ऐसे बात मत कीजिए।

श्री बंबर ठाकुरः आपने पांच वर्ष क्या किया? आप पांच वर्ष तक क्या करते रहे? आप बताइए अगर बिलासपुर जिला के अंदर आपने एक भी पुल बनाया है?

अध्यक्षः आप बोलते जाइए। (व्यवधान)

श्री बंबर ठाकुरः विपक्ष का यह हाल है-

उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा,
धूल चेहरे पर थी आइना साफ करता रहा।

यह विपक्ष का हाल है। अध्यक्ष जी, पहली बार जब इनकी सरकार आई तो मुझे राजनीतिक तौर पर दबाने के लिए इन्होंने ये हथकण्डे अपनाए ,जो मैं आपको बता रहा हूं। (***) मेरे ऊपर आठ केस बनाए। उसके बाद अब जब पीछे आपकी सरकार बनी तो आपने एट्रोसिटी का केस मेरे ऊपर बनाया ताकि बंबर ठाकुर विधान सभा में न पहुंचे। (***) आपने एट्रोसिटी का केस दर्ज करवाया। आपने हर कदम पर हमें रोकने की कोशिश की लेकिन हमने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है। (व्यवधान) (***)

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

*****अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।**

26.3.2015/1535/एजी/जेके/1

श्री बम्बर ठाकुरः-----जारी------

(***) हम उसको भुगत रहे हैं और भुगतेंगे। उसके बाद मानहानि का मुकदमा करेंगे आप चिन्ता मत करें। माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने श्रमिक बोर्ड का गठन किया। श्रमिक बोर्ड का गठन पहले भी हुआ था। श्रमिक बोर्ड के तहत आपने कितनी राहत पहले पहुंचाई यह आप भी जानते है, यह सारा प्रदेश जानता है। आज हमारे जो मज़दूर हैं और मनरेगा के अन्दर जो मज़दूर हैं उन मज़दूरों को भी इसमें शामिल किया गया। इंडक्शन चूल्हा उनको मिलेगा। फ्री मेडिकल सुविधा 9 ,हजार रूपये तक की दवाईयाँ उनको मिलेगी, उनको बर्तन भी मिलेंगे। यदि उनका कोई बीमार हो जाए उसका खर्चा भी मिलेगा। वाशिंग मशीन तक उनको देने का प्रबन्ध राजा वीरभद्र सिंह जी ने किया है। अब धन्यवाद किसका करें, आपका करें? यही धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। राजा वीरभद्र सिंह जी को हम मुबारकवाद देते हैं। आप बधाई के पात्र हैं। मनरेगा में जो काम कर रहे हैं उसमें चाहे कांग्रेस पार्टी का आदमी काम कर रहा है या भाजपा का आदमी काम कर रहा है, मिस्त्री चाहे कांग्रेसी है या भारतीय जनता पार्टी का है या कॉम्युनिस्ट है उसको वाशिंग मशीन देने का इन्तजाम किया गया है। इसके लिए राजा वीरभद्र सिंह जी धन्यवाद के पात्र हैं। बजट में यह इन्तज़ाम नहीं है। आप तो पहले कहते थे कि नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? 18लाख रूपया मैंने बांट दिया। मैंने मजदूरों को 12 लाख रूपया कुठेड़ा में बांटा। हम किसका धन्यवाद करें? आप का करें? जिसने पैसे नहीं दिए उसका धन्यवाद करें? दो लाख वाशिंग मशीनें आ रही हैं। दो लाख मशीनें हम पूरे प्रदेश के मजदूरों को बांटेंगे। आपका भी यदि कोई मनरेगा के अन्दर मज़दूर होगा उसको भी वह बांटी जाएगी। हम भेदभाव नहीं करते हैं। हमारे शब्दकोष में भेदभाव नहीं है। वीरभद्र सिंह जी इसके लिए मुबारिक के पात्र हैं। माननीय धूमल

*****अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।**

26.3.2015/1535/एजी/जेके/2

साहब आप हमीरपुर को मेडिकल कॉलेज नहीं दे पाए। यदि यह मेडिकल कॉलेज राजा वीरभद्र सिंह ने नहीं दिया होता तो हमीरपुर को नहीं मिलता। आपने चम्बा को

भी दिया, आपने सिरमौर को भी दिया। जो मेडिकल कॉलेज आपने हमीरपुर को दिया उसके लिए हम किसका धन्यवाद करें, आप हमें बताएं? .....(व्यवधान)...धर्माणी जी का भी धन्यवाद करते हैं। ये भी हमारा ही अंग है। ये राजा वीरभद्र सिंह से बाहर थोड़ा न है, ये कांग्रेस पार्टी के एम.एल.ए. हैं, आपको इनकी क्या चिन्ता है? आपको इनकी ज्यादा ही चिन्ता है। ये हमारे भाई हैं और राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ हैं। हमारे जिला के मंत्री हैं। इस बारे में आपको कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिए। राजा साहब आपने तीन मेडिकल कॉलेज दिए और साथ-साथ आपने 1 करोड़ 89 लाख रूपया भी दे दिया इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता हमेशा आपकी आभारी रहेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए एम्ज दे दिया जाएगा। हमारे बिलासपुर के धर्माणी जी हैं, रामलाल ठाकुर जी, बीरू राम जी और मैं, हम सभी राज साहब के पास इकट्ठे हो करके गए कि बिलासपुर में आप कहीं पर भी एम्ज खोल दीजिए। राजा वीरभद्र सिंह जी ने हम सबको शाबाशी दी। बिलासपुर में हमने कहा कि जहां कहीं भी जमीन मिलती है एम्ज को आप बिलासपुर में खोल दीजिए। इसके लिए अब हम किसका धन्यवाद करें? हमने इसके लिए कोई झगड़ा पैदा नहीं किया। कांगड़ा के अन्दर आप लोगों ने जिस तरह से सेन्ट्रल युनिवर्सिटी का झगड़ा पैदा किया है वह झगड़ा हमने बिलासपुर में नहीं किया। हम इसके लिए वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद करते हैं। कौंडल साहब आप इतने थैंकलैस मत होइए। आप लोगों ने कांगड़ा में लड़ाई पैदा की। हमारे बिलासपुर में इसके लिए कोई लड़ाई नहीं होगी। हमने इकट्ठे हो करके यह फैसला किया। आज हम मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि बिलासपुर में आपने एम्ज संस्थान दिया। राजा वीरभद्र सिंह जी आप धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। क्या यह खोखला बजट है कि एम्ज बिलासपुर में आया?

श्री एस.एस. द्वारा जारी------

26.03.2015/1540/SS-AG/1

श्री बम्बर ठाकुर क्रमागतः

ये जो मेडिकल कॉलेज आपको हमीरपुर में दिया, क्या यह खोखला है? आपको जो नाहन मेडिकल कॉलेज दिया, क्या यह खोखला है?

अध्यक्षः बम्बर जी, आप बोलते जाईये। ऐसे बहस मत करिये।

श्री बम्बर ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री और ठाकुर कौल सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने बिलासपुर के अस्पताल के लिए 1 करोड़ 24 लाख रुपया दिया। बिलासपुर के अस्पताल की ऐसी हालात थी कि वहां पर दो वर्ष के लिए टॉयलैट बंद पड़ी रही। वहां के एम0एल0ए0 क्या करते रहे? हमारे मुख्य मंत्री जी वहां पर गए और आपने एकमुश्त बजट दिया। आज 18 लाख रुपये से तीनों टॉयलैट के ब्लॉक बनकर तैयार हो गए। आज पूरे बिलासपुर के अस्पताल का नक्शा बदल गया। 29डॉक्टर्ज़ हमें दिए हैं। मैं राजा साहब, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने यह इंतजाम बिलासपुर के अंदर किया है। आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन जिनके समय में दो साल तक टॉयलैट बंद पड़ी रही क्या हम उनका धन्यवाद करें? साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री महोदय ने नर्सिंग होस्टल बनाने के लिए एक करोड़ रुपया अभी-अभी जारी कर दिया। इसके लिए किसका धन्यवाद करें। एक करोड़ रुपया आपने और नर्सिंग होस्टल बनाने के लिए जारी कर दिया। इसके लिए किसका धन्यवाद करें। साथ में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि बिलासपुर के अस्पताल के अंदर ऐसी परिस्थितियां थीं। आपने बिलासपुर से स्वास्थ्य मंत्री दिया। आपके समय में जगत प्रकाश नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री रहे। बिलासपुर में जैसी हालत थी आज दिल्ली में भी है। सुनिये ज़रा क्या हुआ? उनके वक्त में डायरेक्टर जेल मे चला गया। उनके वक्त में बिलासपुर में ऐसा होता था। दो वर्ष पहले तक किसी बहन के अगर प्री-मिच्योर डिलीवरी हो रही है तो डॉक्टर कहते थे कि इस बच्चे को लेकर शिमला या चंडीगढ़ चले जाओ क्योंकि बच्चे को इंक्यूवेटर में रखना पड़ता है। ऐसी व्यवस्था बिलासपुर के अस्पताल में नहीं थी। आज मैं मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज वहां पर ऐसी 8 मशीनें लगी हैं। आज दो महीने के बाद हमारी बहन हरी-भरी गोद से स्वस्थ होकर अपने घर को लौट रही है। ये इंतजाम हमारी सरकार ने दो वर्षों के अंदर बिलासपुर में किये हैं। इसके लिए मैं किसका धन्यवाद करूं? सत्ती जी, किसका धन्यवाद करें? आप बोल

रहे हैं कि हमारा मंत्री दिल्ली में बैठा है। यह इंतजाम बिलासपुर के अंदर प्रोफैसर साहब ने किया।

Speaker: Please wind-up.

श्री बम्बर ठाकुरः बिलासपुर में आपके स्वास्थ्य मंत्री के टाइम की बात बता रहा हूं। एक बच्चे का ऑपरेशन होना था। बच्चे का पेट चीर कर रख दिया। डॉक्टर ने दो टुकड़े कर दिए।

अध्यक्षः बस करिये। काफी हो गया।

श्री बम्बर ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट लूंगा। ऑपरेशन के समय लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद डॉक्टर इंतजार करता रहा कि लाइट आयेगी। जब लाइट नहीं आई तो आनन-फानन में स्टीचिज़ लगा दिए क्योंकि बड़े अफसर का बेटा था और कैंची पेट के अंदर रह गई। बिलासपुर में ये हालात थे आपके स्वास्थ्य मंत्री के समय के। ज़रा सुनने की हिम्मत रखिये।

अध्यक्षः आप बहस मत कीजिए, बोलते जाईये।

श्री बम्बर ठाकुरः आप भी डिप्टी स्पीकर रहे। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि हम माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि इन्होंने 37लाख रुपया मंजूर किया है। बिलासपुर अस्पताल में जनरेटर लगेगा। लाइट जाने पर पूरा अस्पताल जनरेटर से चलेगा। लाइट चली जाए तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या किसी भी पार्टी के व्यक्ति का ऐसा ऑपरेशन हो रहा होगा तो अब कैंचियां पेट के अंदर नहीं रहेंगी। यह इंतजाम हमारी सरकार के मंत्री और मुख्य मंत्री ने किया है। इसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहूंगा। ये बजट का प्रावधान नहीं है तो कहां से पैसा आया?

अध्यक्षः काफी हो गया। बस कीजिए।

श्री बम्बर ठाकुरः लिफ्टों के लिए पैसा कहां से आया? लिफ्टों के लिए पैसा मुख्य मंत्री जी आपने दिया। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत कुछ कहने को है। 50 करोड़ रुपया राजा साहब ने दिया कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो खतरनाक सड़कें हैं, जहां पर

26.03.2015/1540/SS-AG/3

ढांकों से एक्सीडेंट हो जाते थे, उसके लिए इन्होंने 50 करोड़ रुपया दिया। मैं वित्त सचिव महोदय का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। अब पूरी सड़कों पर क्रैश बैरियर लगेंगे ताकि एक्सीडेंट न हों। इसके लिए किसका धन्यवाद करें?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट दे दीजिए।

अध्यक्षः मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा। आप काफी बोल लिये हैं। अगर इस तरह से बोलेंगे तो तीन घंटे लगेंगे।

श्री बम्बर ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट और बोलूंगा। जो उपलब्धि हुई है जो बजट के अंदर है यदि मैं उसको न कहूं तो अच्छा नहीं होगा। ये उसका विरोध करते रहे। विपक्ष के लोग उसका विरोध करें कि बजट खोखला है तो मैं क्यूं न बताऊं कि यह खोखला नहीं है। इसमें पैसा है और पैसा लग रहा है। आपके क्षेत्र के अंदर पैसा लग रहा है। आप उसका विरोध कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं ..

जारी श्रीमती के0एस0

/1545/26.03.2015केएस/एजी/1

श्री बम्बर ठाकुर जारी---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या विपक्ष यह चाहता है कि मा0 मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह जी ने जो बच्चे पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, उनके लिए हॉस्पिटल में स्पैशल वार्ड बनाने का जो इन्तज़ाम किया उसके लिए मुख्य मंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की जाएगी, क्या ये लोग इसका विरोध करना चाहते हैं? जो 50 करोड़ रु0 के क्रैश बैरियर लगेंगें ताकि एक्सिडैंट्स रूकें उसका विरोध कर रहे हैं? विरोध उसका करिए अगर हम कोई अच्छा काम

नहीं कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत सी बातें कहने को रह गई है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, अब समाप्त करें। काफी हो गया ।

श्री बम्बर ठाकुरः अध्यक्ष जी, हमारी जो विधायक निधि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बढ़ाई, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारा डिस्क्रिशनरी फंड है उसको डबल कर दिया जाए, दो लाख से चार लाख कर दिया जाए और बिलासपुर में मल्टीपरपज़ इंडोर स्टेडियम दिया जाए । माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर में मुख्य मंत्री जी ने बहुत बड़ा कॉम्पलैक्स बनाया है।

अध्यक्षः बम्बर ठाकुर जी, समाप्त करिए। अब कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। आप सभी को कहा गया था कि 10-10 मिनट बोलें, आपको 15 मिनट हो गए । आपने सबकुछ तो बोल दिया। और सब कुछ समझ में आ गया है।

/1545/26.03.2015केएस/एजी/2

सारे इसी तरह से बजट पर बोलेंगें तो तीन घंटे लग जाएंगें। कृपया, आप धन्यवाद करके बैठ जाईए।

श्री बम्बर ठाकुर :अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

/1545/26.03.2015केएस/एजी/3

अध्यक्षः अब श्री विनोद कुमार जी चर्चा में भाग लेंगें और 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेंगें।

श्री विनोद कुमारः अध्यक्ष महोदय, 18 मार्च, 2015 को जो हिमाचल प्रदेश सरकार का जो 18वां बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया, मैं उस बजट के समर्थन में तो नहीं बोल सकता क्योंकि समर्थन करने के लिए इस बजट में मुझे कुछ भी नज़र

नहीं आ रहा है इसलिए मैं इसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब से केन्द्र में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से हिमाचल प्रदेश की जनता को केन्द्र की मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी से अधिक अपेक्षाएं हैं। उन अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए केन्द्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहले तो पैट्रोल और डीज़ल के दाम कम किए । एक नहीं अनेकों बार कम किए परन्तु यहां पर कांग्रेस सरकार ने क्या किया, यह हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है। जहां पर केन्द्र की मोदी जी की सरकार ने पैट्रोल और डीज़ल के दाम कम किए आपने ये दाम बढ़ाकर पैट्रोल और डीज़ल को और मंहगा किया इसके लिए हिमाचल की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। अध्यक्ष जी, प्रदेश की जनता ने केन्द्र की सरकार से जो अपेक्षा रखी थी कि 13वें वित्तायोग की अपेक्षा अधिक धन हिमाचल प्रदेश को मिलेगा तो केन्द्र की नरेन्द्र भाई मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 14वें वित्तायोग में तीन गुना अधिक धन हिमाचल प्रदेश के विकास कार्यों के लिए दिया है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

26.3.2015/1550/jt/av//1

श्री विनोद कुमार जारी-------

भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 14वें वित्तायोग में हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए जो तीन गुणा अधिक धन दिया है उसके लिए हम सभी विधायक अपनी और इस प्रदेश की समस्त जनता की ओर से उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं अपने सत्ता पक्ष के विधायकों की मजबूरी समझता हूं कि क्यों ये धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। मगर मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अगर सच्चाई बताऊं तो हिमाचल प्रदेश को 14वें वित्तायोग द्वारा पिछली बार की अपेक्षा तीन गुणा अधिक धन मिलने से हमारे प्रदेश का गरीब तबका बहुत खुश था। हम जब भी गांव में जाते थे तो दिहाड़ीदार लोग चर्चा करते थे कि इस वर्ष के बजट में हमारी कितनी दिहाड़ी बढ़ाई जायेगी। लोग आपस में बैठकर इस तरह की चर्चा करते थे। कुछ लोगों का मत था कि हो सकता है हमारी दिहाड़ी 80 रुपये बढ़ाई जाए। कुछ कहते थे कि 50 रुपये बढ़ाई जाये। 14वें वित्तायोग ने प्रदेश सरकार को जो पहले से 3 गुणा अधिक धन दिया उससे हमारे प्रदेश की जनता को बहुत आशाएं थीं। मगर जिस दिन बजट आया और बजट बुक के सातवें नम्बर पर मुख्य मंत्री जी ने मजदूरों की दिहाड़ी 170 रुपये से

180 रुपये कर दी तो उन मजदूरों को बहुत दुख पहुंचा। इस महंगाई के जमाने में मजदूरों की सिर्फ दस रुपये दिहाड़ी बढ़ाई गई, फिर हम गरीब लोगों के उत्थान की बात करते हैं। क्या दस रुपये से गरीब लोगों का उत्थान होगा? क्या दस रुपये से उस गरीब व्यक्ति की आमदनी में सुधार होगा? इस बारे में सोचने और मंथन करने की आवश्यकता है।

मैं अब शिक्षा के बारे में बात करना चाहता हूं। यहां लम्बे-लम्बे आंकड़े बताए गए मगर मैं उन पर नहीं जाना चाहूंगा। यहां पर कहा गया कि इतने प्राइमरी स्कूल खोले गए। इतने प्राइमरी स्कूलों को अपग्रेड करके मिडिल स्कूल किया गया। इतने मिडिल स्कूल को हाई स्कूल किया गया और इतने हाई स्कूल को अपग्रेड करके सीनियर सैकैण्डरी स्कूल किया गया। सबसे बड़ी बात व्यवस्था की है। आपने जो

26.3.2015/1550/jt/av//2

स्कूल अपग्रेड किए हैं क्या उन स्कूलों में सरकार ने अध्यापकों की व्यवस्था की है? क्या उन स्कूलों में स्टाफ और बच्चों को बैठने के लिए कमरों की व्यवस्था की है? यदि नहीं, तो सरकार को उन सभी विषयों पर सोचना और विचार करना चाहिए। मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि दो बच्चों के लिए भी स्कूल खोले जायेंगे। हम आपका समर्थन करते हैं मगर उन स्कूलों में सरकार को अध्यापक और बच्चों के बैठने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हम स्कूलों को अपग्रेड करेंगे। मैं भी इसका समर्थन करता हूं, स्कूल अपग्रेड होने चाहिए। नाचन विधान सभा क्षेत्र के अभी भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां के लड़के/लडकियां दस जमा दो की शिक्षा ग्रहण करने के लिए 7किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 12-12 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाते हैं। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि गवर्नमैंट हाई स्कूल पलौटा, गवर्नमैंट हाई स्कूल शैंजी, गवर्नमैंट हाई स्कूल छपराह, गवर्नमैंट हाई स्कूल नंडी, गवर्नमैंट हाई स्कूल चच्योट, गवर्नमैंट हाई स्कूल बालड़ी, गवर्नमैंट हाई स्कूल शाला और गवर्नमैंट हाई स्कूल छमयार को भी अपग्रेड किया जाए। यहां के बच्चों को पैदल या बस पर 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर दूरी तय करके जाना पड़ता है और गरीब लोगों के लिए यह सम्भव नहीं है। इसके साथ ही, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं प्लस टू स्कूल में जिन बच्चों ने तो आर्ट्स पढ़ना है वे उसको पढ़ रहे

हैं मगर साईंस पढ़ने वालों के लिए आज भी पहले की तरह मुश्किलें बनी हुई हैं । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि गवर्नमैंट सीनियर सैकैण्डरी स्कूल

श्री बी.जे.द्वारा जारी

26.03.2015/1555/negi/jt/1

श्री विनोद कुमार ..जारी...

मेरा आपसे निवेदन है कि गवर्नमैन्ट सीनियर सकेन्डरी स्कूल मवेसरी, गवर्नमैन्ट सीनियर सकेन्डरी स्कूल बग्गी, गवर्नमैन्ट सीनियर सकेन्डरी स्कूल जाहल, गवर्नमैन्ट सीनियर सकेन्डरी स्कूल गरोड, गवर्नमैन्ट सीनियर सकेन्डरी स्कूल फंगवास, गवर्नमैन्ट सीरियर सकेन्डरी स्कूल किलिंग और गवर्नमैन्ट सीनियर सकेन्डरी स्कूल गिरी में साईंस की क्लासें बिठायी जाए ताकि बच्चों को दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए न जाना पड़े । अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि दो बच्चों के लिए भी स्कूल खोले जाएंगे । लेकिन मैं आपका ध्यान अपने नाचन विधान सभा क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल पलोता की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस स्कूल को खुले हुए 4 साल हो गए हैं। लेकिन आज भी वहां पर कोई भी रेगुलर अध्यापक नही है। प्लानिंग की मीटिंग में मैंने बात की थी, पिछली बार प्लानिंग की बैठक हुई है और बुक छपी है। मैंने डी.आर.डी.ए. की बैठक में बात की और प्लानिंग की बैठक में भी बात की । लेकिन विभाग ने क्या कदम उठाया? कुछ नही किया। दो महीने बीतने जा रहे हैं लेकिन आज भी विभाग ने वहां पर कोई रेगुलर टीचर नही भेजा है। इस स्कूल को 4 वर्ष हो गए और आज भी इस स्कूल में बच्चों को बैठने के लिए अपना कोई कमरा नही है। नाचन विधान सभा क्षेत्र का एक और प्राइमरी स्कूल खुम्बा है, पिछले कई महीनों से इस स्कूल में रेगुलर अध्यापक नही है। 4 दिन डैपुटेशन पर कोई आ जाता है, 2 दिन के बाद कोई और आ जाता है । मैंने इस बात को भी प्लानिंग की बैठक में किया था ,हालांकि मुख्य मंत्री जी ने उस दिन आदेश भी दिए थे कि जो बात विधायक ने कही है उसको गौर से सुना जाए और जहां पर टीचर नही है वहां पर अध्यापक नियुक्त किया जाए। लेकिन मुख्य मंत्री जी आज तक वहां पर कोई भी अध्यापक नही आया है।

अध्यक्षः प्लीज़ वाइन्ड-अप करें।

श्री विनोद कुमारः अध्यक्ष जी, मैंने अभी शुरू किया है।

26.03.2015/1555/negi/jt/2

अध्यक्षः शुरू किया है तो खत्म भी तो करना पड़ेगा।

श्री विनोद कुमारः मुख्य मंत्री जी 26 ,दिसम्बर को प्राइमरी स्कूल खुम्बा में अनुबन्ध आधार पर एक अध्यापक ने ज्वाइन किया और 31 दिसम्बर को उसका तबादला कर दिया गया। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उसका तबादला 6 दिन के बाद कौन सी नीति के तहत हुआ? जबकि उसकी नियुक्ति अनुबन्ध के आधार पर वहां पर पहली बार हुई थी । तो इस तरह से कैसे होगा शिक्षा का सुधार, मुझे तो समझ नही आ रहा है। हमारा गवर्नमैन्ट सीनियर सकेन्डरी स्कूल गिरी जिसको अपग्रेड हुए लगभग 7 साल होने जा रहे हैं और हमारी सरकार के समय वहां पर बिल्डिंग के लिए 52.24 लाख रूपये का प्रावधान किया गया। लेकिन आज तक वहां पर बिल्डिंग का काम शुरू नही हो पाया। इसी तरह से प्राइमरी स्कूल नालू में भी 27 बच्चें पढ़ते हैं, 4 वर्ष इस पाठशाला को खुले हुए हो गए हैं लेकिन आज भी इस पाठशाला के पास एक भी कमरा नही है । इसके अलावा प्राइमरी स्कूल ओडी में भी कमरों की व्यवस्था नही है। प्राइमरी स्कूल खनडेहल में भी कमरों की व्यवस्था नही है। जब बैठने के लिए कमरे नहीं है तो कैसे होगा शिक्षा में सुधार।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का ध्यान नाचन विधान सभा क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवाओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, यहां अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी नही हैं। नाचन विधान सभा क्षेत्र के गोहर में सी.एच.सी. का दर्जा 21 जनवरी, 2014 को बढ़ाया गया । हमने आपसे इसको अपग्रेड करने की डिमाण्ड की थी और आपने इसको अपग्रेड किया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। परन्तु आज भी उस सिविल हॉस्पिटल में न डॉक्टर के पद को सृजित किया गया है और उस सिविल हॉस्पिटल गोहर में जो डॉक्टर्ज़ के 3 पद खाली चल रहे थे उन्हें भी अभी तक भरा नही गया है। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होंगे, न के बराबर होंगे तो उसे अपग्रेड करने का या बेड बढ़ाने का

26.03.2015/1555/negi/jt/3

क्या लाभ होगा? अगर हम और आप सच में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि ...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

/26.03.2015यूके/1600jt/1

श्री विनोद कुमार---जारी---

तो मेरा आपसे निवेदन है कि सिविल हॉस्पिटल गोहर में जो खाली पड़े पद हैं, उनको भरा जाए और नए पदों को भी सृजित किया जाए । ताकि अच्छी स्वास्थ्य सुविधा लोगों को मिल सके । अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि नाचन विधान सभा क्षेत्र में पिछले ढाई वर्षों से एक भी DPR सड़क की तैयार नहीं की गयी है । यह आपके PWD विभाग का है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं । नाचन विधान सभा क्षेत्र की कोई सड़क ऐसी नहीं है जिसमें सड़क कम और गड्ढे ज्यादा दिखाई न देते हों । हमारी सरकार के समय नाचन क्षेत्र की सभी सड़कों की टारिंग आदरणीय धूमल जी के आर्शीवाद से और स्वर्गीय दिले राम जी के प्रयासों से सभी सड़कों में टारिंग हुई थी । पिछले ढाई वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस सरकार का बीतने जा रहा है । नाचन विधान सभा क्षेत्र की एक भी सड़क पर टारिंग नहीं हुई है । अगर कुछ हुई है तो वह टारिंग उखड़ चुकी है । मैने प्लानिंग की बैठक में भी बात की थी । नाचन की सड़कों की ओर भी मुख्य मंत्री जी ध्यान दें । अध्यक्ष जी ,नाचन विधान सभा क्षेत्र की बग्गी से पंडोह, चैलचौक से चहल, चैलचौक से मवीसेरी, चैलचौक से करसोग, खुकलीगलु से सरोहा, जाच से मशोगल पाली से किलिंग, बग्गी से घनोटू, घनोटू से रोहांडा, सयाह से नरसर बाया ढाबण, भयांटा, हटगढ़, साई से घांघल,बाया जलजुगाहण-साशल, सड़क ज्यारगी से सांजी सड़क, भराड़ी से तमरोह सड़क बाया पनहोटा (घंटी) आदि सड़को का बहुत बुरा हाल है । दो सड़कें तो ऐसी हैं जिसमें बारिश में बच्चे तो क्या बड़े भी नहीं चल सकते ।

अध्यक्षः आपके 15 मिनट होने वाले हैं । प्लीज़ वाईंड अप ।

श्री विनोद कुमारः अध्यक्ष जी, जब भी चुनाव आता है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार या कांग्रेस पार्टी के लोग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का बड़ा राग अलापते हैं लेकिन मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं। जब हमारी सरकार प्रदेश के अन्दर थी तो एस0सी0 कम्पोनेंट के तहत एक नहीं अनेकों स्कीमें डाली जाती थीं। लेकिन जब से प्रदेश के अन्दर कांग्रेस पार्टी की सरकार आयी है, उन्होंने एक

/26.03.2015यूके/1600 /2

नोटिफिकेशन जारी की है कि एस0सी0 कम्पोनेंट प्लान के तहत अब केवल 4 स्कीमें डाली जायेंगी। हमने कहा कोई बात नहीं, 4 स्कीमें ही सही। लेकिन इस बार कल्याण विभाग ने जब हमसे सड़कों की डिमांड पूछी तो हमने 4 सड़कों की डिमांडें उनके पास दी तो उन्होंने कहा कि सरकार ने आदेश दिया है कि अब दो ही स्कीमें डाली जाएंगी। तो मै सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि एस0सी0 कम्पोनेंट की सड़कों के ऊपर और एस0सी0सी0पी0 की स्कीमों पर ही कट क्यों लगाया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हमेशा ही अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया है। लम्बे समय से सत्ता में रहने के बावजूद बैकलॉग की एस0सी0एस0टी0 की सीटों को नहीं भरना यह दर्शाता है कि सरकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास के प्रति कितनी गंभीर है।

Speaker: Please wind up now.

श्री विनोद कुमार : सर, अभी तो शुरू ही हुआ है।

Speaker: Please wind up in a minute; otherwise I will close it down.

श्री विनोद कुमारः कांगेस पार्टी की सरकार जब-जब प्रदेश में आयी है तो उन्होंने अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए बैकडोर एंट्री के माध्यम से भर्ती की है। उदाहरण के तौर पर PTA की भर्ती में कोई भी रोस्टर प्रणाली को नहीं अपनाया गया। पैरा टीचर की भर्ती, इसके अलावा एस0एम0सी0 की भर्तियों में भी रोष्टर प्रणाली को नहीं अपनाया गया। इसी तरह से आशा वर्कर की भर्तियों में भी कोई

रोस्टर प्रणाली को नहीं अपनाया गया है । हम तो इस विषय को उठा भी रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं । लेकिन मेरा निवेदन सत्ता पक्ष के अनुसूचित जाति के मंत्रियों से है ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी-----

26.03.2015/1605/sls-ag-1

श्री विनोद कुमार...जारी

लेकिन मेरा निवेदन सत्तापक्ष के अनुसूचित जाति के मंत्रियों और विधायकों से भी है कि आप भी इस विषय पर सोचें और गंभीरता से विचार करें क्योंकि आज जनता जानना चाहती है कि जो अन्याय अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हो रहा है, क्या वह सही है। (घंटी)

अध्यक्ष जी, जब विधान सभा का चुनाव हुआ ,उस समय कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में कहा कि हम नौजवानों को बेरोज़गारी भत्ता देंगे। बड़ी-बड़ी बातें की गईं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के उन बेरोज़गारों के साथ धोखा हुआ है क्योंकि उन्हें आज तक कोई भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष जी, भत्ते के नाम पर लाखों बेरोजगार युवकों को ठगा गया है। दूसरी ओर सरकार कौशल विकास भत्ते की बात करती है। नाचन विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत हिमालयन महिला एवं जन कल्याण संस्था, भोरंज, हमीरपुर द्वारा लगभग 80 प्रशिक्षण केंद्रों को सिलाई एवं कढ़ाई प्रशिक्षण देने के लिए मान्यता दी गई। इन 80 केंद्रों में से 26 केंद्रों का निरीक्षण एस.डी.एम., गोहर के माध्यम से किया गया और ..

Speaker : Wind up, please. No more recording, please. You are going on speaking in spite of my instruction. आप 20 मिनट बोल चुके हैं। Please wind up. यह गलत बात है। This is a wrong procedure. आपको स्वयं ही

रिसपांसीबिलिटी लेनी चाहिए। आप हरेक मद पर बोलेंगे तो आपको 3 घंटे लगेंगे। Please wind up.

श्री विनोद कुमार : जो सिलाई एवं कढ़ाई के सैंटर खोले गए थे उनका नाम भी मेरे पास है। मैं मुख्य मंत्री जी को दे दूंगा।

26.03.2015/1605/sls-ag-2

जैसा कि यहां पर कहा गया कि मुख्य मंत्री जी ने..

अध्यक्ष : आप प्लीज वाईंड अप कीजिए। It is not wind up sign. You are starting a new topic now.

श्री विनोद कुमार :मैं क्लोज कर रहा हूं।

Speaker : You close it now.

अध्यक्ष महोदय, विधायकों की विधायक निधी जो 50 लाख से 70 लाख रुपये की है, इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। लेकिन इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इसको कम-से-कम एक करोड़ रुपये किया जाए और जो कंडिशन इस 20.00 लाख रुपये के ऊपर लगाई है , उसे हटाया जाए। साथ में जो हमारी एच्छिक निधी 2.00 लाख रुपये है ,मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इसे कम-से-कम 5.00 लाख रुपये किया जाए। साथ में हमारा जो हाऊस लोन है, मैं चाहूंगा कि उसको भी कम-से-कम 50.00 लाख रुपये किया जाए।

अध्यक्ष : बस, अब काफी हो गया।

श्री विनोद कुमार: अध्यक्ष जी, इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे हिमाचल प्रदेश के लोगों का उत्थान हो सके। मैं इसका समर्थन तो नहीं कर सकता, लेकिन इसका विरोध करता हूं।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। जयहिंद, जय हिमाचल।

अध्यक्ष : अब तकरीबन सारे लोग बोल चुके हैं। अब माननीय मुख्य मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे और उत्तर के साथ इस चर्चा को समाप्त भी करेंगे।

26.03.2015/1605/sls-ag-3

Chief Minister: Mr. Speaker, Sir, Hon'ble Members have participated in the budget discussion. Thirty five Hon. Members have participated in the budget discussion till yesterday and eight Members have participated today. I think, this is the record number of Members ever participating in any budget discussion in Himachal Pradesh.

Contd...ag/rg

26/03/2015/1610/RG/AG/1

Chief Minister continued . . .

This itself shows that this Budget has many new policies and programmes benefitting all sections of the society. Now, I will reply on the important points raised by the Hon'ble Members.

Mr. Speaker, Sir, issue was raised that the Budget is directionless, disappointing and nothing new. This was said by Prof. Prem Kumar Dhumal, Leader of the Opposition, and other MLAs of the Opposition. In fact, this has been the refrain of almost all the speakers from the Opposition Benches. Mr. Speaker, Sir,

'कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना',

और आज तक हमारी अपोजीशन ने यह मान रखा है कि अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, मगर उसको बुरा जरूर कहेंगे और उसका विरोध करना उनका धर्म हो जाता है। यह आलोचना नहीं है, यह विरोध है।

I fail to understand as to why the Opposition is not able to see any direction in the Budget. If one sees with open mind, the Budget of 2015-16 gives a clear fiscal direction for investment in critical sectors such as; Agriculture, Horticulture, Power, Irrigation, Drinking Water supply, Health, etc.

Speaker Sir, 70 per cent of the population of the State is engaged in Agriculture. Naturally, our main focus in the Budget has been to promote Agriculture. Irrigation is very crucial for increasing the productivity. Therefore, we have proposed launching of a new scheme called *'Rajiv Gandhi Micro-Irrigation Scheme'* with the outlay of Rs. 154 Crore. Farmers will get subsidy of Rs. 133 Crore during the project period. We have also announced 50 per cent subsidy for Construction of Lift Irrigation Schemes and Installation of Bore Wells. As there is a huge gap between

26/03/2015/1610/RG/AG/2

the irrigation potential created and actual water reaching farmers' field, our thrust is on Command Area Development. A Standing Committee headed by Agriculture Minister with the Secretaries of concerned Departments along with Experts on Irrigation will be constituted to take decisions with regard to maximum utilisation of the irrigation potential.

There is also a proposal for establishment of *'Centres of Excellence for Vegetable Nursery Production'* to promote off season vegetables. We propose to provide additional subsidy for High Tech Poly-Houses. With a

view to provide insurance cover to farmers and Agriculture labourers, we propose to launch a new scheme called *'Mukhya Mantri Kissan evam Khetihar Mazdoor Jeevan Suraksha Yojana'*.

Keeping with the hilly terrain of our State, Another area of our focus is Horticulture for which adequate emphasis has been given on Quality Root-Stocks for apple, Pollination and latest techniques of Orchard Management. Freight Charges for Flower Packets have been reduced by 50 per cent.

Safe Drinking Water Supply is another thrust area of this Budget. We propose to provide the Water Treatment Units/Filter Beds in the all the left out 532 Water Supply Schemes. The construction of Water Treatment Plants will also be made compulsory for each water supply scheme in future.

On the power side, apart from hydro-power, we intend to give emphasis on Solar Energy. We will reform our Solar Policy to make investments easy. Solar Projects will be treated as Industrial Projects. Tariff on projects up to 5 MW capacities will be regulated and approved by State Electricity Regulatory Commission and the entire power will be purchased by the HP State Electricity Board Limited.

26/03/2015/1610/RG/AG/3

The Budget also amply indicates our approach towards promotion of industries in the State. Various concessions on Electricity Duty and VAT have been extended to the entrepreneurs. State of the Art Industrial Areas will be set up in Kandrauri in Kangra and Pandoga in Una under the MILUS Scheme of Government of India. Adequate funds have been earmarked for development of Infrastructure in Industrial Areas.

The Government also proposes to formulate a new Scheme called, *'Entrepreneur Development Scheme'* to develop entrepreneurship among the local youth in the State. We have proposed that Green Categories of Industrial Projects, not requiring environmental clearance, will straight-away be granted *'Consent to Establish'* under Water and Air Act on the basis of self-certified application.

Technical Education is the need of hour. More ITIs have been proposed to be opened. Any organisation, which sets up ITI in Tribal, difficult and backward areas, will be given special concessions. 10 State of the Art ITIs, will be opened. We propose to constitute HP Skill Development Corporation. We also propose to open a Skill University in Himachal Pradesh. Besides, a College of Fine Arts has also been proposed to be opened in the State.

On the Health front, we have proposed launching a new Scheme called *'Mukhya Mantri State Health Care Scheme'* for treatment of both the basic and critical ailments for Ekal Naaris and citizens above 80 years of age not covered under RSBY or any other Medical Reimbursement Scheme, irrespective of their income level.

Contd. By AG in English . . .

26/03/2015/1615/MS/AG/1

Chief Minister Continued . . .

We are a Welfare State. The welfare of people, especially the poor and vulnerable section of the Society weighs heavily in our minds. Be they the SCs/STs, OBCs, BPL Families, Ekal Naaris, Senior Citizens, Physically or Mentally Disabled, all have been at the centre-stage of this Budget.

This is both a welfare and development oriented budget. I do not know, what other direction is sought in the budget.

Speaker Sir,

I चिरागों की इफाज़त करते-करते।
हवा का रूख बदलना आ गया है॥
कहां तक आग बरसाएगा सूरज।
हमें शोलों पर चलना आ गया है॥

Continued by AG in English . . .

26032015/1620/AG/1

Chief Minister Continues . . .

It has been said that there is discrepancy of figures in English and Hindi version of Economic Survey. This issue was raised by Prof. Prem Kumar Dhumal.

Speaker Sir, the Leader of Opposition has pointed out that the figures of percentage change of Food Grain Production in Economic Survey does not match in English and Hindi. In English, in 2012-13, it is mentioned (-) 0.2 and for 2013-14, it is 2.3, whereas in Hindi, it is mentioned as 2.3 and (-) 0.2. The Leader of Opposition, who has been the Chief Minister for two tenures has pointed out a small clerical error in Economic Survey, which itself shows that he could not find anything worthwhile to point out against the Budget 2015-16.

Mr. Speaker, Sir, issue has also been raised that there is a mention about outsourcing of DPRs in IPH and PWD and there is no budget provision for the same. Prof. Prem Kumar Dhumal, Shri Ravinder Singh and Shri Suresh Kumar have pointed this out.

Speaker Sir, the Hon'ble Members may see the Budget Provision for Outsourcing of DPRs in Demand No. 10 of PWD at Page No.41 & 42 and Demand No.13 of IPH at Page No. 28.

An issue has also been raised that no reference to 20- Point Programme performance for the year 2012-2013 and 2013-2014 has been made.

26032015/1625/ AG/1

Chief Minister continues . . .

Issue was also raised that as per Budget Speech of 2014-15, Water ATMs were to be installed at important Tourist destinations and the current year's Budget Speech has not any mention about the progress in this regard. This was also stated by some Members of the Opposition.

Speaker Sir, we honour our commitments. I may inform the Hon'ble Members that Water ATMs have already been installed at four places namely the Ridge (Shimla), Vikas Nagar (Shimla), Mata Chintpurni Temple (Una) and Dari (Dharamshala). 2,008 Water ATM Cards have been sold to the consumers of these areas.

Besides, a MoU for installing Water ATMs at Old Bus Stand, Shimla and HRTC Bus Stand, Mandi have also been signed with M/s. Piramal Water Private Limited, Ahmedabad and Gujarat.

Issue was also raised that Hon'ble Chief Minister had talked of opening Lok Mitra Kendras in Himachal Bhawans at New Delhi and Chandigarh and it is not clear whether these Kendras have been opened or not. This was stated by Prof. Prem Kumar Dhumalji.

I would like to inform the Hon'ble Leader of Opposition that as per announcements made, Lok Mitra Kendras have been opened both at Delhi and Chandigarh. Lok Mitra Kendra has started functioning at Delhi from August, 2014 and at Chandigarh from January, 2015. In Himachal Pradesh, there are 2,033 Lok Mitra Kendras, which are providing various services like; Electricity Bill Collection, IPH Water Bills Collection, Issuance of the HRTC Bus Tickets, Jamabandi and Shajra Nasab, Printing of Aadhaar Card, etc., to the people.

Issue was also raised that Allocation under RIDF reduced from Rs. 765 Crore to Rs. 459 Crore for the year 2015-16.

26032015/1625/ AG/2

I would like to apprise the Hon'ble Members of this August House that there is an increase in the allocation of Budget under RIDF for the year 2015-16. Rs. 765 Crore was the loan sanction targets for 2014-15, which is higher than the loan sanction target of Rs. 496 Crore of 2013-14. The Budget provision of Rs. 459 Crore has been provided for 2015-16 under RIDF Programme, which is higher than the 2014-15 Budget provision of Rs. 394 Crore. Therefore, it is not correct to say that the provision under RIDF has been reduced in the 2015-16 Budget.

Shri Prem Kumar Dhumal, Shri Randhir Sharma, Shri Inder Singh and Shri Narender Thakur raised the issue that the provision for capital outlays has reduced from the year 2011-2012 onwards.

Mr. Speaker, Sir, the Capital Outlay in 2012-13 was Rs. 1,970 Crore in 2013-14, it was Rs. 2,063 Crore in 2014-15, it is Rs. 2,528 Crore and in 2015-16, it is proposed to be Rs. 2,950 Crore. Thus, there is a continuous increase in the Capital Outlays in the State.

Contd. By JT in English . . .

26032015/1630/JT/1

Chief Minister Continues. . .

Issue has been raised that the provision kept for eradication of Lantana remained unutilised.

Speaker Sir, the programme for eradication of Lantana grass was started from the year 2009-10. From 2009-10 to 2012-13, only 6,477 hectares area was cleared from Lantana. Whereas, in 2013-14, 5,000 hectares area has been cleared off from Lantana grass with an expenditure of Rs. 878 Lakh. In 2014-15 till 31st December, 2014, 6,859 hectares area has been cleared off from Lantana grass with an expenditure of Rs. 774 Lakh. A new technique of Cut-Root Stock is being used for removal of Lantana grass. Afforestation is being done in the area freed from Lantana so that there is no further growth of this weed.

Prof. Prem Kumar Dhumalji and Shri Ravinder Singh stated that there is no clarity on Mixed Land Use announced in the Budget Speech and it appears that this is for covering up irregularities committed in the past.

Speaker, Sir, there is no hidden meaning behind allowing the Mixed Land Use, which the Opposition is trying to read. The intention of the Government is to give relief to the common man, who at present has to run from pillar to post to get permission for change of land use. Due to hill topography and scarce area, Mixed Land Use is desirable. Recently, the Secretary, Ministry of Urban Development, Government of India, vide his Letter dated 8th January, 2015, has impressed upon the States that

the Mixed Land Use should be encouraged. While NDA Government at national level is promoting Mixed Land Use, our friends of the Opposition here are raising their eye-brows on this. I may say here that this decision of the Government will have the prospective effect and it has nothing to do with earlier cases.

26032015/1630/JT/2

Issue has also been raised that the progress of Apple Juice Concentrate Unit in District Shimla by HPMC announced in the budget 2014-15 is not satisfactory.

Hon'ble Speaker, Sir, I would like to apprise that a proposal for setting up an Apple Juice Concentrate Plant in District Shimla has been cleared by technical committee of APEDA, Ministry of Commerce, Government of India. The project proposal shall now be placed before APEDA Board for approval. I would also like to inform that a project on up gradation and modernisation of fruit processing plant at Parwanoo has been sanctioned by APEDA for Rs. 8 Crore. The work of the two projects on vegetable pack house and cold storage at Nadaun and Ghumarwin has been awarded and will start soon.

Issue was also raised that Economic Survey of 2014-15 shows a decrease in the tourist arrivals in Himachal Pradesh. It was stated by many Members including Prof. Prem Kumar Dhumal, Shri Randhir Sharma, Shri Suresh Kumar, Shri Ravinder Singh and Smt. Sarveen Chaudhary.

Contd. By JT in English . . .

26032015/1635/JT/1

Hon'ble CM continues . . .

It is true that the tourist arrival declined in the year 2013. This decrease was mainly due to the natural disaster that took place in June, 2013 both in Uttrakhand and Himachal Pradesh. In Himachal Pradesh, the whole of Kinnaur & Lahaul-Spiti Districts and parts of Kullu, Shimla, Kangra and Chamba were affected badly due to heavy rains, which led to loss of life, property. It created fear psychosis in the minds of visitors thereby resulting in less tourist inflow. In the month of June, 2013, there was a decrease of 32.33 per cent in tourist arrival. The overall decline in the year 2013 was 6.30 per cent. However, in 2014, the tourist inflow has increased to 7.83 percent. Therefore, the decrease in 2013 was attributed to the natural disaster only, which was beyond the control of Government.

Issue was also raised that the Crime Rate has increased from 15,937 in 2012 to 17,122 in 2014 as per the Economic Survey.

Speaker Sir, the Hon'ble Members, who have raised this issue are using the numbers that suite them. In fact, the incidence of crime was higher in the year 2011, when the number of crimes registered was 18,875 mentioned in the same Table of the Economic Survey, which Leader of Opposition has referred to. The number of crimes registered in 2014 is 17,122, which number is even lesser than the crimes recorded in the year 2009, when the number of crimes registered was 17,418. I hope the Hon'ble Members who have stated this stand corrected.

Issue was raised that announcements made in Budget Speeches of 2013-14 & 2014-15 have not been fulfilled and the progress made in the announcements so made does not find mention in this year's Budget

Speech and it has also been alleged that a lot of promises made in the Congress Manifesto have not been honoured.

26032015/1635/JT/2

Speaker Sir, it appears that Hon'ble Leader of Opposition and others who raised this issue are concentrating more on the Speeches of 2013-14 & 2014-15 instead of the current year's Budget Speech. The announcements made in any of the Budget Speech become Budget Assurances, which are reviewed separately from time to time. It is not necessary to make mention of the past announcements in the current Budget Speech. It seems that they did not have much to say on the Budget for the year 2015-16 and are digressing from the main Budget discussions.

Any Party's Manifesto is for five years. We have completed just two years in the office and it is for anyone to see that most of the promises made in the Manifesto have been fulfilled in first two years of the Government itself.

If I start mentioning all the achievements made and the new announcements made now, it will take more time than my Budget Speech.

Issue has also been raised that the Government should increase the Daily Wage Rate so that the Wage Rate under MGNREGA could increase.

Speaker Sir, we increased Daily Wage from Rs. 150 to Rs. 180 in two years. However, the Government of India has been providing a Daily Wage of Rs. 154 only to the MGNREGA Workers. To say if we increase our Daily Wage here, accordingly the Daily Wage rate of MGNREGA will also be raised. This is a fallacy. These Wage Rates under MGNREGA

were notified by the Government of India in February, 2014. No further hike has been given by the Government of India in the Daily Wage of MGNREGA Works, even though we, in the State, have increased Daily Wage by Rs. 30 per day in the first two years of our Government. We have requested the Government of India to raise the Wage Rate under MGNREGA equal to

26032015/1635/JT/3

minimum wages in Himachal Pradesh, but the Central Government has not agreed to this.

Contd. By JT in English . . .

26032015/1640/JT/1

Hon. CM Continues . . .

Speaker, Sir, it was also stated that unemployed feel cheated and Skill Development Allowance is a hoax, as bogus Skill Providing Companies have mushroomed in the State.

Speaker Sir, while announcing the Skill Development Allowance Scheme in the Budget Speech of 2013-14, I had specifically made a mention of a popular saying, which I would like to reiterate:

"Give a man a fish and
you feed him for a day,
Teach a man to fish and
you feed him for a lifetime".

This is the importance of technical training.

True to this saying, we launched this Scheme, where under an allowance of Rs. 1,000 per month is being provided to the educated unemployed youth to increase their employability by improving their skills. This allowance is being given at the increased rate of Rs. 1,500 per month to the persons with disabilities. 64,389 youth have availed benefit under this Scheme so far. A budget outlay of Rs. 100 Crore has been proposed for Skill Development Allowance in 2015-16 also.

Further, in the current Budget Speech, I have announced that HP State Skill Development Corporation will be set up in the State to co-ordinate the Skill Development Schemes of the State. The State Government also proposes to access funding through the Asian Development Bank to facilitate providing quality and certified skills to the unemployed youth to pave way for their gainful employment.

26032015/1640/JT/2

Aiming at employment, demand driven trades are proposed to be introduced in the existing ITIs. Besides, 10 State of the Art ITIs will be opened in the State to impart training in the group of inter-related trades.

Also, Vocational Education is being extended to 100 more Government Senior Secondary Schools. We also propose to invite reputed organisations to open a Skill University in Himachal Pradesh.

Besides, we have started various new Schemes and enhanced the budget provisions under Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry, Industries, Technical Education, etc., which is going to generate more employment opportunities in the State.

Skill Development Allowance is given only to the youth undergoing training in the Government recognised Institutions or in the private sector Institutes duly empanelled/approved by the District Level Committees constituted for the purpose. 650 Government and non-Government Institutions have been approved for granting the Certificates under the Scheme.

District Level Committees, after scrutinizing the applications, have rejected 1,181 Institutions. I would like to make it clear here that no financial assistance what-so-ever is being given to any Institution imparting training under the Skill Development Allowance Scheme. The Skill Development Allowance is directly transferred to the Bank Accounts of eligible candidates through RTGS.

Issue was also raised that there is nothing concrete for employees in the Budget and withdrawal of Extension will affect promotions.

Mr. Speaker, Sir, they have raised the issue that nothing tangible has been done for the employees in the Budget of 2015-16, which is merely a criticism for the sake of criticism. My Government has always been the well wisher of employees and despite financial constraints, we have given due

26032015/1640/JT/3

benefits to our employees from time to time. We have made a salary provision of Rs. 8,284 Crore for next year to cater to salary, increments, promotions and DA in 2015-16 Budget.

Contd. By JT in English . . .

26032015/1645/JT/1

Hon. CM Continues . . .

Bare reading of this budget would reveal that Contractual employees, who were earlier regularised after six years, will now be regularised after five years. Similarly, Daily Wagers, who would complete seven years of service as on 31st March, 2015, will be regularised and Part-Timers, who complete eight years of service as on 31st March, 2015, will be made Daily Wagers.

The daily wage, has been increased by Rs. 600 per month last year and 300 rupees per month in this Budget.

We increased the income limit for compassionate appointments from Rs. 1 Lakh per annum to Rs. 1.25 Lakh per annum in 2014-15 and this year, we have increased it further to Rs. 1.50 lac per annum.

The remuneration of Home Guards, which was increased last year Rs. 1,050 per month, has now been further enhanced by Rs. 600 per month.

The services of Para-Teachers have been regularised and those of PTA Teachers, have been taken on Government Contract. My friends in the Opposition, who are now claiming to be well wishers of employees must not forget that they had terminated the services of PTA Teachers during their tenure. We have not only re-engaged them, but also enhanced their GRANT.

If my friends have read the Budget document carefully, they would find that we have covered all the Daily Waged Workers, Part-Time Workers, Aanganwari Workers/Helpers and Mid-Day Meal Workers under

the *"Mukhya Mantri State Health Care Scheme"* so as to provide them the basic and critical health care. This will benefit thousands of such employees.

My Government has proposed to provide Rs. 30 Crore for construction of new residences for the Government Employees especially the Class-III & Class-IV. Also Rs. 15 Crore will be provided for the Repair 26032015/1645/JT/2

& Maintenance of Government Residences. Apart from this, Rs. 20 Crore has been earmarked for Police Housing.

Hon'ble Members expressed concern about those employees, whose promotion was affected due to extension in service. I am pleased to inform that the State Government has already ordered that such employees will be given extension till 16th April, 2015 so that they can get the benefit of promotion, if due.

All what I have said is sufficient to prove that the contention of my friends in the Opposition is without substance and far from the facts.

Contd. By AG in English . . .

26032015/1650/ AG/1

Hon. CM continues . . .

Speaker, Sir, it has also been stated that Budget lacks schemes for the Generation of Employment.

I would like to inform Hon'ble Members of Opposition that various schemes have been mentioned in the budget for providing direct and indirect employment to youths/farmers in the State. I would like to mention some of these schemes for the information of Hon'ble Members

of Opposition. A new World Bank Project on *'Post-Harvest Management Practices of Horticulture Crops'* amounting to Rs. 1,000 Crore (at Point No. 29 of Budget Speech), *'Rajiv Gandhi Micro-Irrigation Scheme'* amounting to Rs. 154 Crore (at Point No. 33), Rs. 60 Crore for Off-Season Vegetables (at Point No. 37), *'Dr. Y.S. Parmar Kisan Swarozgar Yojana'* (at Point No. 38), *'Establishment of Centres of Excellence for Vegetable Nursery Production'* (at Point No. 39), *'Setting up 20,000 Vermi-Compost Units'* (at Point No. 40), *'Uttam Chhara Utpadan Yojana'* for bringing an area of 25,000 hectares under fodder production (at Point No. 42), *'Apple Rejuvenation Project'* for covering an additional area of 1,000 hectares' (at Point No. 46), *'Reduction of Freight Charges on Flowers Packets'* by 50 per cent in HRTC Buses (at Point No. 49), 60 per cent *'Subsidy Scheme to set up Milk Processing and Chilling Facilities'* (at Point No. 56), various incentives to Industries to promote employment. Apart from above, a large number of Skill Up-gradation Programmes / Schemes have also been proposed in the budget with a view to improve the skill of the youths so as to increase employability and employment.

26032015/1650/ AG/2

These schemes announced in the Budget 2015-16 will directly and indirectly help in generating additional employment in the State and boost the economy of the farmers.

Contd. By AG in English . . .

26032015/1655/ AG/1

Hon. CM Continues . . .

It was also stated by Shri Maheshwar Singh that Development of Cold Storage Facility in the Marketing Yards should be provided instead of road construction activity by the HP Marketing Board.

The Hon'ble MLA has suggested establishment of Cold Storages in Marketing Board Premises/Yards. We have earmarked Rs. 5 Crore for HPMC for converting its Cold Stores at Rohru, Odi and Patli Kuhal into CA Cold Stores. First time, we have provided Rs. 10 Crores in the State Budget for the HP Marketing Board. My Government will keep Hon'ble Member's suggestion in view, while carrying out infrastructure development under the auspices of HP Marketing Board.

Speaker, Sir, Smt. Sarveen Chaudhary raised the issue of safety of women.

I would like to assure the House that our Government attaches highest importance to women safety. I, in my Budget Speech for 2013-14, announced that at least 20 per cent Women will be recruited at Constable and Sub-Inspector Level in the Police Force. We are posting Women Police Officers in every Police Station of the State, as I have mentioned in the Budget speech also. Three All Women Police Stations have been made functional in Dharamshala, Shimla and Mandi. Two more are being opened in Baddi and Kullu in 2015-16. I am sure such confidence building measures will further enhance Women Security. I have also directed the Police Force especially in towns and in crime prone areas to have regular patrolling by the Police to see that crime against women, crime against children particularly, and crime in general is prevented and if it happens it is detected at the earliest.

Issue was also raised that the Congress Government is trying to take credit for the central schemes.

Speaker, Sir, most of the Central Schemes such as; MNREGA, RUSA, SSA, RIDF, etc., were started by the UPA Government. In fact, the present NDA Government has reduced the Central Allocation for most of such Central Schemes, which will affect the state adversely. I am referring to the schemes which were started by the NDA Government such as MNREGA, RUSA, SSA and RIDF. As I said the allocation has been reduced which will affect their efficacy. Central Government has discontinued many Central Schemes including JNNURM, Modernisation of Police Forces and Backward Region Grant Fund Scheme and the allocation has also been reduced for these schemes which will adversely affect the development in the districts of Chamba and Sirmour.

It has also been stated by some Opposition Members that the financial health of the State is deteriorating and the State Government is not able to pay Salary to the employees. Don't worry? This is not a fact. All the employees and all the Hon'ble Members will get the allowances and salaries in time for full year. It is criticism for the sake of criticism and shows the ignorance.

Speaker: Now, the House is extended upto 5.30 pm.

Chief Minister: Speaker, Sir, Prof. Prem Kumar Dhumal, Shri Ravinder Singh, Shri Randhir Sharma and Shri Govind Sharma said that the financial health of the State is deteriorating and the State Government is not able to pay salary to the employees.

26032015/1655/ AG/3

Speaker Sir, the State Government has released all the due benefits to the employees from time to time. The State Government has ordered release of 107 per cent DA, which is equal to the Central Government. All the State Government employees are getting salary on due dates.

Contd. By AG in English . . .

26032015/1700/ AG/1

Hon. CM Continues . . .

And all the other committed liabilities of the Government are being fulfilled within the time-frame. So, to say that Himachal is getting financially bankrupt and is not able to finance this or that is nothing but a canard and I reject it.

Issue was also raised about rail links in the State and it has been stated that there is nothing much for rail lines has been visible in the Budget.

Hon'ble Members have expressed their concern regarding Construction of Rail Lines in Himachal Pradesh. Speaker Sir, I would like to remind them that it was my Government, which took the historic decision on 5th December, 2013 to share the 50 per cent cost of *'Chandigarh - Baddi Rail Line'* and 25 per cent cost of *'Bhanupalli - Bilaspur - Beri Rail Line'*. We are committed to provide our share of these Rail Lines in 2015-16, as per the actual expenditure by the Railways.

Issue was also raised that the Budget Document mentions that out of Rs. 100 of State Revenue Receipts, Rs. 66 will come from Central

Grants and yet the State Government has not said even a word of thanks to the Central Government. This was stated by Prof. Prem Kumar Dhumal, Shri I.D. Dhiman and Smt. Sarveen Chaudhary.

Speaker Sir, the devolution of Taxes & Grants from Centre to States is done on the basis of recommendation of the Finance Commission. Thus, the devolution has taken place to Himachal as well as to all other States.

Speaker Sir, I am ready to thank the Central Government if the Central Government start funding the Annual Plan of Rs. 4,800 Crore of State Government for 2015-16; if the Central Government removes the condition of

26032015/1700/ AG/2

Revenue Raising and Fiscal Consolidation imposed on release of Revenue Deficit Grant to the State; and if the Central Government restores various Centrally Sponsored Schemes discontinued from 2015-16. Certainly I will be first to not only thank, but profusely thank the Central Government. Since nothing of the sort has happened, I hope it will happen. I will only thank when this will happen.

Speaker, Sir, it has also been stated by Shri Inder Singh that the people above 80 years of age are not getting pension which was announced in the Budget Speech of 2014-15.

I had announced pension to all the persons above 80 years of age irrespective of their income in my last year's Budget Speech. I am happy to inform that 46,247 persons above 80 years of age have availed pension at the rate of Rs. 1,000 per month in the current financial year.

I have already announced in my Budget Speech that all pending pension cases will be sanctioned pension *w.e.f.* 1st April, 2015. The State Government has kept a budget provision of Rs. 317 Crore for disbursement of Social Security Pension in 2015-16.

Contd. By AG in English . . .

26032015/1705/ AG/1

Hon. CM Continues . . .

Issue was also raised that the Budget Speech mentions only about re-tendering of works of *'Theog - Kotkhai - Hatkoti - Rohru Road'* and *'Ghumarwin - Sarkaghat Road'*, but it is silent about the progress.

Speaker Sir, I may like to inform the Hon'ble Members that in *'Ghumarwin - Sarkaghat Road'*, 27 percent of the work has been completed with an expenditure of Rs. 53.5 Crores. Out of ten Bridges, one has been completed, work on eight Bridges is in progress and the work of remaining one Bridge will be taken up shortly. The work of this Road is likely to be completed within the scheduled time.

Regarding *'Theog - Kotkhai - Hatkoti - Rohru Road'*, the progress of the work has picked up and up to date expenditure is Rs. 32.27 Crore. All out efforts are being made to expedite the work and to complete the same within the scheduled time.

It was also mentioned that there is no mention of progress of tunnels announced in the Budget of 2013-14 and 2014-15.

I would like to inform the Leader of Opposition that Detailed Project Reports for *'Bangana - Dhaneta'* and *'Bhubujot'* Tunnels have been

received from the Consultants. Expression of Interest for appointing Transaction Advisory Services for PPP Work of *'Bangana - Dhaneta'* Tunnel is being issued shortly. With regard to *'Holi - Utrala Tunnel'*, I am to inform that the Tunnel has not been found economically viable, as per Draft Feasibility Report of the Consultant. Regarding *'Tissa - Killar'* and *'Chamunda - Holi'* Tunnels, the Sutlej Jal Vidyut Nigam Limited has submitted Draft pre-feasibility study Report for both the Tunnels, which are under examination. Hence, the State Government has taken steps as per the Budget announcement.

26032015/1705/ AG/2

Issue was also raised that the petrol and diesel prices have been reduced by the Centre but the State Government has increased VAT on petrol and diesel.

Speaker Sir, the crude oil prices have come down by nearly 58 per cent since June 2014, touching a level of US $ 46 a barrel in January, 2015 from US $ 109 in June, 2014. However, the NDA Government in Centre have reduced the Petrol and Diesel Prices since August, 2014 just by 20 per cent. Further, the Central Government has increased the Excise Duty on petrol and diesel heavily. If the Members of Opposition are genuinely interested in reduction of rates to pass on the benefits to the people of the State, they should impress upon the NDA Government in Centre to reduce the petrol & diesel prices in proportion to the reduction in International Prices. Himachal Government has increased VAT on petrol and diesel just by 2 per cent in the last two years. I would also like to inform the Hon'ble Members that VAT on petrol and diesel in Himachal Pradesh is less than Punjab.

Issue was also raised that the Government spent only an amount of Rs. 8,864 Crore against the size of Rs. 10,300 Crore of the Tenth Five Year Plan and how will the Government fill the gap of Rs. 5,800 Crore during the last Annual Plan to reach the figure of Rs. 22,800 Crore as approved for 12th Five Year Plan. It was stated by Shri Ravinder Singh, Shri Randhir Sharma and Shri Inder Singh.

Sir, during 2003-04, the committed liabilities amounting to Rs. 829 Crore on account of Salaries, etc., were transferred to the Non-Plan side. These liabilities continued to be part of Non-Plan during the entire Tenth Plan period and amounted to Rs. 3,325 Crore in all. It is because of this reason that an expenditure of Rs. 8,864 Crore only was incurred against the outlay of Rs. 10,300 Crore during Tenth Five Year Plan. Had this liability continued

26032015/1705/ AG/3

to be part of the remaining four Annual Plans of the Tenth Five Year Plan, total Plan expenditure would have exceeded the approved plan size of Rs. 10,300 Crore by an amount Rs. 1,879 Crore. The Congress Government had actually improved the quality of Plan Expenditure by shifting the committed liabilities to the Non-Plan side.

If the NDA Government in the Centre has discontinued the funding of State Plan from 2015-16, Annual Plan of Himachal Pradesh will have to be funded from the State's own resources. We will be happy to increase the Plan size, if the NDA Government at Centre start funding the State Annual Plan, as it used to be done during the erstwhile Planning Commission.

Contd. By JT in English . . .

26032015/1710/JT/1

Hon. CM Continues . . .

Issue was also raised that the electricity generation has decreased from 1,905 Million Unit to 1,815 Million Unit. This was stated by Shri Prem Kumar Dhumal.

The data, which has been presented by the Hon'ble Member in the House is for the year 2011-12 and 2012-13. The decrease in the generation is in the year 2012-13, when the your Government was in power. In the year 2013-14, Electricity generation has increased to 1,951 Million Unit thereby showing a increase of 7.5 per cent.

Issue was also raised that the per capita income has increased to Rs. 1,04,943 per annum, which is appreciable, but if seen in terms of percentage rise of per capita income, the same was higher during our tenure from 2007-2012. This was stated by Prof. Prem Kumar Dhumal.

I would like to say, as I said earlier, the Gross State Domestic Product and Per Capita Income is prepared at current and constant prices. At current prices inflation plays an important role. In the year 2008-09 to 2012-13, the inflation was above 8 per cent and touched the level of 10.9 per cent in the year 2010-11 (April, 2010). The price rise impacts Per Capita Income also. If we see the Per Capita Income in real terms, it has increased only by 5 per cent in the period of 2008-09 to 2012-13. The Per Capita Income in 2013-14 has increased by 5.7 per cent, which is higher as compared to the Per Capita Income during 2007-2012. For the first time, the Per Capita Income has touched the six figure mark and is estimated at Rs. 1,04,943 which is a land mark by itself. I hope the position is clear.

26032015/1710/JT/2

Sir, issue was also raised that no measures suggested for Resource Mobilization. The Government in the State cannot run on borrowings alone for long. There is no mention about the Report of the Cabinet Sub-Committee on Resource Mobilization.

Mr. Speaker, Sir, my friends on the other side, fully well know that Himachal is a resource stressed State. There is a little tax base in the State. The people of the State are not in a position to bear any more taxes. However, the State Government has been making efforts to increase Tax Revenue through efficient Tax collection. The Tax collection of the State Government will increase from Rs. 5,338 Crore Budget Estimate of 2014-15 to Rs. 6,341 in 2015-16, which is a handsome increase of 18 per cent, whereas the Tax Revenue increase of Government of India from 2014-15 to 2015-16 is only 15.8 per cent.

Borrowings are a part of the developmental expenditure and have been resorted to from time to time by the Government of the day. Whatever borrowings are raised, are with the consent of Government of India within the framework of Constitution of India. No off-budget borrowings have been resorted to.

Speaker Sir, we are alive to the need of resource mobilization and that is why we have constituted a Cabinet Sub-Committee on Resource Mobilization. The report has since been received and will be placed before the Cabinet shortly. Needful action will be taken after a decision is taken by the Cabinet.

Contd. By JT in English . . .

26032015/1715/JT/1

Hon. CM Continues . . .

Sir, issue was also raised that we thank the Hon'ble Chief Minister for enhancing the *'Vidhayak Kshetriya Vikaas Nidhi'* from Rs. 50 Lakh to Rs. 70 Lakh. However, conditionality of executing of Command Area Development Works should be removed. This was said by Prof. Prem Kumar Dhumal and many other Members.

Speaker Sir, Hon'ble Members from both sides, have demanded removal of the condition of spending at least Rs. 20 Lakh on the execution of Command Area Development Works from *'Vidhayak Kshetra Vikas Nidhi'*. I accede to their request and announce that this condition will be removed. The Hon'ble Members will be at liberty to utilize the Nidhi as per their priorities in the constituencies. I further announce that *'Vidhayak Nidhi'* will be raised from Rs. 50 Lakh to Rs. 75 Lakh in 2015-16 .

I also announce that the Discretionary Grant of MLAs will be raised from Rs. 2 Lakh to Rs. 4 Lakh on the demand of all the MLAs of this House.

I also announce to open a Fire Post at Baijnath in addition to three mentioned in my Budget Speech.

The PTA Teachers are getting Grant-in-Aid equal to 75 per cent of what is being paid to the Contract Teachers. I announce to raise it to 90 per cent from 75 per cent.

Mr. Speaker, Sir, I have left many parts of my speech which may be considered as read and placed on the Table of the House just to save time, which are as under:

26032015/1715/JT/2

Issue was raised by Shri I.D. Dhiman, Smt. Sarveen Chaudhary, Shri B.K. Chauhan, Shri Ravinder Singh, Shri Virender Kanwar, Shri Randhir Sharma, Shri Suresh Kumar, Shri Bikram Singh and Shri Hans Raj that schools have been opened, where there are even two three students and the quality of education is deteriorating in the State and number of students in Government Schools are decreasing.

Speaker Sir, it has always been the priority to provide easy access to little school going children. The hill topography and difficult conditions of the State require opening a school even for a few children. We are providing requisite infrastructure in the schools. To improve the quality of Education, the Government has re-introduced examination of 5th to 8th standards. The State Government will make efforts to increase the enrolment of students in government schools During the financial year 2015-16, the State has provided Rs. 5,000 Crore for Education, which is 17.60 per cent of the total budget.

Issue was also raised by Shri Randhir Sharma and Shri Ravinder Ravi that fiscal health of the Government is so bad that money had to be withdrawn from Developmental Blocks.

Speaker Sir, there are general guidelines that money should not be drawn from Treasuries and parked idle in the Bank Accounts for long. The Development Blocks had money, which was lying in Bank Accounts from a long time . The money, which was not required for immediate disbursement was to be kept in public ledger account (PLAs) of the concerned BDOs. BDOs are Administrative Officers of the PLAs and can withdraw money and spend the same at any time, when required. No

developmental work has suffered and will not be allowed to be suffered for want of funds.

Issue was also raised by Shri Prem Kumar Dhumal, Shri I.D. Dhiman, Shri Randhir Sharma, Smt. Sarveen Chaudhary, Shri Virender Kanwar, Shri

26032015/1715/JT/3

Ravinder Singh, Shri B.K. Chauhan, Shri Hans Raj and Shri Baldev Singh Tomar that like they had given 4 CFL Bulbs free to the people, LED Bulbs should also be given free.

Speaker Sir, Hon'ble Prime Minister launched a National Programme for LED based energy efficient Street Lights and domestic lights on 5th January, 2015. This programme is being implemented by M/s. Energy Efficiency Services Ltd., a Public Sector Entity under Ministry of Power, Government of India, who have developed Domestic Energy Efficient Lighting Programme. Himachal Pradesh is one of the few States, which has adopted this Scheme. The Government of India has proposed to give it on cost basis. The bills of domestic consumers will get reduced by way of energy saving which will off-set the cost of Bulbs.

I would like to inform the House that distribution of CFL Bulbs resulted in a net loss of Rs. 70 Crore to HPSEB, as the previous Government did not provide any fund to the HPSEB in lieu of distribution of CFL Bulbs.

Issue was also raised by Shri Randhir Sharma, Shri Virender Kanwar, Shri Ravinder Singh and Shri Inder Singh that debt raised during

2013-14 and 2014-15 has been Rs. 8,612 Crore, which is more than the loan raised by BJP Government during its entire tenure from 2007 to 2012.

Speaker Sir, during the recent years, there has been sharp reduction in the Revenue Deficit Grant due to adverse recommendations of the 13th Finance Commission. Further, huge financial liability was caused to the State due to increased Salary burden because of implementation of the revision of pay-scales in the State by following the recommendations of the Punjab Cabinet Sub-Committee in undue haste.

During the period March, 2008 to March, 2013, there has been increase of Rs. 7,466 Crore in the Loan liability of the State Government. Loan amount of Rs. 1,838 Crore was converted into Guarantee in the year

26032015/1715/JT/4

2009-10. As such, the actual Loan taken in the last five years is Rs. 9,304 Crore, whereas during the period April, 2003 to March, 2008, Loan liability increased only by Rs. 8,032 Crore.

Contd. By JT in English . . .

26032015/1720/JT/1

Hon. CM Continues . . .

During 2013-14 and 2014-15, the Net Debt increased is around Rs. 6,000 Crore.

Issue was also raised by Shri Prem Kumar Dhumal, Shri Randhir Sharma and Shri Inder Singh that Non-Tax Revenue has declined by Rs.

507 Crore *i.e.* from Rs. 1,915 Crore in 2011-12 to Rs. 1,408 Crore in 2013-14 (Revised).

Sir, the receipts from Upfront Premium and Sale of Free Power have been the major sources of Non-Tax Revenue. The Upfront Premium is one time receipt. Out of the total exploitable potential of 23,000 MW, Projects with aggregate capacity of 22,551 MW have already been allotted. Upfront Premium is received at the time of allotment. Therefore, little revenue is being generated on account of upfront premium now.

Further, the rates of Sale of Power have also been coming down because of the additional capacities created in the neighbouring States and there being a shift in the market power scenario from Sellers Market to Buyers Market. The rate of sale of Power, which was Rs. 7.18 per Unit in 2007-08, has declined to Rs. 2.35 in 2013-14.

Speaker Sir, I have tried to cover most of the issues raised by the Hon'ble Members in my reply. Some points might have been left out, but no Member should doubt our grit and determination to work for all round development of State. We are working with the motto of *'Sarva Kalyan Smagra Vikaas'*. Bare reading of the Budget would reveal that we have taken various new initiatives for the welfare and development of the people of our State. In a democratic set up, there is a big room for discussion and debate. However, criticism should be the objective and not merely for the

26032015/1720/JT/2

sake of criticism. We are working in a right direction and no obstacle can come in our way to deter us from the path of inclusive development of the State.

This Budget is a forward looking Budget full of vision, which should not be viewed myopically by the Opposition.

Speaker Sir, may I conclude by saying;

मिलेगी परिन्दे को मंजिल यकीनन,ये उसके पर बोलते हैं!
रहते हैं कुछ लोग खामोश, पर उनके हुनर बोलते हैं!!

Thank you very much.

Contd. By BJN in Hindi . . .

26.03.2015/1725/negi/jt/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सभी विधायकों का सुझाव मान कर कंडिशनलिटी को खत्म किया है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। डिस्क्रिशनरी ग्रांट भी 2 लाख रूपये से बढ़ा कर 4 लाख किया, इसके लिए भी धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्री जी ,मैंने उस दिन भी कहा था, जो बजट लिखा गया है वह आपने 3 घंटे में पढ़ लिया। आज भी जवाब जैसे लिखा गया वैसे पढ़ दिया। आपने एक बात कही कि 0.02 परसेन्ट और 2.23 परसेन्ट की बात धूमल जी ने उठायी, बड़ी छोटी थी । इकोनोमिक टर्म्ज़ में अगर आप देखें तो 0.02 नेगेटिव हो जाना और 2.23 परसेन्ट की वृद्धि बहुत बड़ी फिगर बनती है, हजारों करोड़ की, जब आप गिनते हैं। ये खाद्य उत्पादन, फूड प्रोडक्शन की फिगर थी जो मैंने उस दिन बोली थी । इसको आपने क्लेरिकल मिस्टेक कह करके खत्म कर दिया। जो केन्द्र से सहायता मिलती थी उसके लिए जो फाइनैंस कमीशन की रिपोर्ट आई आपने कह दिया कि ये तो फाइनैंस कमीशन के कारण हुआ। मैंने यह भी कहा था कि जब 13वां फाइनैंस कमीशन था उसने भी 8.5 परसेन्ट वृद्धि की सिफारिश की थी 31 ,परसेन्ट से 39.5 परसेन्ट डिवोल्युशन का जिक्र किया था। लेकिन यू.पी.ए. सरकार ने केवल एक परसेन्ट माना था और 7.5 परसेन्ट नही दिया था। तो एक रिकमैंडेशन आती है। But Government of India is not bound to accept it in toto. You know too much. आप कई बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं और कई बार आपने फाइनैंस कमीशन की रिपोर्ट देखी है। हर बार सेन्ट-परसेन्ट मानना, यह सारा श्रेय नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार को जाता है जिन्होंने इसमें पूरा माना है।

मुझे बैठे-बैठे एक घटना याद आ रही थी, एक लड़का सफर पर जाता था, कहीं नौकरी करता था और मालिक उसको एक्चुअल किराया देता था और 4 अन्ने की मुंगफली दे देता था कि रास्ते में बस में खाते जाना। दूसरा मालिक अच्छा आया उसने कहा हम तुझे 5 रूपये किराया देते हैं, 4 अन्ने की मुंगफली के बजाय तू 10 रूपये ले ले और आराम से यात्रा कर लेना। वह 10 रूपये को एप्रिशिएट करने के बजाय 4 अन्ने की मुंगफली को याद करता रहा कि वह मिल जाए। आपने कहा कटौती सेन्ट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्ज़ में की है, यह कटौती भारत सरकार ने सेन्ट्रली

26.03.2015/1725/negi/jt/2

स्पॉन्सर्ड स्कीम्ज़ की स्टेट्स की डिमाण्ड पर ही की है। क्योंकि हम चाहते थे कि स्टेट्स स्पैसिफिक प्रोजेक्ट्स बनें। पहाड़ी राज्यों के लिए और चाहिए, मैदानी राज्यों के लिए और चाहिए। मैंने पहले ही कहा था, मैं ज्यादा रिपीट नही करना चाहता। उसमें मैंने टोटल लगाया, आपका 5 हजार करोड़ का फर्क पड़ता है ,जो कम होता है, सेन्ट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्ज़ का, और आपको मिल रहा है 72 हजार कुछ करोड़ । तो आप इसको एप्रिशिएट करिये। इसमें कोई प्रैस्टिज़ बनाने वाली कोई बात नही है। आपने अगली बात कही कि केन्द्र ने रेट कम किये। अगर केन्द्र ने पैट्रोल और डीज़ल के रेट कम किए थे तो आपने उसपर वैट बढ़ा कर रेट और बढ़ायी। और बस किराया नही घटा। जब थोड़ा सा डीजल का रेट बढ़ा था तब एक बार इकट्ठा 30 परसेन्ट का इन्क्रीज हुआ था। कई माननीय सदस्यों ने बात उठायी लेकिन इसपर कोई रिस्पाँस नहीं आया कि आप किराया कम करेंगे । जब किराया बढ़ाती है तो कॉरपोरेशन बढ़ाती है। कम करने में ...(व्यवधान) ...इसी बजट में बाली जी, फिर आपने छेड़ दी बात, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सैंकड़ों करोड़ की ग्रांट आपके कॉरपोरेशन को दी है और अब कॉरपोरेशन को किराया रिडयूस करना चाहिए और लोगों को सहायता देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पर विधायकों ने उठाया था और सचमुच में मुख्य मंत्री महोदय, बात गम्भीर है। डिवलपमैन्ट ब्लॉकों से एस.डी.पी. का पैसा, विधायक क्षेत्र विकास निधि, विकास में जन सहयोग आदि की तो पैसा स्टेट गवर्नमैन्ट का होता है वो तो आपने मंगवाया ही, आपने हर ब्लॉक से मंगवाया है। लेकिन मुख्य मंत्री जी इसमें जो एक चीज़ हुआ है, या तो इंस्ट्रक्शन्ज़ यहां से गई जो

नीचे हुआ। एम.पी.लैड का पैसा, how can the State Government call it back? ब्लॉक से कि तुम इसे वापिस भेज दो, पैसा चाहिए। मुझे पता है कि पहले भी आप यह करते रहे हैं, 30- 31 मार्च के आसपास कर लो और फिर उसको वापिस भेज दो। तो इसके बारे में आप खामोश रहे।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

/26.03.2015यूके/1/730एजी/ 1

श्री प्रेम कुमार धूमल---जारी---
तो इसके बारे में आप खामोश रहे । शराब के ठेकों की नीलामी के बारे में आप खामोश रहे ।

अध्यक्षः एक मिनट धूमल जी, सदन का समय बढ़ाना है ।

श्री प्रेम कुमार धूमलः हां, आप टाईम बढ़ा लीजिए ।

Chief Minister: Are we starting a second round of debate? In the Budget after the reply by the Government, only voting takes place and no clarification. (Interruption) It is against the customs.

अध्यक्ष : आप अपनी बात खत्म कीजिए । इस पर बहस तो होगी नहीं । Now, the House is extended upto 5.40 pm.

श्री प्रेम कुमार धूमलः थैंक्यू । आपने कहा कि कर्मचारियों से जो हमने वायदे किए थे वे पूरी कर दिए और एक किश्त डी0ए0 की दे दी । जो 10 महीने के बाद मिली है । 4-9-14 जो आपने वायदा किया था, उस पर आप खामोश रहे । मुख्य मंत्री महोदय, आपने कहा कि रोजगार की और ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाएंगी । आपने ही अपने बजट स्पीच में यह कहा कि 47 हजार पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं । तो इरिगेशन में पैसा देंगे या किसी और प्रोजेक्ट में देंगे तो उसमें गवर्नमैंट एम्पलॉयज़ थोड़े होंगे, वे ? तो 5 हजार पोस्टों से काम नहीं चलेगा । ये बातें रह गयी, जो अनआँसर्ड रही हैं । आपने अगली बार कभी इसका जवाब दे देना, जरूरी नहीं है कि आप आज ही इनका जवाब दें । लेकिन आपने जो अभी जवाब दिया, हम उसके बारे में कह रहे हैं । लॉ

एंड ऑर्डर पर आपने कुछ नहीं कहा । वन-कटान पर जो माननीय सदस्यों ने कहा उस पर आप कुछ नहीं बोले हैं । तो बहुत सारी बातों पर आप जो साइलैंस है । तो ये आपकी खामोशी बहुत कुछ कहती है । कुलदीप जी कह रहे थे कि शेर हो जाए ।

मुख्य मंत्री : जाने से पहले आप मेरा जवाब सुन लेना । (व्यवधान)

/26.03.2015यूके//1730एजी/2

श्री प्रेम कुमार धूमलः आपने सुना नहीं होगा, मैने तो शुरु में ही धन्यवाद से किया है । मैने धन्यवाद से शुरु किया है । आपने हजारों करोड़ रुपए मिल गए, उसका धन्यवाद नहीं किया, हमने तो लाखों वालों का भी धन्यवाद कर दिया है।

परिंदे को मंजिल जरूर मिलेगी पर आसमान में नहीं मिलेगी,
धरती पर ही मिलेगी । निश्चित तौर पर ।

मुख्य मंत्रीः सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा, हालांकि यह ट्रेडिशन नहीं है । Once the Budget Speech is given by the Finance Minister, the matter is put to vote. But this is a new tradition which has been created.

श्री प्रेम कुमार धूमलः यह होता रहा है ।

मुख्य मंत्रीः नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है । I have presented so many Budgets. I have also seen so many Budgets in the Centre.

Speaker: There is no discussion on this now.

Chief Minister: Speaker, Sir, Prof. Prem Kumar Dhumalji in nutshell has raised an issue that the fiscal health of the Government is in a very bad condition and Government has to withdraw money from the Developmental Blocks.

Speaker Sir, there are general guidelines that money should not be drawn from Treasuries and parked idle in the Bank Accounts for long. The Development Blocks had money, which was lying in Bank Accounts from a long time. The money, which was not required for immediate disbursement was to be kept in public ledger account (PLAs) of the concerned BDOs. BDOs are Administrative Officers of the PLAs and can withdraw money and spend the same at any time, when required. No

/26.03.2015यूके/1/730एजी/ 3

developmental work has suffered and will not be allowed to be suffered because of lack of funds.

Some other issues have also been raised. In fact I skipped the some part of my speech to shorten it, but I have said I put my entire speech on the Table of the House. Many of the points which have been raised are already covered in my speech. Thank you, Sir.

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक, शुक्रवार, दिनांक 27 मार्च, 2015 के 11.00 बजे पूर्वाहन् तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांकः 26 मार्च, 2015 **सचिव।**